विशेषांक

इंडिया टुडे

19 जनवरी, 2022 50 रुपए

उम्मीद और अंदेशे

विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ देश और दुनियाभर में भविष्य के रुझानों का ले रहे हैं जायजा

www.indiatodayhindi.in

RNI NO 45823/86 REGISTERED NO. DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22

अग्रिम सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित; एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित; कुल पन्नों की संख्या 62 (आवरण सहित)

OC

VISIT…

LANZAROTE

Caliente.com

LUPIN

LUPIN LIFE
BE ONE®

BE READY हर दिन आयुर्वेद की शक्ति के साथ

AYURVEDIC
100%
VEGETARIAN
LUPIN LIFE
BE ONE®
Be Ready Everyday
Re-energize • Rejuvenate • Revitalize
• BUILDS IMMUNITY •
Net contents: 10 Capsules
A QUALITY PRODUCT FROM LUPIN
100% AYURVEDIC
ASHWAGANDHA • SHILAJIT • SHATAVARI
SCIENTIFICALLY TESTED

Be One में है 8 नेचुरल एक्टिव्स की शक्ति, एडेप्टोजन फार्मूला के साथ. रोज़मर्रा की भागदौड़ में यह आपको एनर्जी देता है, इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है और आपको हर दिन एक्टिव रखता है. हेल्दी माइंड और बॉडी के लिए साइंटिफिकली टेस्ट किया गया, यह आपके लिए एक कम्प्लीट सप्लिमेंट है.

- एनर्जी दे*
- इम्यूनिटी बढ़ाये*
- शरीर और दिमाग को स्वस्थ बनाये*
- DRDO के साथ बनाया और टेस्ट किया गया#

अश्वगंधा

शतावरी

शिलाजीत

पीपली

आपके नजदीकी केमिस्ट स्टोर्स और लीडिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर उपलब्ध है.
A QUALITY PRODUCT FROM LUPIN | TOLL FREE : 1800 266 7440 | EMAIL : CUSTOMERCAREOTC@LUPIN.COM

---

*ऊपर लिखे सारे दावों के लिए फाइलों में डेटा उपलब्ध. #DRDO के DIPAS के साथ बनाया और परीक्षण किया गया। गोपीनाथन पीएम, ग्रोवर एसके, गुप्ता एके, श्रीवास्तव केके. लो- इंटेंसिटी-कन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस में कॉम्बेट प्रभावशीलता पर कॉम्पोजिट इंडियन हर्बल प्रिपरेशन के प्रभाव. Mil Med. 1999 Nov;164(11):814-9. PMID: 10578585

प्रधान संपादक की कलम से

हमने 2022 में तमाम आशंकाओं-अंदेशों के साथ कदम रखा है क्योंकि नया साल भी काफी कुछ बीते साल जैसा ही लग रहा है. कोविड-19 के मामले फिर बढ़ रहे हैं और नॉवेल कोरोनावायरस का खासा संक्रामक स्ट्रेन दुनिया भर में फैल रहा है. अच्छी बात यही है कि दो साल बाद कोविड कोई अबूझ बीमारी नहीं रह गया है. हम इस दैत्य के हाव-भाव से वाकिफ हैं और इसका बदतर हमला पिछले साल देख चुके हैं. इसके डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप देश भर में फैल गया था. संक्रमण की दूसरी लहर मेडिकल ऑक्सीजन की भारी किल्लत और ब्लैक फंगस के मामलों से जानलेवा हो गई, जिसमें देश में करीब 2,00,000 लोग जान गंवा बैठे. अब वैक्सीन के भरपूर भंडार और सरकार के बूस्टर डोज कार्यक्रम से हमारी तैयारी पुख्ता है. कोविड-19 दुनिया भर में 54 लाख लोगों की जान ले चुका है, जो 1918 में इन्फ्लूएंजा महामारी से हुई अनुमानित 5 करोड़ मौत का दसवां हिस्सा ही है, जिसे 'स्पैनिश फ्लू' भी कहा जाता है. उसका प्रकोप दो साल रहा था और उसके संक्रमण के चपेट में मानव आबादी का एक-तिहाई हिस्सा आया था.

कोविड का नया ओमिक्रॉन स्ट्रेन तमाम उपलब्ध सबूतों के आधार पर डेल्टा से कम घातक है. यह थोड़ी राहत की बात है. हालांकि हम अभी भी महामारी के दौर में हैं, पर काफी बेहतर हालात में लगते हैं. लेकिन इससे हम बेपरवाह कतई न हों. वायरस शायद ही उस तरह से बर्ताव करता है, जैसा हम चाहते हैं. एक अध्ययन से पता चलता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कोविड-19 की वजह से करीब 30 खरब डॉलर (223 लाख करोड़ रु.) गंवा सकती है. 2022 में अर्थव्यवस्था के 4.3 फीसद दर से बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले साल के 5.8 फीसद (2020 में −3.3 फीसद से उठकर) से थोड़ा कम है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का अनुमान है कि अनेक मौतों की वजह से वैश्विक जीडीपी में घाटा पांच साल में 53 खरब डॉलर (393 लाख करोड़ रु.) तक जा सकता है. भारत को अगर ज्यादा लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना है तो मजबूत आर्थिक वृद्धि बेहद जरूरी है.

2020 सुर्खियों के सरताज
इंडिया टुडे
कोविड-19
ध्वंस और उम्मीदें

13 जनवरी, 2021 का आवरण

विशेषांक
इंडिया टुडे
2021
W N S E
पुनर्निर्माण

20 जनवरी, 2021 का आवरण

महामारी की दशा-दिशा 2022 में दुनिया भर में आर्थिक बहाली तय करने में सबसे अहम होगी. इन चिंताओं के साथ ही भारत के लिए तीसरा संकट चीन से निबटना है. मई 2020 में दबंगई पर उतारू चीन ने तीन दशकों के शांति और सौहार्द के प्रोटोकाल को तोड़ दिया और पूर्वी लद्दाख की सीमा पर भारी सैनिक तैनात कर दिए, जिसमें दोनों पक्ष उलझे हुए हैं. सेहत, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की चिंताओं के अलावा 2022 में कई दूसरे मसले भी राजनैतिक प्रतिष्ठनों के दिमाग में हावी रहेंगे. इस साल हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाएंगे. इस साल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सात राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे. भाजपा इनमें छह राज्यों में सत्ता में है, जिसमें प्रधानमंत्री का गृह राज्य गुजरात भी है. इनमें सत्ता विरोधी रुझानों से निबटने की पार्टी की रणनीति पर करीबी नजर रहेगी.

हालांकि इस साल और आगे भी कई दीर्घकालिक चिंताएं हैं. हमारा विशेषांक '2022: उम्मीद और अंदेशे' इन चिंताओं पर अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों के पैनल के नजरिए से गौर करता है. इसका संयोजन एडिटर (फीचर) काइ फ्रीज ने किया है. मसलन, विषाणु वैज्ञानिक गगनदीप कंग का कहना है कि नीतिगत समर्थन के साथ विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य को अग्रिम मोर्चे पर लाने की जरूरत है, क्योंकि सार्स-कोव-2 के वेरिएंट की वैश्विक लहर का खतरा मिटने वाला नहीं है. चीन के जानकार एंड्र्यू स्मॉल बताते हैं कि मुश्किलें बढ़ाने की बीजिंग की भूख पहले से ज्यादा बढ़ी है और वह विभिन्न मोर्चों पर दुश्मनी के रिश्तों को ही अच्छा मानता है. पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन का मानना है कि 2022 अधिक अप्रत्याशित होगा. वे इस साल भारत से 'ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी' और विभिन्न आर्थिक समझौतों वाले ब्लॉक से रिश्ते मजबूत करने की उम्मीद करते हैं. इनमें रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) और एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जैसे ब्लॉक प्रमुख हैं.

अर्थशास्त्री जहांगीर अजीज अगले कुछ साल में नजर रखने के लिए पांच बड़े पैमानों का जिक्र करते हैं. ये पैमाने हैं: कोविड-19 का सामान्य बीमारी में तब्दील होना, भविष्य के ऊर्जा स्रोत पर सीओपी26 की प्रतिबद्धताओं का असर, चीन में बड़े नीतिगत बदलाव, कोविड महामारी से होने वाला स्थायी नुक्सान, और वैश्विक चुनावी परिदृश्य. पर्यावरणविद् सुनीता नारायण के मुताबिक, वक्त आ गया है कि भारत जलवायु परिवर्तन के टिकाऊ, किफायती और अधिक ऊर्जा सक्षम मॉडल की रूपरेखा तैयार करके प्रदूषण के बिना बढ़ोतरी का तरीका तलाशे. पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन और शोधकर्ता श्वेता सैनी का मानना है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को कृषि सुधारों के खात्मे की तरह नहीं देखा जाना चाहिए. टेक्नोलॉजिस्ट रोहन मूर्ति के लिए 2022 का बड़ा मुद्दा लोगों के काम में ज्यादा सहूलियत की खातिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा.

भाजपा का मूल वैचारिक संगठन आरएसएस 2025 में अपने गठन की सौवीं वर्षगांठ मनाएगा. आरएसएस के विचारक राम माधव के मुताबिक, संगठन की चुनौती अपने गर्व और गुस्से में संतुलन कायम करना होगा और पक्का करना होगा कि कोई एक-दूसरे पर हावी न हो. लेखक तथा तृणमूल कांग्रेस नेता पवन वर्मा की दलील है कि 'हिंदुत्व' का मकसद हिंदू धर्म के समावेशी और सामंजस्य के भाव को बदलना है. ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर (पब्लिशिंग) राज चेंगप्पा मोदी सरकार को आर्थिक सुधारों पर आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर देते हैं. वरिष्ठ वकील अरविंद पी. दातार का कहना है कि भारत पश्चिमी लोकतंत्रों की बराबरी करने की ख्वाहिश रखता है तो उसे अदालतों और न्यायाधिकरणों की संस्थागत आजादी को मजबूत करना चाहिए. वैश्वीकरण विशेषज्ञ पराग खन्ना के मुताबिक, प्रवासी भारतीय दुनिया को नया आकार दे रहे हैं. आखिर में खेल पत्रकार शारदा उगरा की भविष्यवाणी है कि नए साल में सभी खेलों में भारतीय एथलीटों का उभार दिखेगा.

वाकई यह बेहतरीन लेखकों का नक्षत्रमंडल है और अगर आप देश और दुनिया की दिख रही या दिखने वाली दिशा जानने की ख्वाहिश रखते हैं, तो इस विशेषांक को जरूर पढ़िए और आनंद उठाइए. ■

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे
www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादकः अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सनः कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरः दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टरः राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरः मनोज शर्मा
एडिटरः सौरभ द्विवेदी
सीनियर डिप्टी एडिटरः दयाशंकर शुक्ल सागर
सीनियर एडिटरः मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटरः शिवकेश मिश्र, आशीष मिश्र (लखनऊ)
असिस्टेंट एडिटरः मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरोः पुष्यमित्र (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटरः नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टरः चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टरः असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटरः बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंटः यासिर इकबाल, राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चरः प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चरः सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफः अभिनव पुगला
एसोसिएट पब्लिशरः विद्या मेनन (इंपैक्ट)
इंपैक्ट टीम
नेशनल हेडः सुपर्णा कुमार (गवर्नमेंट ऐंड पीएसयू)
सीनियर जनरल मैनेजरः जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजरः मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरू)
डिप्टी जनरल मैनेजरः इंद्रनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसरः विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजरः दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजरः विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजरः राजीव गांधी (नॉर्थ)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजरः योगेश गोधनलाल गौतम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजरः एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजरः पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

वर्षः 36; अंकः 7; 13-19 जनवरी, 2022; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित,

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालयः** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोनः 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवाः** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोनः दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्सः (0120) 4078080. ई-मेलः wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालयः** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालयः** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोनः 022-66063355 फैक्सः 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालयः** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोनः 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोनः 2212448, 226233, टेलेक्सः 0845-2217 INTO IN. फैक्सः 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालयः एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.

- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित.**

संपादकः राज चेंगप्पा

भीतर

सुर्खियां

रिलायंस इंडस्ट्रीजः पीढ़ीगत छलांग
पेज 5

फुरसत

अमर देसवाः विपदा केवल उस्मानाबाद की न थी
पेज 58

सवाल-जवाब/देवदत्त पटनायकः “हम सब अब नोआ हैं”
पेज 60

25

आवरण कथा

उम्मीद की डोर

विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि देश और दुनिया में आगे का परिदृश्य कैसा होगा

26 **हुकूमत**
राज चेंगप्पा

30 **कोविड-19**
गगनदीप कंग

33 **हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व**
पवन के. वर्मा

36 **हिंदुत्व**
राम माधव

38 **वैश्विक अर्थव्यवस्था**
जहांगीर अज़ीज़

40 **भारतीय अर्थव्यवस्था**
नीलकंठ मिश्र

42 **डिजिटल वर्क**
रोहन मूर्ति

44 **भू-राजनीतिक परिदृश्य**
श्याम सरन

46 **चीन और भारत**
एंड्रयू स्माल

48 **जलवायु परिवर्तन**
सुनीता नारायण

50 **कृषि कानूनों के बाद कृषि**
सिराज हुसैन और श्वेता सैनी

52 **न्यायपालिका**
अरविंद पी. दातार

54 **प्रवास**
पराग खन्ना

56 **खेल**
शारदा उगरा

बसपा

12 **सिमटता दायरा**

उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव बसपा के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है.

बिहार

22 **ऑक्सीजन के भरोसे**

बिहार के अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी.

इंडिया टुडे

इंडिया टुडे मैगजीन मिलने में दिक्कत हो रही है?
✆ 7303086006 पर नाम पता या ‘हेलो’ संदेश भेजें.
या मेल करें: wecare@intoday.com ✉
हम आपसे संपर्क कर लेंगे.

आवरणः **नीलांजन दास**

पाठकों के लिए सूचनाः कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में ‘इम्पैक्ट फीचर’ या ‘एडवरटोरियल’ या ‘फोकस’ के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

उत्तर प्रदेशः चुनाव लड़कर बनाएंगे माहौल पेज 8

एफसीआरएः विदेशी पैसों का टोटा पेज 10

पीटीआइ

उत्तराधिकार
अंबानी परिवार की नई पीढ़ी मोर्चा संभाल चुकी है

रिलायंस इंडस्ट्रीज

पीढ़ीगत छलांग

एम.जी. अरुण

हाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआइएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा था कि कंपनी में नेतृत्व परिवर्तन का वक्त आ चुका है. यह 2020-21 में 5.39 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व वाली निजी क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है. 64 वर्षीय अंबानी 1981 से आरआइएल के साथ हैं, जब उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने उन्हें महाराष्ट्र के पातालगंगा में पेट्रोकेमिकल्स प्लांट बनाने में मदद करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रोग्राम से बीच में ही बुला लिया था. तब मुकेश महज 24 साल के थे. दो दशक बाद, उन्होंने 2002 में धीरूभाई के निधन के बाद आरआइएल की बागडोर संभाली.

पिछले कुछ वर्षों से, अंबानी अपने तीन बच्चों—30 साल के जुड़वां ईशा और आकाश तथा 26 वर्षीय अनंत को कंपनी में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार कर रहे हैं. लेकिन उन्होंने परिवार के बाहर भी भविष्य के अगुआ तैयार करने का ढांचा तैयार किया है, जिन्हें उचित समय पर नेतृत्व वाले पदों पर लाया जाएगा. धीरूभाई के जन्मदिन पर आयोजित सालाना समारोह रिलायंस फैमिली डे (28 दिसंबर) पर अंबानी ने कहा, ''रिलायंस ऐतिहासिक नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया में है—इसमें मेरी पीढ़ी के वरिष्ठों की जगह युवा नेतृत्व लेने वाला है.'' यह साफ था कि वह चाहते हैं कि उनके बच्चे आरआइएल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठ जाएं और इसमें उन्हें पेशेवर और परिवार के वफादारों का

बेहतरी के लिए बदलाव

आरआइएल बोर्ड

मुकेश अंबानी,
64 वर्ष
चेयरमैन और एमडी

कार्यकारी निदेशक

निखिल आर. मेसवानी
हितल आर. मेसवानी
पी.एम.एस. प्रसाद
पवन कुमार कपिल

गैर-कार्यकारी निदेशक

नीता अंबानी
दीपक सी. जैन
आर.ए. माशेलकर
आदिल जैनुलभाई
आर.एस. गुजराल
सुमीत बनर्जी
अरुंधति भट्टाचार्य
के.वी. चौधरी
यासिर ओ. अल-रुमायन

अंबानी परिवार के उत्तराधिकारी

आकाश अंबानी, 30 वर्ष
निदेशक, रिलायंस जिओ इंफोकॉम और रिलायंस रिटेल वेंचर्स

ईशा अंबानी, 30 वर्ष
निदेशक, रिलायंस जिओ इंफोकॉम और रिलायंस रिटेल वेंचर्स

अनंत अंबानी,
26 वर्ष
निदेशक, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर

अन्य कारोबारों के हेड/लीडर

50-65 वर्ष आयु समूह के उद्योग जगत के दिग्गज

डिजिटल सर्विसेज

संजय माशरुवाला और मैथ्यू ओमन
प्रेसिडेंट, रिलायंस जिओ

पंकज पवार
बिजनेस हेड, जिओ

तेल से लेकर रसायन

पी.के. कपिल
कार्यकारी निदेशक

संजीव सिंह
ग्रुप प्रेसिडेंट

श्रीनिवास तुट्टागुंटा
निदेशक

रिटेल

सुब्रमण्यम वी.
एमडी, रिलायंस रिटेल

अखिलेश प्रसाद
सीईओ, रिलांयस ट्रेंड्स

दर्शन मेहता
सीईओ, रिलायंस ब्रान्ड्स

ब्रायन बेड
सीईओ, रिलायंस रिटेल

दामोदर मल्ल
प्रेसिडेंट और सीईओ, फूड व ग्रोसरी रिटेल

फाइनेंस

आलोक अग्रवाल
ग्रुप सीएफओ

श्रीकांत वेंकटाचारी
ग्रुप जॉइंट सीएफओ

भविष्य के कुछ लीडर

बड़ी भूमिका के लिए तैयार हो रहे 35-50 वर्ष आयु समूह वाले अफसर

अंशुमान ठाकुर
हेड ऑफ स्ट्रेटजी, रिलायंस जिओ

कौशल नेवरेकर
चीफ बिजनेस ऑफिसर, रिलायंस डिजिटल

सौरभ संचेती
सीएफओ, जिओ प्लेटफॉर्म्स

राज मुलिक
चीफ एकाउंट ऑफिसर, आरआइएल

अश्विन खासगीवाला
सीएफओ, रिलायंस रिटेल

किरण थॉमस
प्रेसिडेंट, जिओ

संजय रॉय
हेड, डीपवाटर ऑयल ऐंड गैसफील्ड एसेट्स

आशीष लोढा और आयुष भटनागर
सीनियर वाइस प्रेसीडेंट, जिओ प्लेटफॉर्म्स

आर. श्रीनिवासन
प्रेसिडेंट-रेवेन्यू व कमर्शियल ऑपरेशन्स, जिओ

सौम्य दत्ता
हेड ऑफ ट्रेजरी

सहयोग मिले. उन्होंने कहा, ''मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि अगली पीढ़ी के अगुआ के तौर पर आकाश, ईशा और अनंत रिलायंस को और अधिक ऊंचाई पर ले जाएंगे.''

अंबानी शायद अपने बच्चों को कारोबार के गुर सीखने के लिए अधिक समय देना चाहते थे. लेकिन बाजार नियामक सेबी की तय की गई समय सीमा आन पड़ी थी, जिसके तहत कंपनियों को अपने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों के पदों को अप्रैल, 2022 तक अलग करना था ताकि अधिक पारदर्शिता और जिम्मेवारी लाई जा सके. अभी तक यह साफ नहीं है कि नेतृत्व के पदों का बंटवारा कैसे होगा, पर आरआइएल के सूत्र बताते हैं कि अंबानी, इस नेतृत्व परिवर्तन के बाद रिलायंस फाउंडेशन के काम पर ध्यान देंगे.

जब अंबानी ने सीएमडी के रूप में पदभार संभाला था तो आरआइएल का सकल टर्नओवर 65,061 करोड़ रुपए और शुद्ध लाभ 4,104 करोड़ रुपए था. तब से बहुत कुछ बदल गया है. बीते वर्षों में आरआइएल कारोबार में तीन बड़ी विविधता लेकर आया—तेल और गैस, खुदरा और सबसे हाल में टेलिकॉम. मोटे तौर पर पेट्रोरसायन और बाद में तेल और गैस पर निर्भर रहने वाले औद्योगिक दिग्गज से आरआइएल ने उपभोक्ता-आधारित कारोबारों पर ध्यान दिया, मसलन खुदरा और टेलिकॉम और इसकी वजह से इसके राजस्व में आठ गुणा वृद्धि हुई और 2020-21 में इसका शुद्ध लाभ 53,739 करोड़ रुपए हो गया.

29 दिसंबर, 2021 तक आरआइएल का बाजार पूंजीकरण 16.25 लाख करोड़ रुपए था, जो भारतीय कंपनियों में सबसे अधिक था. इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद के प्रोफेसर कविल रामचंद्रन कहते हैं, ''आरआइएल में ढांचागत और व्यवस्थित उत्तराधिकार के लिहाज से मुकेश अंबानी सही कदम उठा रहे हैं. हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है. आप अपने हितधारकों के प्रति जिम्मेवार हैं, अपने परिवार या शेयरधारकों के प्रति नहीं.'' वह यह भी कहते हैं कि अंबानी के वारिसों को अपना पद खुद कमाना चाहिए.

अंबानी की नई पीढ़ी, समूह के नए जमाने के कारोबारों के लिहाज से तैयार की गई है—खुदरा, डिजिटल, टेलिकॉम और स्वच्छ ऊर्जा. आकाश और ईशा रिलायंस जिओ इन्फोकॉम और रिलायंस रिटेल वेंचर्स में निदेशक के तौर पर 24 साल की उम्र में शामिल हो चुके हैं. ईशा ने येल विश्वविद्यालय से 2013 में मनोविज्ञान और दक्षिण एशियाई अध्ययन में स्नातक की उपाधि ली है और

विशाल संरचना
गुजरात के जामनगर में आरआइएल की रिफाइनरी

एएफपी

उनका कुछ समय अमेरिका में मॅकिन्से में भी गुजरा है. वहीं, ब्राउन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक आकाश ने आरआइएल के 4जी टेलिकॉम वेंचर के साथ नजदीकी से काम किया है और उसके बाद ही वह समूह के फर्मों में निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं. आकाश और ईशा आरआइएल के डिजिटल जिओ प्लेटफॉर्म्स के उस डील में मुख्य सौदेबाज थे जिससे यह गूगल, फेसबुक और इंटेल के साथ आया और इसने समूह को भविष्योन्मुखी उद्यम में बदल दिया. ये दोनों डेन नेटवर्क्स, हाथवे केबल और डेटाकॉम समेत जिओ प्लेटफॉर्म्स के सभी बड़े अधिग्रहणों में शामिल थे.

रिलायंस जिओ में, आकाश उत्पादों और डिजिटल सेवाओं के ऐप्लिकेशन्स के विकास में शामिल हैं. वह खेल कारोबार भी संभालते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग की टीम मुंबई इंडियंस चलाते हैं. ईशा कंज्यूमर एक्सपीरियंस, ब्रान्डिंग–मार्केटिंग देखती हैं और रिलायंस फाउंडेशन में नीता अंबानी की मदद करती हैं.

अनंत ब्राउन यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं और रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड के बोर्ड में हैं. वह ऊर्जा व्यवसाय का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और जामनगर रिफाइनरी परिसर से जुड़े रहे हैं. आरआइएल के तेल से लेकर रसायन कारोबार का राजस्व महामारी की वजह से मूल्य में कमी आने के कारण 2020–21 में 29 फीसद घटकर 3.2 लाख करोड़ रुपए हो गया. वहीं, डिजिटल सेवाओं ने राजस्व में 90,287 करोड़ रुपए जोड़े, जो 2019–20 में 69,605 करोड़ रुपए से काफी अधिक है.

आरआइएल अंबानी परिवार के बाहर भी नेतृत्व तैयार कर रहा है. मुकेश अंबानी की अध्यक्षता वाले आरआइएल बोर्ड में चार कार्यकारी निदेशक हैं—निखिल आर मेसवानी, हिताल आर मेसवानी, पी.एम.एस. प्रसाद और पवन कुमार कपिल. नीता अंबानी, अरुंधति भट्टाचार्य, के.वी. चौधरी, यासिर ओ. अल–रुमायन, दीपक सी. जैन, आर.ए. माशेलकर, आदिल जैनुलभाई, आर.एस. गुजराल और शुमीत बनर्जी नौ गैर–कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशक हैं.

अंबानी परिवार की नई पीढ़ी के सदस्यों को समूह के नए जमाने के कारोबारों के लिहाज से तैयार किए गया है—खुदरा, डिजिटल, टेलिकॉम और स्वच्छ ऊर्जा. आरआइएल अंबानी परिवार के बाहर भी लीडरशिप आधार तैयार कर रहा है.

विभिन्न विभागों या कारोबारों के प्रमुख का काम संभाल रहे अन्य वरिष्ठ पेशेवर अनुभवी और युवा दोनों हैं. उद्योग के 50–65 आयु वर्ग के दिग्गज इसमें शामिल हैं. मसलन, समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी आलोक अग्रवाल; रिलायंस रिटेल के एमडी सुब्रमण्यम वी., रिलायंस जियो के दोनों अध्यक्ष संजय मशरूवाला और मैथ्यू ओमन तथा जिओ के बिजनेस हेड पंकज पवार. तेल से लेकर रसायन के कारोबार में कार्यकारी निदेशक के रूप में पी.के. कपिल मौजूद हैं, तो समूह अध्यक्ष के रूप में संजीव सिंह और निदेशक के रूप में श्रीनिवास तुट्टागुंटा काम संभाल रहे हैं.

इन व्यवसायों में 35–50 आयु वर्ग के नेतृत्व की एक कड़ी है, जिन्हें बड़ी भूमिकाओं के लिए तैयार किया जा रहा है. मसलन, रिलायंस जियो के हेड ऑफ स्ट्रेटेजी अंशुमान ठाकुर, रिलायंस डिजिटल के मुख्य व्यवसाय अधिकारी कौशल नेवरेकर, जियो प्लेटफॉर्म्स के सीएफओ सौरभ संचेती, आरआइएल के मुख्य लेखा अधिकारी राज मलिक; रिलायंस रिटेल के सीएफओ अश्विन खासगीवाला, जियो के अध्यक्ष किरण थॉमस, जियो प्लेटफॉर्म्स के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट आशीष लोढ़ा और आयुष भटनागर, जियो के राजस्व और वाणिज्यिक संचालन के अध्यक्ष आर. श्रीनिवासन, ट्रेजरी के प्रमुख सौम्य दत्ता और डीपवाटर ऑयल ऐंड गैसफील्ड्स एसेट्स के प्रमुख संजय रॉय.

आइएसबी के रामचंद्रन कहते हैं कि भले ही अंबानी के वारिस पूरी तरह से तैयार न हों, पर वे इस अनुभवी टीम पर भरोसा कर सकते हैं. आरआइएल ने कई ग्रूमिंग प्रोग्राम चलाए हैं. इसका करियर एक्सेलेरेशन प्रोग्राम और स्टेप–अप का मकसद अगुआ लोगों की जल्दी पहचान करना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है. वहीं, प्रबंधक बहु–कार्यात्मक प्रशिक्षण लेते हैं. केवल 30–35 आयु वर्ग के लोगों को लीडरशिप प्रोग्राम में शामिल होने की अनुमति है. विभिन्न भूमिकाओं में अनुभव हासिल करने में मदद करने के लिए अधिकारियों के पास सलाहकार होते हैं. ■

मोर्चे पर
एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

पीटीआइ

उत्तर प्रदेश

चुनाव लड़कर बनाएंगे माहौल

साल 2022 में रणनीति के तहत वरिष्ठ मंत्रियों समेत खुद मुख्यमंत्री योगी के चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा में चल रहा मंथन. अयोध्या और मथुरा पर भी योगी की नजर

आशीष मिश्र

पहली जनवरी को नववर्ष के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार की तरह इस बार भी शाम के वक्त लखनऊ के 5 कालीदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से अनौपचारिक मुलाकात कर रहे थे. कुछ ही देर में यह मुलाकात इस वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश (यूपी) विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी चर्चा में तब्दील हो गई. यह पूछे जाने पर कि “क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे?” योगी आदित्यनाथ का चेहरा खिल जाता है. वह मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, “हां, मैं विधानसभा चुनाव अवश्य लड़ूंगा. पर कहां से लड़ूंगा, इसका फैसला पार्टी करेगी.” इससे पहले भी 6 नवंबर को गोरखपुर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में योगी साल 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं.

साल 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने संबंधी योगी के बयान के बाद से राजनीतिक हल्कों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. इन अटकलों को हवा देते हुए अयोध्या सदर सीट से भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता कहते हैं, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ें तो यह रामलला की नगरी का सौभाग्य होगा.” अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी की सक्रियता भी कुछ संकेत दे रही है. मार्च 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ 33 बार अयोध्या आ चुके हैं. मार्च 2017 से नवंबर, 2019 तक योगी 12 बार अयोध्या आए थे. 9 नवंबर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद योगी 21 बार अयोध्या आ चुके हैं. इस दौरान 6 मौकों पर योगी अयोध्या में सर्किट हाउस में न रुककर रामजन्म भूमि के अपेक्षाकृत समीप पर्यटन विभाग के होटल साकेत में ठहरे थे. अयोध्या के साकेत कालेज के पूर्व प्राचार्य वी.एन.अरोड़ा बताते हैं, “मुख्यमंत्री योगी को अयोध्या से विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाकर भाजपा कुछ उसी तरह की रणनीति बना सकती है जैसा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को वाराणसी से उम्मीदवार बनाकर बनाई गई

थी. योगी आदित्यनाथ के उम्मीदवार बनते ही अयोध्या विधानसभा सीट हाइप्रोफाइल हो जाएगी. इस वजह से यहां हो रहा राममंदिर का निर्माण न केवल सुर्खियों में आ जाएगा बल्कि यह चुनावी मुद्दा भी बन जाएगा.'' योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने का असर जिले की पांच विधानसभा सीटों पर पड़ेगा. साल 1991 और 2017 में जब भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है तब पार्टी ने अयोध्या की सभी विधानसभा सीटें भी जीती हैं.

अयोध्या ही नहीं कृष्ण नगरी मथुरा से भी योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाने की मांग जोर पकड़ रही है. भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा को पत्र लिखकर योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने की मांग की है. नड्डा को भेजे गए पत्र में यादव ने लिखा है, ''मेरे सपने में भगवान श्रीकृष्ण आए थे, उन्होंने कहा कि योगी से कहो कि वो मेरी जन्मभूमि से चुनाव लड़ें.'' इससे पहले मथुरा से भाजपा सांसद हेमामालिनी ने भी 22 दिसंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था, ''मैं चाहती हूं कि योगी आदित्यनाथ हमारे मथुरा से चुनाव लड़ें. अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है तो अब मथुरा में भी कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए.''

मार्च, 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने मथुरा पर खास ध्यान दिया. योगी ने अगर अयोध्या में दीपावली पर दीपोत्सव की शुरुआत की तो होली के मौके पर ब्रज में जाकर साधुओं के साथ रंग खेला. यूपी में भाजपा सरकार बनने के चार महीने के भीतर 11 जुलाई, 2017 को योगी कैबिनेट ने श्रीकृष्ण की जन्मस्थली के आध्यात्मिक स्वरूप को संरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले 'ब्रज तीर्थ विकास परिषद' के गठन का प्रस्ताव पारित किया था. परिषद का उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी शैलजाकांत मिश्र को बनाया गया था. यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी नियमित तौर पर मथुरा जाते रहे हैं. पिछले 19 दिसंबर को योगी ने मथुरा पहुंचकर भाजपा की जनविश्वास यात्रा का शुभारंभ किया था. यह पिछले 56 महीनों में योगी का 19वां मथुरा दौरा था.

लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष एस.के. द्विवेदी कहते हैं, ''योगी ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करके विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश की है. चुनाव लड़कर योगी यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त है और इसके लिए वह जनता के बीच जाने में गुरेज नहीं कर रहे.'' बीते तीन दशक में मुलायम सिंह और कल्याण सिंह के बाद योगी तीसरे सत्तासीन नेता होंगे जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे. एस.के. द्विवेदी बताते हैं, ''योगी ने कभी 'बैकडोर' की राजनीति नहीं की. वह गोरखपुर से साल 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचते रहे हैं. विधान परिषद सदस्य होना उनके मिजाज से मेल नहीं खाता है.'' साल 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी की लोकप्रियता का भरपूर लाभ लेने के लिए भाजपा नेताओं का एक खेमा इन्हें पश्चिमी यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ने की वकालत कर रहा है.

वहीं, योगी के विधानसभा चुनाव लड़ने के मसले पर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं, ''सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वह हारने जा रहे हैं.'' भाजपा के भीतर योगी ही नहीं वरिष्ठ मंत्रियों को भी चुनाव मैदान में उतारने पर मंथन चल रहा है. इनमें ज्यादातर वे लोग हैं जो विधान परिषद सदस्य हैं और जल्द ही उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है. (देखें बॉक्स) हालांकि पार्टी आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रही है. यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं, ''भाजपा में चुनाव संबंधी सारे निर्णय संसदीय बोर्ड लेता है. संसदीय बोर्ड की अभी कोई बैठक भी नहीं हुई है. ऐसे में कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं, इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है.'' ■

विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाएंगे ये दिग्गज

केशव प्रसाद मौर्य (52 वर्ष)– योगी सरकार में उपमुख्यमंत्री. सितंबर, 2017 में विधान परिषद सदस्य बने, जिसका कार्यकाल 6 जुलाई, 2022 तक है. 2012 में कौशांबी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने. 2014 में फूलपुर से सांसद बने.

संभावना–वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रयागराज जिले की सीट या सिराथू से चुनाव लड़ सकते हैं.

दिनेश शर्मा (57 वर्ष)– उपमुख्यमंत्री हैं. आगरा जिले के प्रभारी मंत्री. वर्तमान में यूपी विधान परिषद के नेता सदन. दो बार लखनऊ के मेयर का चुनाव जीत चुके हैं. जनवरी, 2021 में दूसरी बार विधान परिषद सदस्य चुने गए. बतौर सदस्य इनका कार्यकाल 31 जनवरी, 2027 तक है.

संभावना–लखनऊ जिले की किसी शहरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं.

महेंद्र कुमार सिंह (54 वर्ष)–राज्य में जलशक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं. 22 अगस्त, 2019 से पहले राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) थे. 2012 में पहली बार विधान परिषद सदस्य बने. मई, 2018 में दूसरी बार विधान परिषद सदस्य बने, जिसका कार्यकाल 5 मई 2024 तक है.

संभावना–प्रतापगढ़ या लखनऊ की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं.

चौधरी भूपेंद्र सिंह (54 वर्ष)– पंचायतीराज विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं. 2016 में विधान परिषद सदस्य बने. बतौर सदस्य इनका कार्यकाल 6 जुलाई, 2022 तक है. 1999 के लोकसभा चुनाव में संभल सीट से मुलायम सिंह यादव से चुनाव हारे थे.

संभावना–2022 के विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद या पश्चिम यूपी की किसी जाट बाहुल्य सीट से लड़ सकते हैं.

अशोक कटारिया (49 वर्ष)– परिवहन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार). 6 मई, 2018 को विधान परिषद के सदस्य बने, जिसका कार्यकल 5 मई, 2024 तक है. पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री का दायित्व संभाल चुके हैं. गुर्जर समाज में पकड़.

संभावना–बिजनौर या नोएडा जिले की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं.

मोहसिन रजा (53 वर्ष)– अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज विभाग के राज्यमंत्री. 6 मई, 2018 में दूसरी बार विधान परिषद सदस्य जिसका कार्यकाल 5 मई 2024 तक है.

संभावना–लखनऊ में शिया बाहुल्य विधानसभा सीट या अमेठी जिले की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं.

एफसीआरए

विदेशी पैसों का टोटा

कौशिक डेका

भारत में **16,908** संगठन एफसीआरए के तहत विदेशी धन हासिल करने के लिए अधिकृत हैं. ये पिछले साल से कम हैं. पिछले साल इनकी संख्या **22,797** थी

साल 2011 और 2021 के बीच, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), 2010 का कथित उल्लंघन करने पर **20,586** संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए; 89 संगठनों के पंजीकरण अनुरोध पर रद्द किए गए हैं

इनमें से **80** फीसद साल 2014 और 2021 के बीच एनडीए सरकार के राज में रद्द किए गए

एक जनवरी, 2022 को जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5,968 फर्मों के एफसीआरए (विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम) पंजीकरण को रद्द कर दिया तो कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की. किसी संस्था को विदेशी फंडिंग हासिल करने और उनका उपयोग करने के लिए यह पंजीकरण अनिवार्य है. आलोचकों ने कहा कि इस कदम का मकसद उन एनजीओ (गैर-सरकारी संगठनों) को पंगु बनाना है जो भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते रहे हैं या फिर अल्पसंख्यकों की ओर से चलाए जा रहे हैं. जिन संस्थाओं का पंजीकरण खत्म किया गया है उनमें नोबल विजेता मदर टेरेसा की ओर से स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन इस्लामिक सेंटर, ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट और कॉमन कॉज शामिल हैं. इन्होंने हाल के समय में कई केंद्रीय कानूनों के खिलाफ कई जनहित याचिकाएं दाखिल की थीं.

हालांकि, एफसीआरए पंजीकरण खो चुके कुछ लोगों सहित स्वतंत्र पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह 2020 में एफसीआरए में हुए संशोधन का नतीजा है. उस संशोधन ने एफसीआरए पंजीकरण प्रक्रिया को बोझिल, अपारदर्शी और सरकार के विवेक पर निर्भर बना दिया है. आंध्र प्रदेश में शेयर ऐंड केयर फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एफसीआरए, 2020 की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. फाउंडेशन के नोएल हार्पर कहते हैं, ''नए नियमों से अब एनजीओ का काम करना बहुत मुश्किल हो गया है. नए नियम उन लोगों के लिए भी दंडात्मक हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं.'' एफसीआरए की सूची में से हटाए गए 5,968 संस्थाओं में से 5,789 ने 31 दिसंबर की समयसीमा के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया. (एफसीआरए पंजीकरण पांच साल के लिए वैध होता है और उसके बाद उसका नवीकरण किया जाना जरूरी होता है). असल में, 29 सितंबर, 2020 और 13 दिसंबर, 2021 के बीच 18,778 संगठन लाइसेंस के नवीकरण के योग्य थे—इनमें से केवल 12,989 ने नवीकरण के लिए आवेदन दाखिल किया. कुछ संस्थानों ने आवेदन नहीं किया, जिनमें दो आइआइटी (दिल्ली और कानपुर), नेहरू मेमोरियल म्यूजियम ऐंड लाइब्रेरी और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स भी शामिल हैं.

बहरहाल, आलोचक इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी और ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट सहित कुछ पंजीकरण रद्द कर दिए गए थे, और वे खत्म नहीं हुए थे. 25 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 'प्रतिकूल इनपुट' का हवाला देते हुए मिशनरीज ऑफ चैरिटी के पंजीकरण का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया. पंजीकरण के लिए नया आवेदन तीन साल बाद ही किया जा सकता है. 12 दिसंबर को, वडोदरा पुलिस ने, एक जिला समाज कल्याण अधिकारी की शिकायत के आधार पर, कोलकाता स्थित इस एनजीओ के वडोदरा के एक आश्रय गृह के खिलाफ गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ''हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने'' और ''युवा लड़कियों को ईसाइयत की ओर आकर्षित करने'' के आरोप में मामला दर्ज किया था. अगस्त में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने दावा किया कि वडोदरा के उस आश्रय गृह के दौरे में उन्हें धर्मांतरण के सुबूत मिले थे. फरवरी 2020 में, एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था और इसमें झारखंड में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के शेल्टर होम की बाल तस्करी में कथित संलिप्तता की जांच की मांग की गई थी. बहरहाल, इन आरोपों को कानून के उल्लंघन श्रेणी में नहीं रखा जाता है और इस मामले में, कानून कहता है कि एफसीआरए पंजीकरण केवल उन लोगों के लिए अस्वीकार किया जा सकता है जिन पर जबरन धर्मांतरण के लिए मुकदमा चलाया गया है या उन्हें दोषी ठहराया गया है.

इलस्ट्रेशनः सिद्धांत जुमडे

एफसीआरए को पहली बार 1976 में विदेशी फंडिंग की प्राप्ति और उपयोग को निगरानी के लिए लागू किया गया था. 2010 में, केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसे निरस्त कर दिया और एक नया कानून पारित किया. फिर, 2020 में, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विदेशी फंडिंग के उपयोग पर नियंत्रण सख्त करने के लिए इस अधिनियम में और संशोधन किए. मसलन, अब विदेशी फंडिंग के केवल 20 फीसद (पहले के 50 फीसद से कम) का उपयोग प्रशासनिक खर्चों के लिए किया जा सकता है. अगर सरकार, किसी जांच के आधार पर, यह मानती है कि कोई संगठन एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, तो वह इसे विदेशी फंडिंग हासिल करने या उसका इस्तेमाल करने से रोक सकती है, भले ही वह संगठन दोषी नहीं पाया जाए. नए नियम एनजीओ पर विदेशी फंड की रकम को किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को ट्रांसफर करने पर भी रोक लगाते हैं. आलोचकों का कहना है कि इस नियम से दूरदराज के इलाकों में काम करने वाले छोटे एनजीओ पर बुरा असर पड़ा है जिनकी विदेशी फंड तक पहुंच नहीं है, और इससे इनके बड़े एनजीओ से फंड मिलने पर रोक लग गई है.

तेलंगाना में नेशनल वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट के जोसेफ लिजी और एनम्मा जाओचिम के साथ हार्पर ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि एफसीआरए में 2020 के संशोधन ने एनजीओ के कामकाम में विदेशी फंड के इस्तेमाल पर बुरी तरह से बंदिश लगा दी है. हार्पर कहते हैं, “सरकार को नियमों को आसान बनाना चाहिए. वरना स्वाभाविक है कि लोग शक करेंगे कि इन नियमों के पीछे जरूर कोई और बात है.” केंद्र ने कहा है कि विदेशी धन का उपयोग उनके बताए गए उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, न कि देश को नुक्सान पहुंचाने वाले अन्य मकसदों के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधनों की जरूरत थी. मसलन, सरकार का दावा है कि विकास कार्यों के लिए मिले धन को अक्सर माओवादियों को प्रशिक्षित करने में इस्तेमाल कर लिया जाता है.

विदेश फंड का लेखा-जोखा

2015-16 से सालाना विदेशी योगदान में मामूली गिरावट के बावजूद, साल 2014 और 2020 के दौरान हासिल कुल विदेशी फंडिंग में 2009-2014 के बीच प्राप्त राशि के मुकाबले 39 फीसद की वृद्धि हुई है

एनजीओ को प्राप्त कुछ विदेशी योगदान

(करोड़ रु. में)

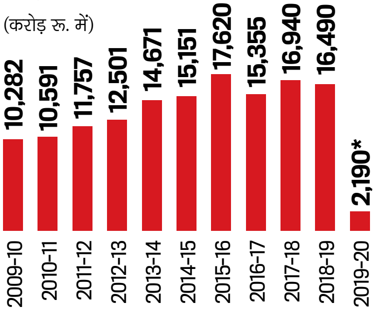

*स्रोतः अशोक यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट ऐंड फिलेनथ्रोपी की एस्टिमेटिंग फिलेनथ्रॉपिक केपिटल इन इंडिया, 2019 और 24 मार्च, 2021 तक प्राप्त लोकसभा डेटा *16 मार्च, 2021 तक का, एनजीओ की ओर से दाखिल सालाना रिटर्न्स के आधार पर*

इन संशोधनों के समर्थन में एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कुछ गैर-सरकारी संगठनों का जिक्र किया गया है, जहां फंड को कथित तौर कहीं और भेजा गया या या संदिग्ध स्रोतों से प्राप्त किया गया. अभी शीर्ष अदालत ने अपना फैसला नहीं सुनाया है. एफसीआरए पंजीकरण रद्द करने को लेकर कई कानूनी चुनौतियां हैं—2016 में, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर की ओर से संचालित गैर-सरकारी संगठन लॉयर्स कलेक्टिव का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था. सरकार ने दावा किया था कि संगठन ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विदेशी धन का इस्तेमाल किया. सरकार ने यह भी कहा कि जयसिंह ने विदेशी धन प्राप्त करके एफसीआरए मानदंडों का उल्लंघन किया था, क्योंकि एफसीआरए के तहत एक सरकारी अधिकारी ऐसा नहीं कर सकता.

2014 में सत्ता में आने के बाद से, कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों की आवाज दबाने के लिए एफसीआरए का इस्तेमाल करने के आरोप में वैश्विक स्तर पर मोदी सरकार की आलोचना होती है. खासकर ग्रीनपीस और ऐमनेस्टी इंटरनेशनल के एफसीआरए पंजीकरण को रद्द किए जाने के बाद. सितंबर 2020 में, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने आरोप लगाया था कि अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से केंद्र ने उसके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया. बैंक खातों के बंद होने के बाद, संगठन ने भारत में अपना कार्यालय बंद कर दिया.

वहीं, केंद्र की एनडीए सरकार ने ध्यान दिलाया कि ऐमनेस्टी इंटरनेशनल का एफसीआरए पंजीकरण 2010 में यूपीए सरकार ने रद्द कर दिया था और इसे कभी नवीनीकृत नहीं किया गया. असल में, एफसीआरए का प्राथमिक मकसद गैर-सरकारी संगठनों के कामकाज पर कड़ी नजर रखना था. 2012 में, तत्कालीन यूपीए सरकार ने कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना का विरोध करने वाले कई गैर-सरकारी संगठनों की बांह मरोड़ने के लिए एफसीआरए नियमों का इस्तेमाल किया. 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पहले महीने में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कई विदेशी-वित्त पोषित संगठनों पर भारत के “आर्थिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित” करने का आरोप लगाते हुए एक गोपनीय रिपोर्ट पेश की थी. इससे एनजीओ के प्रति मोदी सरकार का नजरिया साफ हो गया था. ■

खास रपटः चुनाव 2022 | मायावती

दरकती आस्था सिमटता साम्राज्य

उत्तरप्रदेश की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बसपा को विधानसभा चुनाव में मुकाबले से बाहर और मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भाजपा और सपा के बीच होने के अफसाने में कितना दम है? क्या बसपा वाकई रेस से बाहर है या किसी नई रणनीति के साथ मैदान में सबको चौंकाने की तैयारी कर रही है?

दयाशंकर शुक्ल सागर

झांसी में गुजरते साल के आखिरी दिनों की खिली धूप आमतौर पर सकून देने वाली होती है. चारों तरफ बिखरी ऐसी ही धूप में काले पुलओवर पर नीला कोट पहने सतीशचन्द्र मिश्र मंच पर अकेले खड़े दिखते हैं. पीछे बैक ग्राउंड में मुस्कुराती हुई मायावती की तस्वीर के साथ बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का एक बड़ा-सा बैनर लगा है. मंडल स्तर के रिजर्व सीट के कंडीडेट और कोऑर्डिनेटर गेंदे के फूलों की विशालकाय माला ब्राह्मण किंग मेकर के गले में डालते हुए तस्वीर खिंचवाते हैं. सामने सफेद चांदनी में कुसियों पर नीली टोपी पहने बैठे कार्यकताओं को संबोधित करते हुए धाकड़ वकील मिश्र कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हैं- ''नया साल बहुजन समाज पार्टी का होगा और हम सब बहनजी को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनते देखेंगे.''

दलित-ब्राह्मण भाईचारे के तमाम कामयाब प्रयोग कर चुके सतीश मिश्र के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी का हिमालय है. पहले सूबे के दर्जनों जिलों में ब्राह्मणों का ताबड़तोड़ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन फिर दिसंबर भर उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में रिजर्व सीटों पर जनसभाएं. मंच पर वे अकेले दिखते हैं. कोई बीस साल के राजनीतिक जीवन में इतना अकेलापन उन्होंने शायद कभी महसूस नहीं किया होगा. उधर भाजपा और सपा के बड़े नेताओं ने अपनी पूरी उर्जा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में झोंक दी है. मोदी और योगी गोरखपुर, वाराणसी, बुंदेलखंड, समेत कई रैलियां कर चुके हैं. पिछ्ले दस हफ्ते में मोदी की एक दर्जन से ज्यादा जनसभाएं हो चुकी हैं. अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी भी प्रदेश भर में सभाएं और रोड शो कर रहे हैं जबकि मायावती पिछ्ले साल 7 सितंबर को पहली दफा लखनऊ में प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी के समापन सम्मेलन में दिखाई दीं. इसके बाद वे कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के दिन 9 अक्तूबर 2021 को लखनऊ की एक बड़ी रैली में दिखीं. हर सभा, हर सम्मेलन में पत्रकार मिश्र से पूछा रहे हैं, ''बहनजी कहां हैं? वे क्यों नहीं नजर आ रहीं?'' नतीजा यह हुआ है कि चुनाव से ठीक पहले ही एक नैरेटिव बनाने की कोशिश चल निकली कि 2022 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच लड़ा जा रहा है.

झांसी में सभा के बाद इलेक्ट्रानिक मीडिया की मिश्र पर सवालों की बारिश शुरू हो जाती है. एक स्थानीय पत्रकार उनकी तरफ व्यंग्यात्मक लहजे में सवाल उछालता है, ''आप कहते हैं कि बसपा कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रही है जबकि भाजपा कहती है मायावतीजी दो साल से क्वारंटाइन

पीटीआइ

सजग सिपहसालार

मायावती की परछाई कहे जाने वाले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र ने अकेले चुनाव कमान संभाली है

हैं’’ असुविधाजनक हालात में खुद को सहज रखने में माहिर मिश्र थोड़े तल्ख हो जाते हैं, ‘‘वे कितने साल से क्वारंटाइन हैं, जरा ये भी तो पूछ लीजिए उनसे. और नौ अक्तूबर को वे आंख पर पट्टी डाले हुए थे क्या, जब पांच लाख लोगों को बहनजी संबोधित कर रही थीं. 7 सितंबर को वे आंख बंद रखे थे क्या?’’ इन दो तारीखों के अलावा मिश्र के पास कोई तीसरी तारीख नहीं है जब मायावती किसी सार्वजनिक मंच पर आई हों. जिद्दी पत्रकार आगे पूछते हैं कि ‘‘...ऐन चुनाव के वक्त मायावती निकलेंगी तो कहेंगी हमें प्रचार नहीं करने दिया गया?’’ मिश्र जवाब देते हैं, ‘‘अमित शाहजी क्या कह रहे हैं और योगीजी क्या कह रहे हैं... ये सब हमारी मीटिंग में उमड़ रहे जनसैलाब को देखकर ऐसी बातें कर रहे हैं, जब बहुत जल्द बहनजी हर जिले में प्रचार के लिए निकलेंगी (तभी मंच से तबला-हरमोनियम बजने लगता है, मिश्र मंच की तरफ देखकर गुस्से में उंगलियों से ‘ये क्या है’ की मुद्रा बनाते हैं. बाजा डर के बंद हो जाता है) तब किस तरह का तूफान आएगा देखिएगा.’’

लेकिन तूफान के इंतजार का वक्त किसे है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म से लेकर इलेक्ट्रानिक मीडिया तक सपा-भाजपा में असली मुकाबला दिखा रहे हैं. जेएनयू के सेंटर फॉर स्टडी आफ सोशल सिस्टम के प्रो. विवेक कुमार कहते हैं कि, ‘‘ये नैरेटिव जानबूझ के बनाया जा रहा है ताकि बसपा लड़ाई से बाहर दिखे. अनुभवजन्य आंकड़ों को देखिए. ग्रास रूट पर कोई ये नहीं पूछ रहा है कि समाजवादी पार्टी का संगठन कहां हैं? अगर संगठन है तो अखिलेश रोड शो क्यों कर रहे हैं? सब जानते हैं कि जिनका संगठन नहीं होता वही रोड शो करते हैं. 2012 में अखिलेश यादव की बैकडोर इंट्री हुई थी और वे इत्तेफाकन मुख्यमंत्री बने थे. दरअसल, ये चुनाव उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने बेनी प्रसाद वर्मा, आजम खान, अमर सिंह और शिवपाल यादव के संग लड़ा था. आज अखिलेश के पास इनमें से कोई चेहरा नहीं है. वे अकेले हैं. दूसरा डेटा यह है कि 2017 में सपा को 1 करोड़ 89 लाख वोट मिले थे जबकि बसपा को 1 करोड़ 93 लाख वोट मिले थे. इस लिहाज से भी बसपा, सपा से आगे थी. इस तरह इम्पीरकल डेटा कहीं से भी ये प्रमाणित नहीं करता कि ये लड़ाई किनके बीच में है.’’

दलित चिंतक प्रो. विवेक आगे कहते हैं कि, ‘‘वे यह नरैटिव इसलिए गढ़ना चाहते हैं ताकि भाजपा आसानी से आगे निकल जाए. समाजवादी पार्टी में 7 फीसदी यादव वोट और 16 फीसदी मुसलमानों के वोट का अगर पूरा ध्रुवीकरण हो भी जाए तो वे 23 या 24 फीसदी से आगे नहीं बढ़ते. तो ऐसे में भाजपा आगे निकल जाएगी. लेकिन दूसरी तरफ बसपा की तरफ 17 फीसदी मुस्लिम वोट और 20 फीसदी दलितों वोट एकजुट हो जाते हैं तो 37 फीसदी वोट कहीं नहीं गए. इसमें तीन या चार फीसदी वोट ब्राह्मणों के भी जोड़ दीजिए. क्योंकि जहां ब्राह्मण खड़ा होगा 3 या 4 प्रतिशत वोट तो उसे मिलेंगे ही. ऐसे में कहीं मुस्लिम और अपर कास्ट बसपा के पाले में न खड़ा हो जाए इसलिए ये नैरिटिव गढ़ा जा रहा है कि चुनाव में टक्कर सपा और भाजपा में है.’’

दलित चिंतकों की ये स्थापना पूरी तरह गलत भी नहीं है. बीएसपी अप्रैल 1984 में अस्तित्व में आई. लेकिन कांशीराम की विरासत संभालते ही 2002 के चुनाव में दूरदर्शी मायावती ने एक बड़ा रणनीतिक यू-टर्न लिया. वे बहुजन से सर्वजन समाज की तरफ शिफ्ट हो गईं. हालांकि ये अवधारणा कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन के चिंतन के खिलाफ थी. जैसा कि बसपा के संस्थापक सदस्यों में एक रहे पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद इंडिया टुडे से कहते हैं कि ‘‘मान्यवर कांशीराम ये कभी नहीं चाहते थे कि सवर्ण उनकी पार्टी से जुड़ें. उनका कहना था कि सवर्णों की तो अपनी छह पार्टियां हैं. अगर वे मेरी पार्टी में आए तो सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया रूक जाएगी. ये उनके हित में है कि स्टेटस-को रहे.’’ इसका पार्टी के भीतर विरोध हुआ और बाहर विपक्ष भी आक्रामक हो गया. विपक्ष ने प्रचार शुरू कर दिया कि ‘तिलक, तराजू और तलवार...इनको मारो जूते चार’ का नारा देने वाली पार्टी अब इन्हीं तीनों जातियों की शरण में चली गई है. (हालांकि डीएस4 के पुराने लोगों का दावा हैं कि ये नारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने दलित मूवमेंट को बदनाम करने के लिए गढ़ा था कांशीराम का असली नारा था, ‘तिलक तराजू और तलवार, इनसे रहो सदा होशियार’). लेकिन इन बातों की परवाह न करके 2002 में मायावती ने अपनी पार्टी के दरवाजे ब्राह्मण-ठाकुर जैसे सवर्णों और मुसलमानों के लिए खोल दिए और याद रहे तब तक सतीश मिश्र की राजनीति में इंट्री भी नहीं हुई थी. इस चुनाव में बसपा ने ब्राह्मण (38), ठाकुरों (36) मुसलमानों (82) और पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों (126) को दिल खोलकर टिकट बांटे. तब बसपा सवर्ण प्रत्याशियों को दिलचस्प पैकेज देती थी, जिसमें जीत की लगभग गारंटी होती थी. बसपा के गैर दलित प्रत्याशियों को केवल अपनी बिरादरी के वोट

बातचीतः

फैजान खान, *राष्ट्रीय प्रवक्ता, बसपा*

“असल में सबकी लड़ाई बसपा से है”

- **एक नैरेटिव बनाया जा रहा है चुनाव में भाजपा-सपा आमने सामने हैं और बसपा लड़ाई से बाहर है?**

असल में सबकी लड़ाई बसपा से है. लेकिन इसे बाइपोलर दिखाया जा रहा. क्योंकि ये दोनों दल एक दूसरे के पूरक और पोषक हैं. हिंदू-मुस्लिम की सियासत करते हैं. अगर आप डेटा भी देखें तो पाएंगे कि लोकसभा चुनाव में जब हम सपा से मिलकर लड़े थे तो हमारी 10 सीटें आईं थी और सपा की 5 सीटें. बसपा का वोट प्रतिशत भी ज्यादा था. सपा सबसे पहले टिकट घोषित करती थी. पर इस बार क्या हो गया. सपा जानती है कि अगर उसने टिकट का ऐलान कर दिया तो उनकी किसी सभा में भीड़ नहीं दिखेगी.

- **सभी दलों के नेता चुनाव मैदान में प्रचार कर रहे हैं लेकिन बहन जी कहीं नहीं निकल रहीं. मोदीजी अब तक एक दर्जन से ज्यादा रैलियां...?**

रैलियां तो उन्होंने बंगाल में भी की थीं वो भी कोरोना काल में क्या नतीजा रहा? सबको रैली करने से मना किया जा रहा है. हमें जनता की जान की भी परवाह है. कांशीरामजी की पुण्यतिथि पर 9 अक्टूबर को बहनजी सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि देने निकली थीं और लाखों की भीड़ उन्हें देखने के लिए जमा हो गई. अब अगर बहन जी ओमिक्रॉन के इस दौर में प्रदेश में निकल गई होतीं तो क्या होता? इन्हें सत्ता का लालच है. हमें लोगों की जान की परवाह है.

- **तो आप कहना चाहते हैं बहनजी कोविड के कारण रैलियां नहीं कर रहीं?**

नहीं कोविड के कारण नहीं. हम अपनी पॉलिटिक्स अपने तरीके से करते हैं. अगर बहनजी नहीं निकलीं तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है.

- **लेकिन विपक्ष को इससे बहाना मिल गया है वे कह रहे हैं कि तमाम जांचों से बहनजी को इतना डरा दिया गया है कि वो प्रचार नहीं कर रहीं हैं?**

ये अफवाह फैला दी गई है बस. ये आपस की नूरा कुश्ती में बता रहे हैं कि ये इसका काला धन (कानपुर-कनौज इत्र व्यापारी प्रकरण) है ये उसका काला धन है.

- **ऐसा पहली बार है कि चुनाव में बसपा का कोई पुराना चेहरा नहीं दिख रहा. सब बड़े नेता पार्टी से निकाले जा चुके हैं?**

इन्हें नेता किसने बनाया? मायावती ने ही इन्हें नेता बनाया न, वर्ना इन्हें कौन जानता था. नेता के जाने से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जनता तो हमारे साथ है. ये सब चुके हुए नेता थे. किसी को बेटे के लिए टिकट चाहिए था किसी को दामाद के लिए. बसपा में ये सब नहीं चलता. लालच और मोह में ये लोग दूसरे दलों में चले गए. देखिएगा इनका क्या हश्र होता है.

- **लेकिन अब वे ये प्रचार कर रहे हैं कि सतीश मिश्रा को आरएसएस ने बसपा को खत्म करने के लिए प्लांट किया है?**

अब आप बताइए सतीशजी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं. 72 साल की उम्र में भी रात दिन पार्टी के काम में लगे हैं. जो पार्टी के लिए मेहनत करता है उस पर भी आरोप लगाया जाएगा कि वो प्लांट किया गया नेता है. ये उनकी बौखलाहट है बस.

जुटाने होते थे. चुनाव में दिलचस्पी लेने वाले नेताओं के लिए बसपा का टिकट एक ऐसा लाटरी टिकट हो गया था जिसका नंबर लगना तकरीबन तय था. जाहिर है इसके लिए प्रत्याशी को काफी संसाधन जुटाने पड़ते थे. पर यह समावेशी फार्मूला रंग लाया और 2002 के चुनाव में नीला हाथी पहली बार पूरे आत्मविश्वस से शतक (98 सीटें जीत कर) की दहलीज पर आकर लखनऊ एनेक्सी के सामने एक बार फिर खड़ा हो गया. मायावती के सिर पर देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनने का तीसरी बार ताज सज गया. फिर तो ये फार्मूला मायावती का ट्रेड मार्क बन गया. 2007 में तो इस फार्मूले ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर चमत्कार ही कर दिया. लेकिन 2012 और 2014 में मोदी लहर के बाद बसपा का जनाधार लगातार गिरता चला गया. और अब नौबत ये आ गई कि विरोधी दल बड़ी चतुराई से उन्हें लड़ाई से ही बाहर बता रहे हैं.

चैनसुख भारती बसपा के संस्थापक सदस्यों में एक रहे हैं. भारती ने ‘इंडिया टुडे’ से कहा कि, ‘‘बसपा के कार्यकर्ता कभी मुखर नहीं रहे. वे ग्रासरूट पर काम करते हैं. गांव स्तर पर मीटिंगें करते हैं. बहनजी हमेशा बाद में ही चुनाव प्रचार के लिए निकलती हैं.’’ लेकिन बावजूद इसके ये नरैटिव इतनी तेजी से फैलने लगा कि सतीश मिश्र ने 29 दिसम्बर को ट्वीट किया, बहनजी आने वाली है. पार्टी के सूत्र कहते हैं अगर कोविड के कारण रैलियों पर रोक नहीं लगी तो अपने जन्म दिन (15 जनवरी) से वे 75 जिलों में रैलियों का सिलसिला शुरू कर सकती है.

‘तीसरा पक्ष अभी जिंदा है’

बद्रीनारायण, (दलित चिंतक)

ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि 2022 का चुनाव का मुकाबला केवल दो दलों के बीच सिमट गया है, ऐसा है नहीं. अभी तो मायावती ने कैंपेन शुरू ही नहीं किया है. जब वे निकलेंगी तो दलित मतदाताओं में उत्साह आएगा तो वे विजिबल होंगे. दूसरे समुदाय भी उनसे जुड़ेंगे. सोशल मोबिलाइजेशन भी मायावती के निकलने के बाद शुरू होगा. दूसरी बात बसपा जैसी पार्टी में नेताओं के पार्टी छोड़ने या निकाले जाने से कोई असर नहीं पड़ता है. ये काडर बेस्ड पार्टी है. ये किसी को खड़ा कर देंगे वो नेता हो जाएगा. जो लीडर निकले हैं वो किसी भी दल में गए हों, वे खत्म हो गए हैं. बसपा एक अलग तरह की पार्टी है, जिसका मूल्यांकन अन्य राजनीतिक दलों की तर्ज पर नहीं किया जा सकता. लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि बसपा का जनाधार घटा है. बहुजन समाज में भी जाटवों, कोरियों, धोबियों आदि का एक नया मिडिल क्लास पैदा हुआ है जिसकी अलग राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं.

फोकस रिजर्व सीटों पर

बसपा 2022 के चुनाव में 'जो है उसे समेटो' के मंत्र पर काम कर रही है. उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि दलित पार्टी के रणनीतिकारों ने बड़ी चतुराई से अपना फोकस सूबे की केवल 86 आरक्षित सीटों पर केंद्रित किया है. बसपा ने मिशन 2022 को दो चरणों में बांटा. एक 'प्रबुद्ध विचार संगोष्ठियां' और दूसरे चरण में मंडल स्तर पर जनसभाएं. इन दोनों चरणों के केंद्र में दलित-ब्राह्मण समीकरण को साधने की कोशिश है. जुलाई के सावन के महीने में 'प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी की शुरूआत के लिए सतीश मिश्र ने राम की जन्मभूमि अयोध्या को चुना. लेकिन राम अब भाजपा के ट्रेड मार्क हैं. सो सतीश मिश्र अपने भाषणों में सीता मैया को तरजीह देते हैं. मिश्र कहते हैं, ''अयोध्या में आकर भाजपा नेता राम मंदिर की बात करते हैं. लेकिन वे सीता मैया की बात नहीं करते.'' पौराणिक आख्यानों में राजनीतिक रसायन मिलाकर मिश्र सीता को सीधे वाल्मीकि से जोड़ देते हैं. वे बताते हैं कि कैसे मायावती ने अपनी पिछली सरकार में बिठूर के उस वाल्मीकि आश्रम को ठीक कराने में कई सौ करोड़ रुपए खर्च किए, जहां लव-कुश के साथ सीता मैया रहती थी. वहां सीता रसोई भी बनवाई. इस तरह उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलनों में भी दलित और महिला वोटरों को रिझाने का कनेक्शन खोज लिया. अब मिश्र अपने हर भाषण में सीता मैया को याद करते हैं. सितंबर में जिला स्तर पर हुए इन प्रबुद्ध सम्मेलनों के बाद सतीश मिश्र ने 8 दिसंबर से मंडल स्तर पर जनसभाएं शुरू की. इनमें फोकस केवल सुरक्षित सीटों पर था. जैसे मिल्कीपुर (अयोध्या), मनकापुर(गोंडा), खजनी (गोरखपुर), महादेवा(बस्ती), मऊरानीपुर (झांसी) नरैनी (बांदा) आदि.

पार्टी थिंकटैंक को लग रहा है कि ब्राह्मणों को इन सीटों से जोड़ा जा सकता है इसीलिए मिश्र अपने हर भाषण में दोहरा रहे हैं कि ''अगर 13 फीसदी ब्राह्मण और 23 फीसदी दलित मिलकर भाईचारा कायम कर लें तो उनकी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता.'' इन सभी सीटों पर सतीश मिश्र का एक ही संदेश है- ब्राह्मण और दलित वोट बंटे नहीं, जैसे पिछले चुनाव में बंटे थे. इन रिजर्व सीटों पर कब्जे के लिए मायावती ने चौतरफा घेरेबंदी की है. उन्होंने एक तरफ मिश्र को ब्राह्मण वोटों के लिए लगाया है, दूसरी ओर अति पिछड़े खासतौर से जाट और मुस्लिम इंचार्जों को दिसंबर के शुरूआती दिनों में ही लखनऊ बुलाकर समझा दिया कि कैसे वोटों को एकजुट करना है. ब्राह्मण पिछले चुनावों में बड़ी मुश्किल से भाजपा के पीछे एकजुट हुआ था. इसे तोड़ने के लिए विपक्ष ने भाजपा सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा और नाराजगी को जमकर हवा दी. मिश्र इसी को कैश करने की जुगत में हैं. लेकिन बसपा के लिए ब्राह्मणों को जोड़ना इतना आसान भी नहीं होगा. लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार बृजेश शुक्ल कहते हैं कि, ''अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और काशी में कोरिडोर ने ब्राह्मणों के एक तबके को बहुत प्रभावित किया है. उसका असर इस चुनाव में दिखेगा.''

बिदक गई हाथियों की सेना

नब्बे और नए सदी के पहले दशक में मायावती की कामयाबी के पीछे दलित-पिछड़े और अति पिछड़े-मुस्लिम नेताओं की एक वफादार फौज थी, जो मायावती की नई सोशल इंजीनियरिंग को जमीन पर बखूबी अंजाम देती थी. इन्हीं के बल पर मायावती ने सूबे में जमीनी स्तर पर ऐसे समीकरण तैयार किए थे जिनके बल पर कांग्रेस यहां आजादी के बाद से अस्सी के दशक के अंत तक राज करती आई थी. बसपा की रणनीति को उसके पुराने नेता अभी तक याद करते हैं. अपने काफिले के साथ सपा के प्रचार के लिए वाराणसी कूच कर रहे कभी बसपा के कद्दावर नेता रहे राम अचल राजभर 'इंडिया टुडे' से कहते हैं, ''साहेब (कांशीराम) हमें खूब दौड़ाते थे. पाल, निषाद, कुर्मी, मल्लाह, धोबी, पासी, केवट, राई, गद्दी, घोसी, राजभर जातियों के सारे नेता अपने लोगों के बीच जाते थे. समाज के लोग उन्हें ही नेता मानते थे क्योंकि सरकार और उनके बीच की कड़ी यही नेता थे. अब नब्बे फीसदी राजभर और कुर्मी सपा के साथ है. मैंने इस समाज को 38 साल दिए हैं, इसके नुकसान की भरपाई अब बसपा कैसे करेगी ?.''

बसपा का सबसे ताकतवर समीकरण दलित-ब्राह्मण-मुसलमान के गठजोड़ का था. यानी 21 फीसदी दलित, 30 फीसदी सवर्ण और 17 फीसदी मुसलमान. दलितों को मानवीय गरिमा प्रदान करने वाला ये एक अजेय फार्मूला था जिसकी काट न भाजपा के पास है न सपा के पास. ब्राह्मण और मुसलमानों को करीब लाने के लिए मायावती के पास दो भरोसेमंद चेहरे थे. एक उनके कानूनी सलाहकार पंडित सतीश चंद्र मिश्र और दूसरे उनके वफादार सिपहसालार नसीमुद्दीन सिद्दीकी. एक ताज गलियारे घपले में फंसी मायावती के संकटमोचक थे, दूसरा एक मुस्लिम नौजवान जिसे उनकी पार्टी में शुरूआती मुसलमान विधायकों में एक होने का तमगा मिला था. तब दलितों की पार्टी में नसीमुद्दीन की हैसियत उस गैर-अरबी मुसलमान हजरत बिलाल जैसी हो गई जिसे पैगम्बर ने मदीना की मस्जिद में पहली दफा अजान पढ़ने की इज्जत बख्शी थी क्योंकि उस अफ्रीकी बाशिंदे की आवाज़ मीठी पर बुलंद थी. सतीश मिश्र ने बसपा के चुनाव चिन्ह को 'हाथी नहीं गणेश' है के नारे में बदला तो वालीबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके दबंग नसीमुद्दीन ने पार्टी को सिखाया कि अनुशासन ही कैडर का मूल मंत्र है. मायावती ने इन दोनों को 2007 की शानदार जीत का रचनाकार बताया था. नसीमुद्दीन को मायावती ने 10 मई, 2017 को 'टेपिंग ब्लैकमेलर' बताते हुए 'पार्टी फंड में हेराफेरी' और ''अनुशासनहीनता'' के इल्जाम में पार्टी से बर्खास्त कर दिया.

बसपा का दूसरा ताकतवर समीकरण दलित-अति पिछड़ा गठजोड़ था, जिसे अंबेडकर नगर इलाके में जमीनी सतह पर देखा जा सकता है. अयोध्या से 75 किमी. दूर अंबेडकर नगर संसदीय सीट कभी गाजियाबाद की रहने वाली मायावती का गढ़ थी. मायावती ने इस सीट से 1998,1999 और 2004 में चुनाव जीत कर हैट्रिक लगाई. यहां मायावती की ताकत के पीछे अति पिछड़े वर्ग के उनके दो भरोसेमंद क्षत्रप राम अचल राजभर और लालजी वर्मा हुआ करते थे. कांशीराम से जुड़े राजभर को तो बसपा 'संगठन का शिल्पकार' माना जाता था. वे अकबरपुर से पांच बार विधायक चुने गए. बसपा ने उन्हें न केवल प्रदेश अध्यक्ष बनाया बल्कि एक वक्त तो वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी बना दिए गए थे. कई राज्यों के प्रभारी रहे. इसी तरह लालजी वर्मा बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा में विधानमंडल दल के नेता रहे. दोनों बसपा की हर सरकार में

''अंत में आप पाएंगे पार्टी में सिर्फ मिश्र बचेंगे, आरएसएस का मैनेजमेंट गजब का है. उसने उन्हें बेहद सुनियोजित एजेंडे के तहत बसपा में भेजा है.''

नसीमुद्दीन सिद्दीकी
(पूर्व कैबिनेट मंत्री, बसपा)

इंडिया टुडे
देश की भाषा में देश की धड़कन

INDIA TODAY GROUP

विशेषांक
इंडिया टुडे
3 नवंबर, 2021
50 रुपए
ऊंचे और असरदार
रसूखदारों की सूची 2021
27 अक्तूबर, 2021
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021
बेहतरी की उम्मीद
महामारी के बाद उपजी आशंका और आशा के बारे में राजनीति, कारोबार, विज्ञान और खेलकूद की प्रमुख हस्तियों की राय

सबसे भरोसेमंद स्रोतों से, सबसे सटीक जानकारी

सब्सक्राइब करें और पाएं 21% तक की छूट

हां! मैं इंडिया टुडे को सब्सक्राइब करना चाहता/चाहती हूँ

अपनी पसंद के सब्सक्रिप्शन को टिक करें और फॉर्म को इस पते पर भेज दें– **वी केअर, लिविंग मीडिया इंडिया लि. सी–9, सेक्टर–10, नोएडा 201302 (भारत)**

टिक करें	अवधि	कुल अंक	कवर प्राइस (₹)	ऑफर प्राइस (₹)	डिस्काउंट
☐	2 वर्ष	104	~~5200~~	4099	21%
☐	1 वर्ष	52	~~2600~~	2199	15%

कृपया फॉर्म को ब्लॉक लेटर में भरें

मैं चेक/डीडी जमा कर रहा/रही हूँ जिसकी संख्या.......................है और इसे दिनांक................ को लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के पक्ष में .... (बैंक का नाम).......................रुपये की धनराशि (दिल्ली से बाहर के चेक के लिए ₹ 50 रुपये अतिरिक्त जोड़ें, समान मूल्य के चेक मान्य नहीं होंगे) के लिए बनवाया गया है.

नाम.. पता..

.... शहर...................... राज्य...................... पिन......................

मोबाइल.. ईमेल..

सब्सक्राइब करने के लिए यहां स्कैन करें.

ऑफर के विषय में विशेष जानकारी के लिए निम्न माध्यमों से संपर्क भी कर सकते हैं

हमारे टॉल फ्री नंबर पर कॉल करें
18001800100 (0120) 2479900

ईमेल भेजें
wecare@intoday.com

लॉग ऑन करें
subscriptions.intoday.in/indiatoday-hindi

लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड इस ऑफर या इसके अंश को कभी भी समाप्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कृपया देखें-www.indiatoday.in

मंत्री रहे. 2017 में जब भाजपा की लहर थी, तब इन दोनों नेताओं ने न केवल अपनी सीट बचाई बल्कि इलाके की एक और सीट पार्टी की झोली में डाल दी. वर्मा कुर्मी नेता हैं और अंबेडकर नगर में करीब ढाई लाख कुर्मी वोटर हैं. इन दोनों कद्दावर नेताओं को बहनजी ने बीते साल जून में बाहर का रास्ता दिखा दिया और सपा ने बिना वक्त गंवाए दोनों जनाधार वाले नेताओं को लपक लिया. अब ये दोनों नेता बसपा की जड़ें खोदने में जुट गए हैं. उधर राकेश पांडेय अंबेडकर नगर से बसपा के दबंग सांसद हुआ करते थे. मायावती ने उन्हें अपनी सीट से चुनाव जितवाया. पांडेय ने भी अभी 3 जनवरी को सपा का दामन थाम लिया. इससे पहले भी ब्राह्मण नेताओं का बसपा से मोह भंग हो चुका है. बसपा के सांसद रहे ब्रजेश पाठक 2017 के विधानसभा चुनाव के ठीक एक साल पहले हवा का रुख भांप कर पार्टी छोड़कर न केवल भाजपा में शामिल हो गए बल्कि बहुत जल्द सूबे की योगी सरकार में मंत्री भी बन गए. अब वे भाजपा का ताकतवर ब्राह्मण चेहरा हैं. ब्रजेश पाठक ने 'इंडिया टुडे' से कहा ''सिर्फ ब्राह्मण नहीं बल्कि सर्वसमाज भाजपा के साथ है. जहां तक इस चुनाव में हमारी लड़ाई का सवाल है वो किसी के साथ नहीं. विकास की आंधी में सारे गठबंधन तो पहले ही फेल हो चुके हैं.''

इसी तरह ब्रिजेश मिश्र सौरभ प्रतापगढ़ के बसपा नेता हुआ करते थे. 2012 में उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी. सौरभ कहते हैं, ''2012 में पार्टी छोड़ते वक्त मैंने नसीमुद्दीन से साफ कहा था कि अब प्रतापगढ़ सदर की भूमि पर बसपा का कोई उम्मीदवार नहीं जीतेगा. एक वह दिन था और आज ये दिन है तब से बसपा का कोई नेता यहां से चुनाव नहीं जीता.'' इसी तरह बसपा सरकार में ताकतवर ऊर्जा मंत्री रहे सादाबाद से पार्टी के विधायक रामवीर उपाध्याय दो साल पहले पार्टी से निलंबित कर दिए गए. पहले बसपा विधायक रहे उनके छोटे भाई मुकुल उपाध्याय भाजपा में शामिल हुए फिर उनका बेटा और फिर पत्नी सीमा उपाध्याय भी. रामवीर अब गले में जय श्री राम लिखा दुपट्टा डाले घूम रहे हैं.

इसी तरह बसपा के स्थापना काल से पार्टी का सांगठनिक ढांचा तैयार करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, आर.के. चौधरी, वीर सिंह, जुगल किशोर, बाबू सिंह कुशवाहा, दारा सिंह चौहान, दद्दू प्रसाद जैसे दिग्गज नेता बसपा छोड़ गए या पार्टी से निकाल दिए गए. अब सब बसपा को मटियामेट करने में लगे हैं. इटावा में कांशीराम के चुनाव प्रतिनिधि रहे बसपा के संस्थापक सदस्यों में एक डॉ. बाबू रामाधीन कहते हैं, ''ये डूबता जहाज है. बसपा का पतन उसी दिन से शुरू हो गया था जब धन्नासेठों को टिकट मिलने लगा था.'' तो 2007 में मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे बना ली थी? जवाब में डॉ. रामाधीन कहते हैं, ''ये जीत 2006 में मान्यवर कांशीराम के निधन की सहानुभूति की लहर का नतीजा थी.''

बसपा के संस्थापक लीडर के रूप में पहचान रखने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद 2015 में बसपा से निकाले गए. 2017 के चुनाव में पूरे बुंदेलखंड से बसपा का सफाया हो गया. बसपा की ताकत केवल जाटव वोट नहीं हैं. उसमें बहुजन समाज का अति पिछड़ा वर्ग भी शामिल था (कांशीराम जिसे को-सफरर कहते थे), जिसकी मदद से बुंदेलखंड की सारी सीटें भाजपा के खाते में चली गईं. नाराज दद्दू प्रसाद कहते हैं, ''सच तो ये है कि मायावती ने कांशीराम की स्क्रिप्ट भाजपा को बेच दी है. ताकि उन्हें और उनके भाई-भतीजे को जेल न जाना पड़े.''

कांग्रेस में चले गए नसीमुद्दीन ने इंडिया टुडे से कहा कि, ''अंत में आप पाएंगे पार्टी में सिर्फ मिश्र बचेंगे, आरएसएस का मैनेजमेंट गजब का है. उसने उन्हें बेहद सुनियोजित एजेंडे के तहत बसपा में भेजा है.''

लेकिन दलित चिंतक इसे दगे हुए कारतूसों की खीझ बताते हैं. प्रो. विवेक कुमार कहते हैं, ''सड़े हुए अंडों से आमलेट नहीं बनाया जाता. अशोक सिद्धार्थ, रामजी गौतम, मुनकाद अली, भीम राजभर, ओजस्वी वक्ता धर्मवीर अशोक जैसे बसपा में कई नेता अभी भी हैं लेकिन उन्हें कोई नेता न माने तो कोई क्या किया जाए.''

2007 में 206 विधायकों वाली पार्टी 2017 में 19 सीटों में सिमट कर रह गई. 37 साल की राजनीति में बसपा का इतना खराब प्रदर्शन पहली बार हुआ. इतने खराब नतीजों ने मायावती को दो साल बाद अपनी जानी दुश्मन पार्टी सपा से लोकसभा चुनाव में हाथ मिलाने को मजबूर किया. लेकिन हालात और बदतर हो गए. न अकेले दम पर बात बन रही है न किसी से गठबंधन करके. 2022 का चुनाव बसपा के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है. लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं कि इस चुनाव में बसपा ने अगर कोई चमत्कार नहीं किया तो मायावती के पास राजनीतिक वानप्रस्थ की तरफ जाने के सिवा कोई और विकल्प नहीं बचेगा. ■

रिजर्व सीट-सत्ता का गलियारा

दरअसल उत्तर प्रदेश में सत्ता का गलियारा दलित बहुल रिजर्व सीटों से होकर गुजरता है. इन रिजर्व सीटों पर बसपा का सर्वाधिक बेहतर स्कोर 2007 के चुनाव में रहा था जब रिकार्ड 62 सीटें मायावती की झोली में आकर गिरी थीं और उनके लिए राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का रास्ता बना था. लेकिन पिछले दस साल में सब कुछ बदल गया. 2017 के विधानसभा चुनाव में 86 में से रिकार्ड 74 सीटें भाजपा की तकदीर से नत्थी हो गईं. इन 74 में से चार सीटें (सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 3 और 1 अपना दल (सोनेलाल)) जैसे सहयोगी दलों ने जीती थीं. इस तरह 2017 के चुनाव में रिजर्व सीटों पर भगवा पार्टी का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. और इस प्रदर्शन ने उसे न केवल पूर्ण बहुमत दिलाया बल्कि उसे राज सिंहासन तक पहुंचा दिया जहां आज योगी बैठे हैं. हैरत की बात ये थी कि पांच साल पहले 2012 के चुनाव में भाजपा ने केवल तीन रिजर्व सीटें जीती थीं. सपा के हिस्से यहां से 58 सीटें आईं और अखिलेश ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली थी. और एक दिन ऐसा आया जब इन्हीं रिजर्व सीटों ने बसपा को अचानक अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया. 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा के हिस्से केवल दो रिजर्व सीटें आईं. तो यूपी की रिजर्व सीटें बसपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती हैं इसे बखूबी समझा जा सकता है.

''सच तो ये है कि मायावती ने कांशीराम की स्क्रिप्ट भाजपा को बेच दी है. ताकि उन्हें और उनके भाई-भतीजे को जेल न जाना पड़े.''

दद्दू प्रसाद

(पूर्व बसपा नेता)

GOA@60
आजादी का अमृत महोत्सव
Department of Information and Publicity
GOA LIBERATION DAY

गोवा: सफलता के लिए आत्मनिर्भरता

देश का सबसे छोटा राज्य गोवा मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा की कामयाबियों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत की सराहना की.

हाल ही में गोवा का मुक्ति दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान हजारों लोग गोवा के गौरव के शानदार प्रदर्शन में जुटे. देश का यह सबसे छोटा राज्य औपनिवेशिक शासन से आजाद होने वाला आखिरी इलाका था. लेकिन, 1961 के उस महत्वपूर्ण दिन के बाद से इसने तेजी से तरक्की की है.

पुर्तगाली शासन से अपनी मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए साल भर चलने वाले उत्सव का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोवा आगमन के साथ हुआ. उन्होंने विभिन्न सुशासन सूचकांकों में गोवा की कामयाबी का उल्लेख किया और विकास से संबंधित उपलब्धियों के लिए राज्य सरकार की सराहना की.

उन्होंने राजधानी पणजी के ठीक बाहर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में 19 दिसंबर को अपने भाषण में कहा, ''सुशासन के हर काम में अग्रणी रहना राज्य की नई पहचान बन गई है. अन्य जगहों पर जो काम अभी शुरू ही हुआ है, गोवा उन्हें पहले ही पूरा कर चुका है.''

अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों का अभिनंदन किया, विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, पंचायत और नगर निकायों को पुरस्कार प्रदान किए, राज्य के शहीद नायकों को श्रद्धांजलि दी तथा सशस्त्र बलों की ओर से आयोजित जलयानों और वायुयानों की परेड में शिरकत की.

मोदी ने डॉ. प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली राज्य भाजपा सरकार की उपलब्धियों की खास तौर पर तारीफ की. मोदी ने डायमंड जुबली गिफ्ट स्कीम के तहत स्कूलों में कोडिंग और रोबोटिक्स की पढ़ाई शुरू करने की मुख्यमंत्री के कदम की तारीफ करते हुए उनकी पीठ थपथपाई.

उन्होंने कहा, ''अगर गोवा से सटा समुद्र है, जिसका ओर-छोर नहीं, तो यहां युवाओं के सपने भी उतने ही विस्तृत हैं. इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें एक विजन की जरूरत है. मैं कह सकता हूं कि सावंत इसी तरह के विजन के साथ काम कर रहे हैं. अपनी मुक्ति के 75 साल पूरे होने पर गोवा कहां पहुंचेगा? नए संकल्प करें. गोवा में निरंतरता की जरूरत है. विकास की रफ्तार भविष्य में भी ऐसी ही बनी रहनी चाहिए. हमें इस रफ्तार को रोकना या कम नहीं करना चाहिए.''

1961 में अपनी मुक्ति के बाद से गोवा के विकास के लिए काम करने वाली सभी सरकारों को गोवा की सफलता का श्रेय देते हुए, डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि ''विकास का मार्ग प्रशस्त करने और आज गोवा को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए'' सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है. उन्होंने कहा, ''मेरी सरकार राज्य और उसकी हर जाति और धर्म के लोगों के हित में फैसले करती है. मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास में विश्वास करती है.''

डॉ. प्रमोद सावंत ने लोगों से केंद्र और राज्य की आत्मनिर्भर भारत तथा स्वयंपूर्णा गोवा पहलों के जरिये अपनी प्रगति के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की. साथ ही सभी क्षेत्रों में विकास को सुनिश्चित करते हुए इसे स्वच्छ, हरा-भरा और टिकाऊ, शांतिप्रिय जगह बनाए रखने का आग्रह किया.

बाद में प्रधानमंत्री ने गोवा में 600 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इनमें फोर्ट अगुआडा में पुनर्निर्मित जेल संग्रहालय शामिल है. उस जेल में कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था. उन्होंने गोवा मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक; दक्षिण गोवा में एक नया जिला अस्पताल; मोपा में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पर एक विमानन कौशल विकास केंद्र और मडगांव के पास डाबोलिम-नावेलिम में एक गैस-इन्सुलेट सबस्टेशन का उद्घाटन भी किया.

इसके अलावा, उन्होंने गोवा को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की स्मृति में एक विशेष कवर भी जारी किया.

उन्होंने 'माई स्टाम्प' जारी किया, जिसमें मुक्ति आंदोलन में शहीदों के बलिदान का अभिनंदन करते हुए पत्रादेवी के हुतात्मा स्मारक का चित्रण किया गया है. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की विभिन्न घटनाओं की तस्वीरों के कोलाज वाला मेघदूत पोस्टकार्ड स्वीकार किया.

मुख्यमंत्री और राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लै के साथ प्रधानमंत्री आजाद मैदान गए, जहां उन्होंने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया और गोवा की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों के सम्मान में कुछ मिनट बिताए. मोदी ने कहा, ''गोवा की मुक्ति संग्राम का इतिहास केवल भारत के संकल्प का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारत की एकता और अखंडता का एक जीवंत दस्तावेज है.'' उन्होंने कहा कि सदियों की उथल-पुथल और सत्ता हस्तांतरण के बावजूद ''गोवा भारत को नहीं भूला और न ही भारत गोवा को भूल गया.'' उन्होंने यह भी कहा कि गोवा ने भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक स्वतंत्रता की लपटों को जलाए रखा.

अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर को भी श्रद्धांजलि

Chief Minister Dr Pramod Sawant Inaugurating the Start-Up Conclave & Entrepreneurship Summit “Antha Prerna”

अर्पित की. मार्च 2019 में पर्रीकर का निधन हो गया था. पर्रीकर चार बार मुख्यमंत्री बने और वे 2014 से 2017 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे. उन्हें पिछले साल मरणोपरांत पद्मभूषण से सम्मानित किया गया.

मोदी ने कहा, ''मैं जब गोवा की उपलब्धियों और इसकी नई पहचान को मजबूत होता हुआ देखता हूं तो मुझे अपने दोस्त मनोहर पर्रीकर जी याद आते हैं. उन्होंने गोवा को न केवल विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि गोवा की क्षमता का भी विस्तार किया. कोई अपनी अंतिम सांस तक अपने राज्य, अपने लोगों के प्रति किस तरह समर्पित रह सकता है? इसे हमने उनकी जिंदगी में देखा है.'' इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि राष्ट्र ने पर्रीकर में गोवा के लोगों की ईमानदारी, प्रतिभा और परिश्रम का प्रतिबिंब देखा.

उसके बाद मोदी शानदार मीरामार समुद्र तट के लिए रवाना हुए जहां उन्होंने भारतीय नौसेना के वायुयानों और जलयानों की परेड को देखा.

भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला छोटा राज्य

इस बार लगातार तीसरे साल भी इंडिया टुडे ने गोवा को छोटे राज्यों में विजेता करार दिया है और उसने खासकर अर्थव्यवस्था, पर्यटन और बुनियादी ढांचे में अन्य दावेदारों से बेहतर प्रदर्शन किया है. साल 2012 में खनन पर प्रतिबंध की मार झेलने के बावजूद, 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह और बुनियादी ढांचे में वृद्धि के मामले में राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.

2017-18 में इसकी सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 12.14 फीसद ज्यादा रही. राज्य भर में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया गया है. इनमें मंडोवी नदी पर नया अटल सेतु पुल, जुआरी नदी पर एक नया पुल, मोपा में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दक्षिण गोवा में एक औद्योगिक निगम के लिए यातायात के बोझ को कम करने वाली चार लेन की सड़क और हाइकोर्ट का नया परिसर शामिल है.

इसके अलावा, दक्षिण गोवा के तुएम में एक इलेक्ट्रॉनिक हब के विकास के लिए फंड लगाया जा रहा है. यहां तक कि कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राज्य भर में कई स्थानों पर पुलों का पुनर्निर्माण किया गया है. स्वच्छ भारत के नितोल गोएम मिशन के हिस्से के रूप में, सरकार ने पूरे गोवा में 100 फीसद घर-घर कचरा संग्रह की दिशा में काम किया है. इसके तहत 14 शहरी स्थानीय निकायों में पृथक्करण सफलता दर 86 फीसद है.

निवेश की आशाजनक जगह

गोवा ने मुक्ति के बाद से प्रसन्नता के वातावरण और अच्छी जिंदगी का खिताब हासिल किया है. सरकार समृद्धशाली पर्यटन के अलावा अपने राजस्व में नए आयाम जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है. समग्र उद्देश्य गोवा को एक निवेश गंतव्य के रूप में बदलना है ताकि राज्य में रोजगार और वैकल्पिक उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके.

पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने उद्यमिता और टिकाऊ व्यवसायों को बढ़ावा दिया है; आइमैजिक (एस4एस)3, डब्ल्यूई-नेचर और रिवर समेत कई स्टार्ट-अप पहलें शुरू की गई हैं; गोवा के स्टार्ट-अप में निवेश आकर्षित करने के लिए एक इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है; और गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अटल इनक्यूबेशन सेंटर के जरिये वैकल्पिक करियर विकल्प के रूप में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया है.

अवसरों को बढ़ावा देकर और रोजगार के इको-सिस्टम को प्रोत्साहन देकर 'गोवावासियों को गोवा में बनाए रखना' डॉ. प्रमोद सावंत का विजन है. स्टार्ट-अप कॉनक्लेव और उद्यमिता सम्मेलन अंत: प्रेरणा इनमें से एक है.

प्रमाणित स्टार्ट-अप्स को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए अप्रैल 2019 तक 1.27 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था. देश में नवाचारों के लिए वैश्विक पूंजी जुटाने के लिए गोवा में स्टार्ट-अप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट का भी आयोजन किया गया था. इसकी मदद करने के लिए, 2020 में एक नई दूरसंचार इनफ्रास्ट्रक्चर नीति को पेश किया गया है. इस नीति का मकसद तकनीकी स्टार्टअप, आईटी पेशेवरों, छात्रों समेत समाज के सभी वर्गों के फायदे के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार करना है.

इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के इग्नाइट इनोवेशन हब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट बिल्डिंग सॉल्यूशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, 3डी प्रिंटिंग और अन्य में काम करने वाली संस्थाओं से 100 प्रतिशत क्षमता हासिल कर ली है.

डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा है, ''गोवा में अनुकूल कारोबारी माहौल है. हम गोवा को निवेशकों और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए नीतियां तैयार कर रहे हैं. निवेश प्रमोशन बोर्ड अब 15 दिनों की निश्चित समय सीमा के भीतर सभी विभागों से मंजूरी लेगा.''

कोविड-19 के खिलाफ जंग

पर्यटन पर आधारित राज्य के रूप में, गोवा कोविड-19 की मार के खिलाफ संघर्ष करता नजर आया.

विकासशील देश बेसब्री से टीकों की प्रतीक्षा कर रहे थे, जितनी जल्दी हो सके अपनी अधिक से अधिक आबादी के टीकाकरण की भारत की कोशिश में गोवा भी शामिल हो गया. समाज के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कमजोर वर्गों के टीकाकरण से इसकी शुरुआत हुई.

जैसे-जैसे वैक्सीन का स्टॉक अधिक सहज रूप से उपलब्ध होता गया, राज्य सरकार ने लोगों को आगे आने और सरकारी तथा निजी केंद्रों में टीका लेने को प्रोत्साहित करने के लिए टीका उत्सव का आयोजन किया. राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. राजेंद्र बोरकर ने कहा, ''21 जून से, सभी पात्र लोगों का सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और 27 निजी अस्पतालों के माध्यम से सभी 42 सरकारी कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों और 198 सहयोगी केंद्रों में नि:शुल्क टीकाकरण किया जा रहा है.''

सितंबर, 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे पहले अपनी पात्र आबादी के 100 फीसद को टीके की पहली खुराक दिलाने वाला पहला राज्य बनने पर गोवा का बधाई दी थी. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत ने कहा कि सरकार का मकसद गोवा को जितनी जल्दी हो सके कोरोनावायरस-मुक्त राज्य घोषित करना है.

पारंपरिक पेशे को प्रोत्साहन

कृषि और मछली पकड़ना गोवा के दो पारंपरिक पेशे हैं. चावल, नारियल, काजू, गन्ना, अनन्नास और आम यहां की प्रमुख पैदावार हैं. इनमें से कई फसलों और पैदावार का प्रसंस्करण पड़ोसी राज्यों में होता है, और सरकार इन क्षेत्रों में और अधिक निवेश के बारे में विचार कर रही है.

महामारी के दौरान, इकोनॉमिक रिवाइवल

कमिटी ने सलाह दी है कि भंडार, बिक्री और पैकेजिंग प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए हर गांव में सामुदायिक बाजार के जोन निर्धारित हैं और वे तालुका बाजार से जुड़े हुए हैं. कुछ चुनिंदा फसलों के लिए मूल्य श्रृंखला को प्रोत्साहित करने के लिए एक क्लस्टर पद्धति को पेश किया गया है.

इस साल की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए बजट को पांच गुना बढ़ा दिया. राज्य में विकास को गति देने के लिए करीब 500 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और इससे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को लाभ मिलने की उम्मीद है. नारियल और काजू के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 2020-21 में क्रमश: 20 और 25 फीसद बढ़ाया गया है.

सुनिश्चित मूल्य फसल मुआवजा योजना, कामधेनु योजना, सामुदायिक डेयरी खेती योजना, पशुपालन योजना, डेयरी उपकरण योजना और चारा विकास योजना समेत कई योजनाएं गोवा में 40,000 से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा रही हैं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी हजारों लोगों का लाभ मिला है. इस योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये अतिरिक्त आमदनी प्रदान की जाती है. मछली पालन से जुड़े समुदाय को भी विभिन्न प्रकार की मदद दी जा रही है. इनमें मछलीपालन उपकरण की खरीद के लिए 5 लाख रूपये तक की सब्सिडी, मतस्यपालन फॉर्म स्थापित करने के लिए 50 फीसद सब्सिडी और अधिकतम 1,700 लीटर की खपत पर प्रति लीटर 30 रुपये की सब्सिडी शामिल है.

मत्स्य सेतु ऐप की शुरुआत, गोवा राज्य मारिकल्चर पॉलिसी और एलईडी फिशिंग पर प्रतिबंध के साथ-साथ इस साल एक मेगा फिश फेस्टिवल भी आयोजित किया गया.

भविष्य के लिए निवेश

राज्य सरकार का मकसद सभी बोर्डों में शिक्षा में सुधार करना है. ग्रामीण इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता बढ़ाने और निजी विश्वविद्यालयों के साथ गठजोड़ करके शिक्षा का केंद्र बनने की कोशिश कर रही है.

यह तकनीकी शिक्षा में भारी निवेश—कम से कम करोड़ रुपये—कर रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपायों को लागू करने की दिशा में काम कर रही है. उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण, प्रशिक्षण और ज्ञान के लिए वैश्विक स्तर की मशहूर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनियों के साथ साझेदारी के जरिये स्कूलों में कोडिंग और रोबोटिक्स के प्रशिक्षण को शामिल करने की मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सराहना की है.

पूरे गोवा के छात्रों को अध्ययन सामग्री, प्रश्न पत्र, अधिसूचना और परिपत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक ई-पोर्टल (डिशतावो या डीआइएसएचटीएवीओ) और राज्य बोर्ड ऐप लॉन्च किया गया है. युवा मन में रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. सावंत ने गोवा विज्ञान केंद्र में एक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है.

महामारी के दौरान, विभिन्न सुरक्षा उपायों के साथ अहम शैक्षणिक और प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गईं. इसके अलावा, राज्य ने उच्च शिक्षा निदेशालय के दायरे में आने वाले सभी कॉलेजों में शैक्षणिक प्रवेश के लिए ट्यूशन, जिमखाना और सांस्कृतिक शुल्क का आधा हिस्सा माफ कर दिया.

विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक, गोवा स्कूल-स्तर पर बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन के मामले में सर्वोच्च स्थान पर है. भारत की उच्च शिक्षा में लड़कियों के सबसे अच्छे अनुपात वाले राज्यों में गोवा शामिल है, और देश का तीसरा सबसे अच्छा छात्र-शिक्षक अनुपात इस राज्य में है.

स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाओं को विकसित करने, बेहतर स्वच्छता सुविधाओं और अनाथों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के लिए धन आवंटित किया गया है. सरकार राज्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का एक स्थायी कैंपस स्थापित करने के लिए भी काम कर रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी जो भारत में फोरेंसिक साइंस के एक नए युग की शुरुआत करेगा.

स्वयंपूर्ण गोवा

देश और उसके नागरिकों को खास तौर पर अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, प्रणालियों, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है. इस आह्वान से प्रेरित होकर गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सांवत ने अक्तूबर 2020 में स्वयंपूर्ण गोवा नामक पहल की शुरुआत की है. इसके तहत पंचायतों और नगर निकायों में विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई है.

इसका मकसद स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके राज्य के हर गांव को आत्मनिर्भर बनाना है. इस कार्ययोजना में कृषि, पशुपालन, पर्यटन, मत्स्यपालन और प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं. इसमें विभिन्न योजनाओं और उनके संयोजन के जरिये युवाओं और किशोरों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और स्वयंसहायता समूहों से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं.

फरवरी 2021 में, केंद्र सरकार ने गोवा की मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए. मुख्यमंत्री ने वादा किया कि वह गोवा में एक नीली अर्थव्यवस्था बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो गोवावासियों के लिए फायदेमंद है.

उन्होंने कहा, ‘‘आवंटित राशि का इस्तेमाल न केवल बुनियादी ढांचे के विकास, बल्कि स्वयंपूर्ण गोवा योजना के तहत मानव विकास के लिए भी किया जाएगा.’’ प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के अधिकारियों और कार्यक्रम के लाभार्थियों के साथ बातचीत की और उन्होंने मुख्यमंत्री की पहल की तारीफ की.

मोदी ने कहा, ‘‘गोवा ने कई कार्यक्रमों में 100 फीसद लक्ष्य हासिल कर लिया है. इसने हर घर में शत-प्रतिशत बिजली कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है. भारत ने खुले में शौच से मुक्त होने का लक्ष्य रखा. गोवा ने इस मुकाम पर को भी हासिल कर लिया है. हर घर जल अभियान के लक्ष्य को पूरा करने वाला गोवा पहला राज्य था. गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने में भी राज्य ने शत-प्रतिशत कामयाबी हासिल की है. गोवा में महिलाओं की योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है. राज्य में विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे से किसानों, पशुपालकों और मछुआरों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी. साल 2021 में, गोवा में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए फंड पिछले साल की तुलना में पांच गुना बढ़ा दिया गया है.’’

उन्होंने बताया कि नवोन्मेषी, संवेदनशील और जिम्मेदारी नौकरशाही के नतीजतन स्वयंपूर्ण गोवा पहल कामयाबी के दास्तान लिख रही है. उन्होंने कहा, ‘‘गोवा का मतलब प्रकृति और पर्यटन है, लेकिन अब इसका मतलब विकास का एक नया मॉडल और सामूहिक प्रयासों का प्रतिबिंब भी है.’’

व्यापक परिदृश्य

डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि वह बड़े शहरों में जाने में असक्षम दूरदराज के गांवों की दादियों, अपना गुजारा करने के लिए मदद की जरूरत वाली

विधवा माताओं और जरूरतमंद विकलांग लोगों के दुख को देखकर द्रवित हो गए. उनका मानना है कि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हाशिए पर खड़े हर जाति और धर्म के प्रत्येक आखिरी शख्स को इन पहलों का लाभ हासिल होगा.

उन्होंने कहा, ''योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया को तेज करने के लिए यह पहल शुरू की गई थी. गोवा में लोग गृह आधार (गृहिणियों के लिए), लाडली लक्ष्मी (बालिकाओं के लिए) और दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना (स्वास्थ्य के लिए) जैसी योजनाओं से अवगत हैं. लेकिन वे किसी और योजना के बारे में नहीं जानते. मैं चाहता हूं कि वे इन 150 योजनाओं के बारे में जानें और आवेदन करें. उनके और आवेदनों के बारे में जानकारी गोवाऑनलाइन वेब पोर्टल पर उपलब्ध है. हम सभी लोगों के लिए आवास, पानी, बिजली और बीमा समेत अपने सारे वादों को पूरा करना चाहते हैं. योजनाओं और सेवाओं के साथ-साथ, हम चाहते हैं कि लोग हमारे मॉडल करियर केंद्रों के जरिये रोजगार हासिल करें.''

यह किस तरह काम करता है

उच्च शिक्षा निदेशालय और गोवा लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से किए गए एक गहन अध्ययन ने गोवा की सभी 191 पंचायतों की ताकत, कमजोरियों, अवसरों और जोखिम को समझने में मदद की. इसने उपलब्ध संसाधनों और प्रतिभाओं की भी परखा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकते हैं.

निष्कर्षों ने यह संकेत दिया कि गोवा भले ही खेती के लिए भारत में सबसे अधिक सब्सिडी प्रदान करता है, लेकिन जागरूकता की कमी और प्रोत्साहन की कमी की वजह से युवा इस पेशे में आने से कतराते हैं.

गांवों और नगर पालिकाओं के निवासियों को एक तय दिन पर सरकारी प्रतिनिधियों के सामने अपनी शिकायतें रखने का मौका मिलता है. विभिन्न योजनाओं, सेवाओं और कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी उनके काउंटरों पर दी जाती है.

इस कार्यक्रम का मकसद सड़क, पानी की आपूर्ति, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं समेत गोवावासियों की नियमित समस्याओं का त्वरित समाधान प्रदान करना है. पूरे दिन राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आइडी कार्ड, किसान कार्ड, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, सिंचाई योजना और आदिवासी कल्याण योजनाओं पर लंबित आवेदनों और बकाया राशि पर कार्रवाई की जाएगी.

स्वयंपूर्ण गोवा पहल के जरिये उपलब्ध सेवाओं में गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से निवास प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, आय प्रमाणपत्र और लाभार्थी कार्ड जारी करना; दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना; गृह आधार; सामाजिक कल्याण योजनाएं; बिजली कनेक्शन और उससे जुड़े मामले; पानी के कनेक्शन; घरेलू शौचालय; भूमि का म्यूटेशन, विभाजन और परिवर्तन; कृषि कल्याण योजनाएं; बाल परियोजना विकास कल्याण योजनाएं; श्रम कल्याण योजनाएं और उससे जुड़े मामले; पशु चिकित्सा योजनाएं; लीड बैंक, अटल बीमा और क्रेडिट कार्ड सुविधाएं; और आदिवासी कल्याण, मत्स्य पालन, आर्थिक विकास निगम, जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए संबंधित योजनाएं शामिल हैं.

अब तक की प्रगति

अक्तूबर 2021 में लक्ष्य 10 प्रमुख लक्ष्यों को लेकर था. इनमें पानी और बिजली कनेक्शन, सभी परिवारों के लिए आश्रय और स्वच्छता, किसानों के लिए लाभार्थी कार्ड, विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मदद, साथ ही कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य, सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना शामिल है.

गोवा की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों, नगर निकायों और राज्य सरकार के अधिकारियों को 'स्वयंपूर्ण मित्र' नामक पुरस्कार प्रदान किया. इससे पहले उन्होंने स्वयंपूर्ण गोवा पहल के लाभार्थियों और हितधारकों के साथ बातचीत की थी और जानकारी हासिल की कि हजारों लोग पहले से ही इससे कैसे लाभान्वित हो रहे हैं.

पूरे गोवा के गांवों में, महिला सशक्तिकरण, मेडिकल इलाज का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों को लिए इसे उपलब्ध कराने, नि:शुल्क मेडिकल जांच, स्वयंसहायता समूहों को दिए गए प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करने, विकलांग लोगों और आदिवासियों को सहायता, टीकाकरण जागरूकता, किसानों और मछुआरों को सहयोग, लाभार्थी कार्ड, शौचालय की सुविधा, पानी और बिजली कनेक्शन, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, सौर ऊर्जा और यहां तक कि इको-पर्यटन को बढ़ावा देने की अगिनत कामयाब कहानियां भरी पड़ी हैं.

स्वयंपूर्ण गोवा पहल का दूसरा चरण अक्तूबर 2021 में शुरू हुआ और यह अक्तूबर 2022 तक चलेगा जब तीसरा चरण शुरू होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "स्वयंपूर्ण गोवा पहल पांच महीने या पांच साल का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अगले 25 वर्षों के विजन का पहला चरण है. इसके लिए सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए. पूरे राज्य के आशीर्वाद से हम स्वयंपूर्ण गोवा के लक्ष्य को पूरा करेंगे."

गोवा को मिले पुरस्कार और सम्मान

राज्यों की दशा-दिशा

- इंडिया टुडे की राज्यों की दशा-दिशा कॉनक्लेव 2020 में गोवा को लगातार तीसरे साल छोटे राज्यों में समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का खिताब मिला
- अर्थव्यवस्था, पर्यटन और इनफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया

बुनियादी ढांचा

- स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के तौर पर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने इसे खुले में शौच से मुक्त प्रमाणित किया

पर्यटन

- 2019 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य का पुरस्कार मिला
- पर्यटन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला
- भारत की पहल, विश्व यात्रा और पर्यटन काउंसिल की ओर से सुरक्षित यात्रा स्टॉम्प हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य

रोजगार

- 2019-20 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट में नवाचार को प्रोत्साहन प्रदान करने में भारत में पहला रैंक हासिल हुआ
- 2019-20 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट में नवोन्मेषी दृष्टिकोण के मामले में छठा रैंक हासिल किया

शिक्षा

- गोवा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित हुआ
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा की 40 फीसद सीटें गोवा के छात्र-छात्राओं के लिए आरक्षित हैं
- कानून-व्यवस्था
- सामुदायिक पुलिसिंग में उल्लेखनीय योगदान के लिए गोवा पुलिस को 2016 और 2018 में फिक्की का स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड मिला

बिहार / ओमिक्रॉन

सिर्फ 'ऑक्सीजन' के भरोसे कोविड की तीसरी लहर से जंग

कोविड की दूसरी लहर में किरकिरी के बावजूद बिहार के अस्पतालों के नहीं बदले हालात नए ऑक्सीजन प्लांट लग गए पर डॉक्टरों तथा अन्य इंतजामात की भारी कमी बरकरार है

पुष्यमित्र

पटना के बापू सभागार में 28 दिसंबर, 2021 को देश भर से आए चार से पांच हजार डॉक्टरों की भीड़ जुटी थी. मौका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय सम्मेलन का था. उस सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, ''बिहार में कोरोना की तीसरे लहर की शुरुआत हो चुकी है. इसके लिए राज्य सरकार ने अस्पतालों के संचालन से लेकर लोगों की मदद करने के लिए हर तरह की तैयारी की है. लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी चल रहा है और इन सबकी जिम्मेदारी आप डॉक्टरों पर है.''

मगर दुर्भाग्यवश उनके संबोधन के वक्त मंच पर मौजूद ज्यादातर डॉक्टरों ने मास्क तक नहीं पहने थे. ऑडिटोरियम खचाखच भरा था, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया था. इस लापरवाही ने आखिरकार अपना असर दिखाया. एक हफ्ते बाद जब यह खबर लिखी जा रही है, पटना के तीन सौ से अधिक डॉक्टर संक्रमण का शिकार हो चुके हैं. इनमें सबसे अधिक संख्या नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) के डॉक्टरों की है. वहां कुल 239 डॉक्टर संक्रमित हैं.

हालांकि एनएमसीएच के अधीक्षक डॉ. विनोद कुमार सिंह, जो खुद संक्रमित हो चुके हैं, नहीं मानते कि उनके यहां के डॉक्टर आइएमए सम्मेलन की वजह से संक्रमित हुए हैं. उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस में सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्टर ही शामिल हुए थे. ऐसे संक्रमित डॉक्टरों की संख्या 20-25 ही है. ज्यादातर संक्रमित मेडिकल स्टूडेंट हैं. आइएमए, पटना के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार भी कहते हैं, ''जितने डॉक्टर संक्रमित हैं, उनमें से बीस फीसदी भी हमारे कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे. हम लोग आयोजक थे, हमें कोई इंफैक्शन नहीं हुआ.'' मगर एनएमसीएच के हॉस्टल में मौजूद एक इंटर्न ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जितने भी छात्र संक्रमित हुए हैं, उनमें ज्यादातर उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे.

मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और देश भर से आए आइएमए पदाधिकारियों की मौजूदगी में पटना में हुई यह लापरवाही बताती है कि बिहार कोविड की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए कितना सजग है. दुखद तथ्य यह है कि इस आयोजन से 13 दिन पहले कर्नाटक

नहीं बदले हालात

1 कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री के साथ आइएमए के पदाधिकारी बगैर मास्क के
2 सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर का आइसीयू, वेंटिलेटर तो है मगर पन्नी उतरी नहीं

हाइकोर्ट ने वहां हो रहे डॉक्टरों के कांफ्रेंस निओकॉन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे. भाग लेने वालों की संख्या तीन हजार से घटाकर 305 कर दी और सभी का आरटी-पीसीआर टेस्ट और वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया. मगर बिहार में चार-पांच हजार लोगों की भीड़ बिना किसी ऐहतियात के जुट गई.

राज्य में अचानक कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं. सक्रिय मरीजों की संख्या चार हजार के करीब पहुंच गई है. इसमें ओमिक्रॉन के एक ही मरीज की पुष्टि हुई है, मगर इसके लिए बहुत कम सैंपल (पांच सौ से भी कम) जांचे भी गए हैं. स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के मुताबिक राज्य में फिलहाल एक ही जगह आइजीआइएमएस में ओमिक्रॉन की जांच हो रही है. हर सैंपल की ओमिक्रॉन जांच मुमकिन नहीं है. हालांकि राज्य सरकार सभी तरह की तैयारियों का दावा कर रही है और ऐसा जता रही है कि इस बार उसकी तैयारी पुख्ता है. पर्याप्त ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर उपलब्ध हैं. (देखें *बॉक्स*)

नहीं सुधरे हालात

पटना से सिर्फ 50 किमी दूर सदर अस्पताल, आरा में पहुंचते ही पता चल जाता है कि तैयारी कैसी है. अस्पताल में ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं थे. इनमें रोगी और परिजन ही नहीं, अस्पताल के कर्मी और अधिकारी भी शामिल थे. अस्पताल प्रबंधक बिना मास्क लगाए 12 बजे अस्पताल पहुंचे थे, वह भी फोन से बुलाए जाने पर. जबकि सुबह दस बजे से उनके दफ्तर के आगे मुलाकातियों की भीड़ थी. सिविल सर्जन रामप्रीत सिंह भी छुट्टी पर थे. चार्ज एडीशनल सीएमओ केएन सिंह के पास थे, मगर वे भी कहीं गए हैं. डीपीएमओ भी गैर-हाजिर थे. भोजपुर जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला बिना किसी सेनापति के चल रहा था.

12 बजे पहुंचे अस्पताल प्रबंधक कौशल कुमार दुबे ने अस्पताल का कोविड वार्ड दिखाया. वह चार अलग-अलग कमरों में 15-15-15 और 20 बेड का था. हालांकि पहले दो कमरे में इमरजेंसी वार्ड के मरीज भर्ती थे, तीसरे में नशामुक्ति केंद्र चल रहा था और चौथे में तीन बेड अस्त-व्यस्त तरीके से पड़े थे, जैसे स्टोर रूम हो. प्रबंधक बोले, इमरजेंसी वार्ड को दस जनवरी को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा. नशामुक्ति वार्ड आज खाली हो जाएगा और चौथे कमरे को जल्द तैयार कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अस्पताल में तीन वेंटिलेटर भी हैं, मगर उनके हिसाब से वे एक कमरे में बंद थे, जिसकी चाबी उनके पास नहीं थी. अस्पताल में एक ही चीज सकारात्मक दिखी, वह एक हजार लीटर प्रति मिनट का ऑक्सीजन प्लांट था, जिसकी पाइप लाइन हर जगह बिछी थी.

कोविड की दूसरी लहर में इसी अस्पताल की अव्यवस्था की तसवीरें और वीडियो वायरल हुए थे. खासकर स्थानीय विधायक मनोज मंजिल की वह तसवीर वायरल, जिसमें वे लगातार अस्पताल परिसर में बैठकर मरीजों की मदद कर रहे थे. फोन पर उन्होंने बताया कि यहां आज तक आइसीयू चालू नहीं हो पाया है. न 24 घंटे ईसीजी की सुविधा है, न ब्लड बैंक की. कोविड को लेकर सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट बिठा दिया गया है, दूसरी चीजें जस की तस हैं. दिलचस्प है कि इस अस्पताल को लगभग दस साल पहले आइएसओ सर्टिफिकेट मिला था. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय इसी जिले के प्रभारी मंत्री हैं, भोजपुर के सांसद केंद्र में मंत्री हैं. तब इस सदर अस्पताल का ऐसा हाल है.

फर्श पर मरीजों का इलाज

मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल के पुरुष वार्ड में एक 25 वर्षीय महिला रोगी अनिष्का शाह एडमिट थीं, जो दरअसल आइसोलेशन वार्ड की मरीज थीं. कोविड संदिग्ध होने की वजह से उन्हें दूसरे मरीजों से अलग रखा जाना चाहिए था. ड्यूटी पर मौजूद इकलौती स्टाफ नर्स ने कहा, ''हम क्या करें. उसे यहां भेज दिया गया तो हमें रखना ही पड़ेगा.'' गनीमत ये थी कि उन्हें कोविड नहीं, कोल्ड डायरिया हुआ था. उस अस्पताल में चार बेड का एक आइसीयू था, उसमें वेंटीलेटर तो दिखा, मगर उस वक्त तक उसके ऊपर से पोलिथीन पैकेज को हटाया नहीं गया था. अस्पताल प्रबंधक विपिन ने बताया कहने को अस्पताल में 30 डॉक्टर हैं, मगर हमें नियमित 17-18 डॉक्टरों की ही सेवा मिल पाती है, नर्स भी सिर्फ 40 हैं. ज्यादातर मरीज प्रसव के लिए आते हैं, मगर महिला रोग विशेषज्ञ एक ही है, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ एक भी नहीं है, बाहर से कॉल पर बुलाना पड़ता है. ड्रेसर के भी सभी पद खाली हैं.

मुजफ्फरपुर शहर में एक मेडिकल कॉलेज भी है, श्रीकृष्ण मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल. चमकी बुखार की वजह से यह अस्पताल हमेशा चर्चा में रहता है. वहां मरीजों की जबरदस्त भीड़ थी मगर मास्क लगाये लोग कम ही दिखे. ओपीडी में लंबी कतारें थीं, इमरजेंसी वार्ड के मरीज खुले गलियारों में बेड और फर्श पर लेटे इलाज कराते नजर आये. इनमें गंभीर मरीज भी थे. मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट बाबूसाहेब झा ने बताया, हमारी मजबूरी है. यहां सिर्फ 907 बेड हैं, मगर हमेशा 1100 से 1200 मरीज भर्ती रहते हैं. लिहाजा गलियारे में भी जहां-जहां जगह होती है, हमें बेड लगाना पड़ता है.

गया में सबसे ज्यादा केस

कोविड की इस लहर में पटना के बाद सबसे अधिक मरीज गया जिले से मिल रहे हैं. मंगलवार तक वहां 565 सक्रिय मरीज थे. गया शहर में 53 माइक्रो कंटोनमेंट जोन बने हैं, हालांकि ये जोन कहने को हैं. रामधनपुर मोहल्ले में तीन कंटोनमेंट जोन बने और अखबारों में तसवीरें भी छपी थीं. मगर वहां बैरिकेडिंग कहीं नजर नहीं आ रही थी. एक मरीज के घर छोटा सा पोस्टर चिपका था. पड़ोसियों ने कहा कि लोगों ने खुद बैरिकेट हटा लिए हैं. वे सारा काम खुद ही बाहर निकल कर रहे हैं.

पूरे जिले में एक ही मरीज शहर के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज

बिहार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर

तीसरी लहर के लिए सरकारी तैयारी

ऑक्सीजन युक्त बेड	12000
जिला अस्पतालों में आइसीयू बेड	455
अनुमंडल अस्पतालों में आइसीयू बेड	266
निजी अस्पताल कोविड के इलाज के लिए	550
ओमिक्रॉन की जांच के लिए जीनोम लैब- (आइजीआइएमएस, पटना)	01

(बुधवार, 5 जनवरी 2022 को स्वास्थ्य विभाग ने मीडिया को बताया)

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी

डाक्टर	
स्वीकृत पद-	11645
पद रिक्त (सामान्य चिकित्सक)	3206
पद रिक्त विशेषज्ञ चिकित्सक	4149
कुल खाली पद	7355
स्वास्थ्य कर्मी	
पद सृजित	91921
पद खाली	46256

(अप्रैल, 2021 में बिहार सरकार ने पटना हाइकोर्ट को) जानकारी दी. उसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं)

के 130 बेड के कोविड वार्ड की तीसरी मंजिल पर भर्ती था. इसी कोविड वार्ड में पिछले साल एक महिला मरीज के साथ रेप की घटना हुई थी.

वहां मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट प्रदीप कुमार अग्रवाल ने तीन ऑक्सीजन प्लांट और 700 से अधिक ऑक्सीजन बेड को दिखाकर कहा कि तैयारी पुख्ता है. उन्होंने अस्पताल में 76 वेंटिलेटर और 264 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होने की भी जानकारी दी. मगर यह स्वीकार किया कि मैनपावर की कमी है. डॉक्टरों की संख्या 30 फीसद कम है, टेक्नीशियनों की भी कमी है. गया के सिविल सर्जन के.के. राय ने भी मैनपावर के कमी की बात स्वीकार की. उनके मुताबिक जिले में 50 से 60 फीसद डॉक्टरों से ही काम चल रहा है. मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन ऑफिस से मिली सूची के मुताबिक, डॉक्टरों के 601 स्वीकृत पदों में से 391 डॉक्टर ही हैं. वहां तीन सरकारी अस्पतालों में कोई नियमित चिकित्सक नहीं है.

डॉक्टरों का संकट बरकार

यह सच है कि राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर काफी काम किया है. मेडिकल कॉलेजों, सदर अस्पतालों और अनुमंडल स्तरीय अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट बने हैं और दिसंबर महीने में उनका मॉक ड्रिल भी कराया गया है. कई जिलों में कोविड वार्ड बने हैं. बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्य में 12 हजार ऑक्सीजन बेड तैयार हैं. वेंटिलेटर की उपलब्धता पर भी काम किया गया है. मगर जमीनी हकीकत यही है कि राज्य के अस्पतालों में मैनपावर का जबरदस्त संकट है. जो तीसरी लहर तेज होने पर बड़ी मुसीबत बन सकता है.

यहां डाक्टरों की संख्या कितनी कम है, इसका अंदाजा बिहार सरकार के उप सचिव शैलेष कुमार की 24 मई, 2021 को महालेखाकार को लिखी चिट्ठी से पता चलता है. वे लिखते हैं, ''डब्लूएचओ के मुताबिक हर एक हजार की आबादी पर एक चिकित्सक होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर औसत 1456 मरीज पर एक डॉक्टर का है, जबकि बिहार में एक डॉक्टर पर 28,391 लोगों का बोझ है.'' अप्रैल, 2021 में जब बिहार में कोविड की की वजह से स्थितियां बेलगाम हो गई थीं, तब पटना हाइकोर्ट इस मसले पर रोजाना सुनवाई कर रहा था. उसी दौरान स्वास्थ्य विभाग ने हाइकोर्ट को बताया था कि राज्य में सामान्य चिकित्सक के लगभग साठ फीसदी पद खाली हैं. बाद में जब इस मुद्दे पर सरकार की खूब फजीहत हुई तो डॉक्टरों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए 6338 स्थायी और 1000 अस्थायी पदों की नियुक्तियां निकाली गईं. उन नियुक्तियों के जरिए अब तक कितने डॉक्टर बिहार के सरकारी अस्पतालों को मिले, यह आंकड़ा उपलब्ध नहीं है.

इंडिया टुडे ने यह आंकड़ा जानने के लिए स्वास्थ्य विभाग में एक मेल और उसके दो रिमाइंडर भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. स्वास्थ्य मंत्री से बात करने की भी लगातार कोशिश की गई, मगर उनसे वक्त नहीं मिला. हालांकि बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संवाददाता ने अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से यह सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैनपावर बड़ा मसला नहीं है. हमारा फोकस ऑक्सीजन बेड पर है. हालांकि पिछली लहर के मुकाबले इस बार डॉक्टर और नर्स बढ़े हैं. मगर उन्होंने सटीक संख्या नहीं बताई.

न पर्याप्त नर्स हैं, न स्टाफ

स्वास्थ्य विभाग ने पटना हाइकोर्ट को यह भी बताया था कि स्वास्थ्य कर्मियों के भी आधे से अधिक पद खाली हैं. उन पदों को भी भरने की बात हुई, मगर कितने लोग बहाल हो पाए, यह बताने के लिए कोई तैयार नहीं. इस संबध में भी मुजफ्फरपुर जिले के आंकड़े हमारी समझ बढ़ाते हैं. जिले में नर्सिंग स्टाफ के 398 पदों के बदले सिर्फ 176 कार्यरत हैं. सपोर्टिंग स्टाफ के 1178 पद हैं, जिनमें फिलहाल 481 कार्यरत हैं. ऐसी स्थिति लगभग हर जिले की है. इसलिए कोविड से मुकाबले की तैयारी के संदर्भ में सरकार बेड, ऑक्सीजन और वेंटीलेटर की बात ही करती है, मैनपावर के मसले को गायब कर जाती है.

राज्य सरकार इस बात को भले न समझे मगर नीति आयोग ने पिछले दिनों देश के जिला अस्पतालों की स्थिति पर जारी रिपोर्ट में लिखा है कि जब तक अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ नहीं होंगे, कर्मियों की ड्यूटी शिफ्टवार तरीके से ठीक से नहीं लगेगी, सभी 14 तरह की जांचों की सुविधा नहीं होगी, सपोर्ट सेवाएं नहीं होंगी और मेडिकल उपकरणों की नियमित देखभाल नहीं होगी तब तक अस्पतालों की हालत नहीं सुधरेगी. मगर बिहार सरकार का स्वास्थ्य महकमा मानता है कि बेड पर ऑक्सीजन पहुंचा देने से उसकी तैयारी पूरी हो गई है. बाकी सब राम के भरोसे है. ■

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

उम्मीद की डोर

एक महीना कितना उलटफेर कर देता है. अप्रैल में इसके दिखाए बदतरीन वक्त को पीछे छोड़कर नवंबर 2021 की शुरुआत में हम भूलने और मौज-मस्ती के साथ छुट्टियां मनाने के मौसम की तरफ बढ़ रहे थे. सामन्य हालात नहीं भी तो कम से कम 'न्यू नॉर्मल' (नया सामान्य) आने वाले साल का सूत्रवाक्य लगता था. वह और 'मकामी खूबी'. तभी 26 नवंबर को हमें ज्यादा बड़ा सूत्र मिलाः ओमिक्रॉन.

हमारे नववर्ष विशेषांक के चौदह निबंध उम्मीद और सतर्कता का संतुलन होने जा रहे थे, लेकिन आप देखेंगे कि वे दिसंबर की संततियां हैं—गंभीर, अगर निराशाजनक न भी हों, उनका आशावाद सतर्कता से सहेजी गई स्मृति है. हमारे अर्थशास्त्री रुकावटों और नई चुनौतियों से आगाह कर रहे हैं, हमारे प्रतिष्ठित महामारी विशेषज्ञ शाश्वत सतर्कता की सलाह दे रहे हैं और हमारे भूराजनैतिक विशेषज्ञ दुनिया के अनिश्चितताओं से भरा होने का वायदा कर रहे हैं. भारतीय राजनीति बेशक अपने आप में एक दुनिया है, ऐसी दुनिया, जिसमें इस साल हम उम्मीद कर सकते हैं कि एकाधिक राज्यों के चुनावों में मौजूदा संकट के कांटे में चुनावी अवसरों को फंसाया जाएगा. यह 2024 के आम चुनाव का ट्रेलर बन सकता है. सच तो यह है कि हमारे लेखक ज्यादातर दूसरों के मुकाबले महामारी से कम मायूस मालूम देते हैं. उनकी नजरें वैश्विक भारतीय प्रवासी समुदाय के दीर्घकालिक उभार पर टिकी हैं या वे तेजी से नए डिजिटल मोड़ की तरफ ले जाने वाली हमारी कामकाजी दिनचर्या में उथल-पुथल का स्वागत कर रहे हैं. हमारी जलवायु परिवर्तन भविष्यवक्ता तो कोविड संकट का कतई जिक्र ही नहीं करतीं, बल्कि अपने 'सामान्य कामकाज' के आह्वान में वे यह सुझाव देती हैं कि अगर महामारी 'पर्यावरण के लिए अच्छी' वाकई नहीं रही तो भी इसने हमें अपनी प्राथमिकताओं के बारे में ठहरकर सोचने का वक्त दिया है, जिसके बारे में नए साल में जरूर सोचा जाएगा.

राज चेंगप्पा

चुनौतियां का चतुष्कोण

भारत को 2022 में जिन इम्तहानों से गुजरना है, उनमें राजनीतिज्ञ मोदी नहीं बल्कि राजनेता मोदी की जरूरत है

साल 2022 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनौतियों के चतुष्कोण से दोचार हैं, जिसमें उनके नेतृत्व कौशल और राजकाज का कड़ा इम्तहान होगा: कोविड की तीसरी लहर पर काबू पाना, पांच विधानसभाओं के चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाना, देश की तहस-नहस अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकना और आक्रामक चीन से निपटना. लड़ाई के लिए हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री को उस भारतीय बाजीगर की तरह महसूस करना होगा जिसके बारे में 19वीं सदी के अंग्रेजी निबंधकार विलियम हैजलिट ने एक लेख में लिखा था: ''एक सेकंड से भी कम वक्त में एक के बाद चार गेंदें पकड़ना और उन्हें इस तरह लौटाना ताकि वे आभासी चेतना के साथ हाथ में वापस आ सकें, निश्चित अंतरालों पर उन्हें गोल-गोल घुमाना, जैसे ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं, वह करना जो असंभव दिखाई देता है... समय के छोटे से छोटे कल्पनीय क्षण की बाल बराबर चूक भी जानलेवा हो सकती है.''

मोदी जिन चार चुनौतियों से दोचार हैं, वे आपस में गहराई से जुड़ी हैं. उनसे निपटने के लिए उन्हें जादूगर सरीखी निपुणता, तालमेल, तत्क्षण प्रतिक्रिया, सभी आयामों के प्रति जागरूकता, रणनीतिक सोच-विचार और एकाग्रता की दरकार होगी. कोविड-19 के ओमिक्रॉन रूप के फटाफट फैलाव को ही लीजिए. इसने तब धावा बोला जब भारत अपने विशाल टीकाकरण अभियान की प्रगति से गदगद था और 2021 की दूसरी लहर के दुस्वप्न को पीछे छोड़ आया लगता था. कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन 'वैक्सीनों की वैक्सीन' है—हल्की और फिर भी कहीं ज्यादा व्यापक रूप से फैलने वाली संक्रामक बीमारी, जो इसे दुनिया भर में हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने का आदर्श साधन बना सकती है. लेकिन जरा भी आत्मसंतुष्ट रहना नादानी होगी क्योंकि मामलों की भारी तादाद भर स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को चरमरा सकती है. नए खतरे को समझते हुए मोदी ने 15 से 18 के बीच की उम्र के 14 करोड़ भारतीयों किशोरों को टीके लगाने की शुरुआत कर दी. साथ ही, दोनों टीके लगवा चुके पर दूसरी बीमारियों से ग्रस्त 65 से ऊपर के उन लोगों को भी बूस्टर डोज लगेगी. मोदी सरकार को अब यह जरूर पक्का करना चाहिए कि राज्य संक्रमण दरों को धीमा करने के कदम उठाएं और इलाज के लिए पर्याप्त बिस्तरों, दवाइयों और ऑक्सीजन से लैस हों. इस बीच और भी छोटी उम्र के बच्चों की कई संभावित वैक्सीन को फास्ट-ट्रैक पर डालने की जरूरत है, ताकि अंततः देश की पूरी आबादी को टीके लग सकें.

ओमिक्रॉन से जिस तरह निपटा जाता है, उसी से तय होगा कि प्रधानमंत्री बाकी तीन गेंद कितनी अच्छी तरह उछाल सकते हैं. यह समझने के लिए बहुत अक्ल की जरूरत नहीं कि राजनीति में उत्तर प्रदेश बेशकीमती है. मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए दो टूक बहुमत के साथ इस राज्य को जीतना वह कुंजी है जिसके बल पर वे

इलस्ट्रेशनः **नीलांजन दास**

तीसरे कार्यकाल के अभियान को गति दे पाएंगे और दूसरे कार्यकाल के उत्तरार्द्ध में बेधड़क हुकूमत कर पाएंगे. अपनी पार्टी को विधानसभा चुनाव जिताने में मदद का मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड 2018 के बाद अच्छा नहीं रहा है. 2021 की गर्मियों में असम और एक साल पहले बिहार की सीमित जीत को छोड़ दें तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हाल में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल की हार भाजपा के तुरुप के पत्ते के छीजते प्रतिफल की तरफ इशारा करती हैं. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सत्ता बनाए रखना भाजपा के लिए बेहद जरूरी है और उतना ही जरूरी पंजाब में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में आने से रोकना भी है ताकि उसे फिर उठ खड़ा होने से रोक सके.

राजनैतिक मोर्चे पर मोदी को और भी कई मुश्किल फैसले लेने हैं. चुनाव में जा रहे राज्यों में भीड़-भरी राजनैतिक रैलियां कोविड के मामलों में विस्फोट का सबब होंगी. प्रधानमंत्री के नाते भाजपा के पक्ष में उनके प्रचार अभियान को सावधानी और सतर्कता का आदर्श कायम करना चाहिए, जिसका अनुसरण दूसरे भी करें. फिर 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव की हार से साबित हो चुका है कि किसी भी कीमत पर जीतने की खातिर ध्रुवीकरण में जोर लगाने के पार्टी और उसके प्रधान प्रचारक के लिए नुक्सानदेह नतीजे हो सकते हैं. हिंदुत्व का उग्र धड़ा पहले ही अपने आक्रामक तेवर दिखा रहा है, जैसा कि हाल में उत्तराखंड की धर्म संसद में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ भाषणों में देखा गया. समुदायों के बीच मौजूदा फूट को तीखा करने वाला चुनाव अभियान न केवल पंजाब के चुनाव नतीजों पर प्रतिकूल असर डाल सकता है बल्कि लंबे समय की दरारें पैदा कर सकता है. टूट-फूट से ग्रस्त पंजाब भारत गवारा नहीं कर सकता क्योंकि अफगानिस्तान में अपनी कामयाबी से दुस्साहसी हो उठा पाकिस्तान इस सरहदी राज्य में उग्रवादी तत्वों को फिर जिंदा करने का मौका ताड़ रहा है. यही चेतावनी जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होती है जहां मोदी सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 रद्द करके राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था. घाटी में अलगाव की भावना को खत्म करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा नैतिक आधार दोबारा हासिल करने के लिए भी 2022 में विधानसभा चुनाव करवाने चाहिए.

राजनैतिक लड़ाइयां लड़ते हुए भी प्रधानमंत्री जानते ही हैं कि 2021 के बाद के आधे साल में अर्थव्यवस्था की बहाली फिर जहां की तहां आने लगी. बढ़ती महंगाई और खासकर अनौपचारिक क्षेत्र में बेरोजगारी की प्रेतछायाएं ओमिक्रॉन से धुंधली रोशनी में और भी मनहूस ढंग से चमकेंगी. इसका असर खास तौर पर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने कोविड की पिछली लहरों के दौरान छोटे और बहुत छोटे उद्यमों पर ताले पड़ने के वक्त नौकरियां गंवा दी थीं. उधर कृषि कानूनों के मामले में मोदी के पीछे हटने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया को तेज करना सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है. मसलन, किसान आंदोलन की देखा-देखी, मजदूर संगठनों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वे नए श्रम कानूनों पर अमल के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए.

2022 वह साल है जब मोदी को मुंह ताक रही असाधारण चुनौतियों से निपटने के लिए विपक्ष के पास जाना चाहिए और एकता के लिए संवाद शुरू करना चाहिए

2022 में मोदी सरकार का फोकस तेज रफ्तार आर्थिक वृद्धि पर अवश्य कायम रहना चाहिए ताकि नौकरियां दी जा सकें और जनकल्याण तथा बुनियादी ढांचे के योजनाओं के लिए जरूरी राजस्व बढ़ाया जा सके. लेकिन, वित्त मंत्रालय के एक बड़े अफसर के शब्दों में कहें, तो ''कोई आसान समाधान नहीं हैं.'' छोटे और बहुत छोटे उद्यमों में नई जान फूंकने के लिए वित्तीय सहायता के अलावा, विशेषज्ञों के मुताबिक, मौजूदा वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को पांच के बजाय तीन स्लैब में घटाकर और तर्कसंगत बनाया जा सकता है और टर्नओवर सीमा बढ़ाकर और ज्यादा छोटे कारोबारों को छूट दी जा सकती है. इससे प्रक्रिया सरल होगी, अनुपालन बढ़ेगा और करचोरी कम होगी. इस बीच केंद्र सरकार को बेरोजगार शहरी कामगारों के लिए सुरक्षा जाल लाना पड़ सकता है. एक तरीका यह हो सकता है कि मनरेगा की तर्ज पर शहरी बेरोजगार योजना लाई जाए.

मोदी सरकार ने 2021 के बजट में राजकोषीय घाटे की जिस राह का वायदा किया था, उसे कायम रखते हुए बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत खर्च कम नहीं करना चाहिए. बैंकों और केंद्र सरकार के उपक्रमों का निजीकरण आगे बढ़ना चाहिए ताकि सरकार नकदी संकट से बच सके. यह भी महत्वपूर्ण है कि पूंजी निवेश का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र से आए, जिसमें पिछले साल अर्थव्यवस्था के उबरने के बाद विस्तार की तीव्र इच्छा दिखाई दी. 13 क्षेत्रों की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन लाभ योजनाओं से मदद मिलनी चाहिए. हाल ही में खुले खनन, अंतरिक्ष और प्रतिरक्षा सरीखे क्षेत्रों के लिए नियामकीय लाल फीते भी काटने होंगे.

मोदी को 2022 में जिस चौथी गेंद को हुनर और बाजीगरी से संभालना होगा, वह है विदेश नीति, खासकर आक्रामक चीन से उत्पन्न खतरों और अवसरों से जुड़ी नीति. चीन को काबू करना भारत और अमेरिका का साझा उद्देश्य है. 2021 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्वाड की प्रक्रिया को पुख्ता किया. मगर उनमें भारत अकेला है जो चीन के साथ अनसुलझी सरहद साझा करता है और 2022 में मोदी सरकार को ऐसी रणनीतियां और व्यूह रचनाएं विकसित करनी होंगी जिनसे चीन को आगे किसी भी सामरिक दुस्साहस से भयपूर्वक रोका जा सके. काबुल में तालिबान की वापसी से उत्पन्न अपनी चुनौतियां हैं—आतंकवाद उनमें नहीं है—खासकर तब जब इससे चीन-पाकिस्तान की मौजूदा साठगांठ को पहले ही रणनीतिक गहराई मिल गई है. दूसरी तरफ, चीन और पश्चिम के बीच बढ़ते गतिरोध में भारत के लिए वैकल्पिक सप्लाई चेन नेटवर्क का हिस्सा बनने और निर्यात बढ़ाने का आर्थिक मौका है. इसके लिए भारत को बड़े व्यापार समझौतों को लेकर अपने प्रतिरोध की नए सिरे से जांच करनी होगी.

सबसे बढ़कर, 2022 में देश के सामने मौजूद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए शिखर पर राजनीतिज्ञ मोदी नहीं बल्कि राजनेता मोदी की जरूरत है. देश की प्रगति पर प्रतिकूल असर डाल रही राजनैतिक गर्मागर्मी को कम करने की तीव्र जरूरत है, चाहे वह सत्तारूढ़ पार्टी का उग्र राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण हो या विपक्ष का अड़ियलपन और नकारात्मकता. यह वह साल है जब मोदी को 2022 में मुंह ताक रही असाधारण चुनौतियों से निपटने के लिए विपक्ष के पास जाना और एकता के लिए संवाद शुरू करना चाहिए. एक बार फिर हैजलिट के शब्दों मे, ''महानता महान प्रभाव उत्पन्न करने वाली महाशक्ति है.'' मोदी के पास अब भी महाशक्ति है. 2022 में उन्हें इसका प्रयोग बुद्धिमानी से और बेहतर भलाई के लिए करना चाहिए. ■

देश का नं. 1
हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

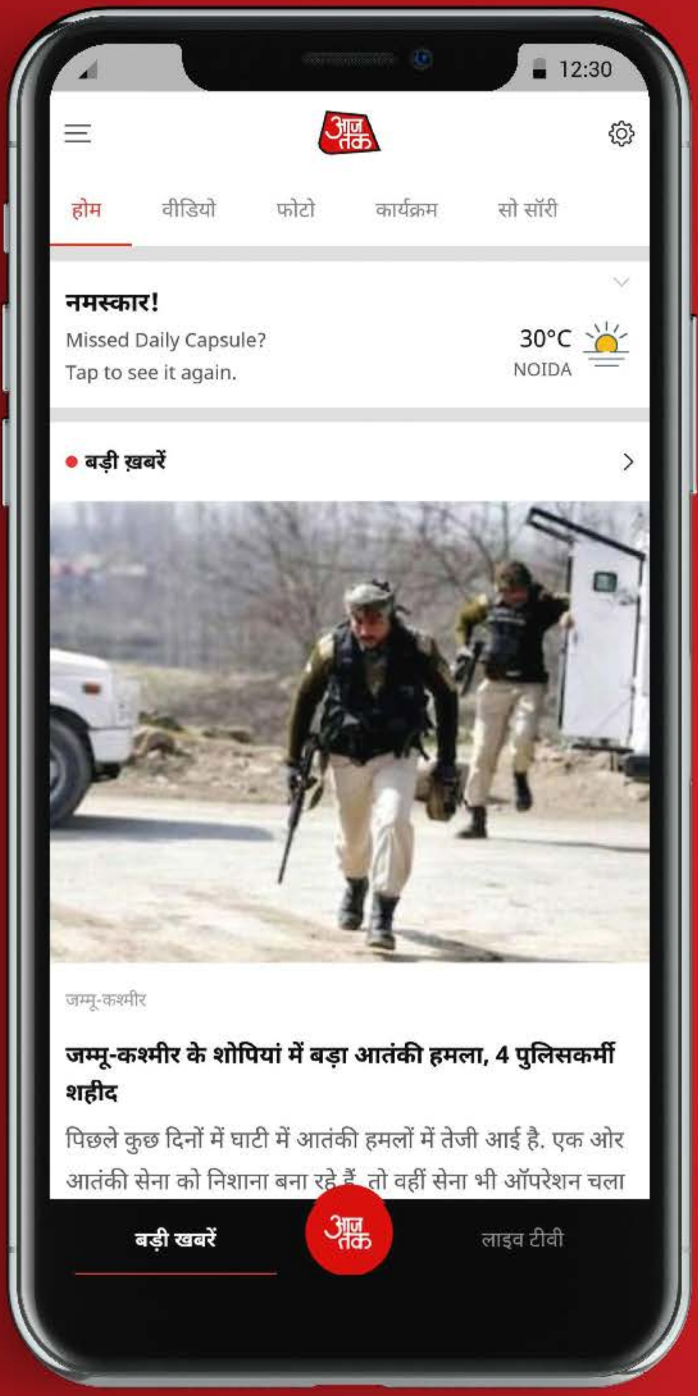

12:30

होम वीडियो फोटो कार्यक्रम सो सॉरी

नमस्कार!
Missed Daily Capsule?
Tap to see it again.

30°C
NOIDA

बड़ी ख़बरें

जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में बड़ा आतंकी हमला, 4 पुलिसकर्मी शहीद

पिछले कुछ दिनों में घाटी में आतंकी हमलों में तेजी आई है. एक ओर आतंकी सेना को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं सेना भी ऑपरेशन चला

बड़ी खबरें लाइव टीवी

गगनदीप कंग

कोविड-19

क्या 2022 कोविड से राहत दिलाएगा?

ओमिक्रॉन ने हमें दिखाया है कि कोविड के नए स्ट्रेन अभी भी उभर रहे हैं. अगर हमें वायरस को हराना है तो नियंत्रण की कोशिशों में सबसे आगे विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य को रखना होगा और उनके लिए एक सक्षम नीति भी दरकार है

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

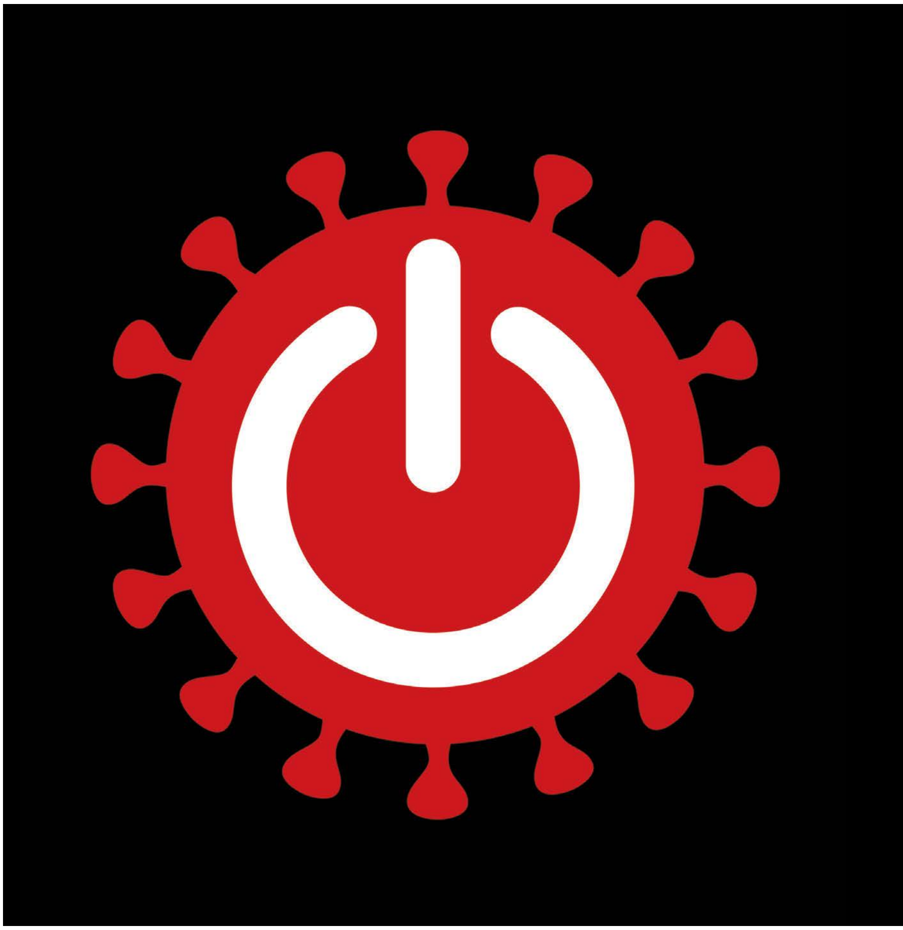

साल 2021 का आगाज शानदार तरीके से हुआ था—भारत में कोविड के कम होते मामलों और टीकों के वादे के साथ. उस समय ब्रिटिश वैरिएंट (जिसे अब अल्फा कहा जाता है) का खतरा छाया हुआ था और ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था. भारत की टीके की कहानी आगे बढ़ रही थी, हालांकि यह पहले से साफ था कि अग्रणी निर्माताओं की ओर से पेश किए गए खुराकों की संख्या और समय के सुहाने अनुमान पूरे नहीं होने वाले थे. यह साल के आखिर में साफ नजर आया और टीकाकरण में धीमी वृद्धि हुई तथा 2021 के पहले छह महीनों में खुराकों को हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा. खरीद और दान के रूप में खुराकों के शुरुआती बंटवारे के बाद, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने टीके के निर्यात को रोक दिया. फरवरी के उत्तरार्ध में कोविड मामलों में वृद्धि हुई और फिर अगले दो महीनों में तो इसका विस्फोट ही हो गया.

अब, यह सब साफ नजर आता है. एक नया वैरिएंट, धीमा टीकाकरण तथा स्थानीय और लंबी दूरी की यात्रा समेत लोगों के जमावड़े ने खासकर उत्तर भारत में कमजोर स्वास्थ्य प्रणालियों को तबाह करने के लिए पूरा तूफान पैदा कर दिया. जांची-परखी दवा के अभाव में सब कुछ इस्तेमाल करने की हताशा ने भारत में ब्लैक फंगस की दूसरी महामारी पैदा कर दी. ब्लैक फंगस भारत के लिए असाधारण है और चेतावनी है कि हद से ज्यादा इलाज के बुरे नतीजे भी निकलते हैं. अभी भी इस बात पर विवाद है कि कितने लोग मारे गए, लेकिन कई राज्यों में इसे कम करके बताए जाने की संभावना है. पहले ही आर्थिक नुक्सान और

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

9:41
INDIA TODAY
LIVE
TOP NEWS
VIDEOS
PROGRAMMES
TOP STORIES

LOK SABHA 2019

Narendra Modi Live: By Congress-mukt India we will fulfil Gandhi's dream

PM Narendra Modi was speaking in Lok Sabha

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

सामाजिक व्यवधानों से जूझ रहे परिवारों को अस्पतालों में बिस्तर और मदद पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा. घटते मामलों और टीके की आपूर्ति पर एक तर्कहीन फैसले के पलटे जाने के साथ, जून की शुरुआत तक हम बेहतर स्थिति में थे. लेकिन बाकी दुनिया के लिए, डेल्टा की उनकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी.

सार्स-कोविड2 महामारी से कैसे निपटा जाएगा, इसका पैटर्न 2020 में तैयार हो चुका था. जिन अमीर देशों में टीकों के निर्माण की क्षमता थी उन्होंने टीकों के विकास और परीक्षण में अपने संसाधनों को झोंक दिए. और, जिन अमीर देशों में यह क्षमता नहीं थी, उन्होंने अप्रमाणित टीकों की खुराकों को भी जमा करना शुरू कर दिया. उनका दांव कामयाब रहा. नए और पुराने प्लेटफॉर्मों ने बेहतर काम किया, और टीकों को विकसित करना आसान था (भले उनका निर्माण आसान नहीं हो) और प्लेटफॉर्म के आधार पर शानदार या अच्छा काम किया. दुनिया के टीकाकरण कार्यक्रम ने एक साल में चार अरब से ज्यादा खुराक कभी भी नहीं बनाए थे. लेकिन इसने 2021 में सार्स-कोविड2 टीके के 10 अरब खुराद बनाए और नौ अरब खुराक दे भी दिए. दुनिया की आबादी के आधे से ज्यादा ने टीके का कम-से-कम एक खुराक ले लिया है.

लेकिन, चाहे वह नैदानिक परीक्षणों, सिक्वेंसिंग या टीका और टीकाकरण का मामला हो, अमीरों और वंचितों के बीच चौड़ी खाई थी. अमीर देशों ने बाकी दुनिया, खासकर अफ्रीका से पहले बूस्टर खुराक देना और बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया. उन्होंने अपने सबसे कमजोर लोगों—डब्ल्यूएचओ के अनुमान के मुताबिक, आबादी के 20 फीसद—की रक्षा के लिए खुराक हासिल कर लिया. कम आय वाले देशों में, 10 फीसद से भी कम लोगों को टीके की पहली खुराक मिली. अग्रिम खरीद के बावजूद, कोवैक्स सुविधा अधिक शक्तिशाली राजनैतिक ताकतों की ओर से पीछे धकेल दी गई और 2021 में दो अरब खुराक मुहैया कराने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में नाकाम रही. लेकिन अब कम से कम उम्मीद तो है क्योंकि निर्माण बड़े पैमाने पर बढ़ गया है और उच्च-आय वाले देशों में मांग घट गई है. इससे अधिक खुराकें सुलभ हो गई हैं. 2022 में हमें जितनी जल्दी हो सके यह सुनिश्चित करना होगा कि दुनिया की अधिक से अधिक आबादी सुरक्षित हो. इसके लिए निर्माण और वितरण प्रणाली को मजबूत करने की दोगुनी कोशिश करनी होगी. दरअसल, खतरा यह है कि अगर हम वैश्विक स्तर पर वायरस के प्रसार को कम नहीं करते हैं तो नए वैरिएंट के उभरने का जोखिम कम नहीं होगा.

साल 2021 की शुरुआत में अल्फा के अपने अनुभव के दोहराव के साथ, हम अत्यधिक उत्परिवर्तित ओमिक्रॉन वैरिएंट के नए खतरे का सामना कर रहे हैं. ओमिक्रॉन का सिक्वेंस डेटा बताता है कि हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि वायरस क्यों और कैसे, और शायद इससे भी अहम कि कहां और किसमें विकसित होते हैं. यह बहुत ज्यादा संक्रामक वायरस है और संभावना है कि वैश्विक स्तर पर प्रमुख स्ट्रेन बनने के लिए यह डेल्टा को पछाड़ देगा. ओमिक्रॉन पिछले वैरिएंट से कम गंभीर हो सकता है, लेकिन इसमें कई म्युटेशन (उत्परिवर्तन) हुए हैं. ऐसे में पहले हुए संक्रमण या मौजूदा टीकों से हासिल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का इस पर कम असर होता है. सरकार ने इस अप्रत्याशित खतरे से निपटने के लिए यात्रा प्रतिबंध, कर्फ्यू और बूस्टर खुराक की कोशिशें शुरू की हैं. लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि 2020 के आखिर की तुलना में इस साल हम अलग स्थिति में हैं. हम वायरस के बर्ताव, नैदानिक परीक्षणों, दवाइयों और टीकों के इस्तेमाल के तरीकों के बारे में अधिक जानते हैं.

नए साल में हमें टीकों के निर्माण और डिलिवरी सिस्टम को मजबूत और दुरुस्त करने के अपने प्रयासों को दोगुना कर देना चाहिए... अगर हमने दुनियाभर में कोविड के विभिन्न वैरिएंट को फैलने से प्रभावी ढंग से नहीं रोका तो हम नए वैरिएंट उभरने के जोखिम को कम नहीं कर पाएंगे

अभी बाकी बचे कामों या हम जिन तरीकों से नाकाम रहे और कई लोगों को हुए जबरदस्त नुक्सान का शोक मनाने की जरूरत को दरकिनार किए बगैर पिछले दो साल में हमने बड़े पैमाने पर काफी कुछ हासिल किया है. यह तर्क दिया जा सकता है कि विज्ञान और तकनीक ने हमें अपने वायरल दुश्मन को समझने, उस पर निगाह रखने और उसके संक्रमण को रोकने की गुंजाइश मुहैया की है. हालांकि यह अन्य कोरानावायरस से कम घातक है. एक ऐसी दुनिया में जहां मानव-निर्मित बदलाव नई महामारियों में वृद्धि की संभावना उत्पन्न कर रहे हैं, यह हमें बताता है कि आने वाली चीजों कैसी शक्ल ले सकती हैं. मोटे तौर पर, हम उन स्थितियों पर दोष मढ़ सकते हैं जिनकी वजह से महामारी फैली, लेकिन 2021 में किए गए व्यापक और ऐतिहासिक प्रयास बताते हैं कि हमारे सहयोगी, सामूहिक बौद्धिक संसाधन कितना कुछ हासिल कर सकते हैं.

हमें क्या करना चाहिए? हमें यह समझने की जरूरत है कि ओमिक्रॉन भविष्य के बारे में यह जानकारी देता है कि नए सार्स-कोविड2 वैरिएंट सामने आते रहेंगे और कुछ तो प्रतिरक्षा प्रणाली को भी चकमा देने में कामयाब रहेंगे और नई वैश्विक लहरें आएंगी. ठीक उसी तरह जैसा हम इनफ्लुएंजा के मामले में पहले ही अनुभव कर चुके हैं. इसका मतलब यह है कि नियंत्रण के हमारे प्रयासों में विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य को अग्रिम मोर्चे पर रहना होगा और इसके लिए सक्षम नीति भी होनी चाहिए. हमें यह समझने के लिए वैज्ञानिक शोध की जरूरत है कि कौन-से नियंत्रण उपाय कामयाब हैं और कौन-से नहीं, कमजोर लोगों को सर्वाधिक सुरक्षा के लिए किस तरह की परीक्षण रणनीति अपनाई जानी चाहिए, सामुदायिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाले कौन-से कारक हैं, बीमारी के हर चरण के लिए सर्वश्रेष्ठ क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्या हैं. यह भी कि व्यापक रूप से सुरक्षात्मक नए टीके कैसे बनाएं और उनका परीक्षण करें जिनमें हर कुछ महीनों में बूस्टर खुराक की जरूरत न हो. हमें ऐसी सक्षम नीति की जरूरत है जो रणनीतिक रूप से बड़े पैमाने पर और लंबी अवधि के लिए विज्ञान को फंड मुहैया करे क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है.

गगनदीप कंग *क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर के गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं*

पवन के. वर्मा

हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व

हिंदू मूल्यों की लड़ाई

हिंदू धर्म की विराट, जटिल और बौद्धिक विरासत को हिंदुत्व के कट्टर दुराग्रहियों ने उसके सबसे निचले मूल्य तक गिरा दिया है. असल हिंदुओं को खड़े होकर इस विभाजन से लड़ना चाहिए

सभी का सार ग्रहण करने की हिंदू धर्म की विजयी क्षमता को सृष्टि की उत्पत्ति पर सबसे पहले लिखित चिंतन ऋग्वेद के 'नासदीय सूक्त' की इन पंक्तियों से बेहतर शायद कोई और बयां नहीं करता ''कौन वास्तविक रूप से जानता है? कौन यहां इसे बता सकता है? यह सृष्टि किस कारण से उत्पन्न हुई? देवता भी इस सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद आए? इसलिए कौन जानता है कि किस कारण से यह सारा संसार उत्पन्न हुआ?''

यह ऋचा रूढ़ धर्मसिद्धांत की अनुपस्थिति की वजह से उल्लेखनीय है; न कोई निश्चितता है; न श्रृद्धा का आदेश है; न धार्मिक आज्ञा पालन, न अनुष्ठान का निर्देश है. इसमें विस्मय है, कुतूहल है, लेकिन सबसे बढ़कर इसमें पड़ताल है, पूछने की, जांच करने की, विचार के पारंपरिक खांचों से आगे परिकल्पना और अनुमान के क्षेत्र में जाने की जरूरत पर जोर है, विचार को आगे बढ़ाने का निमंत्रण है.

हमारे ऋषि-मुनियों ने हिंदू धर्म का यही आत्म-आश्वस्त, अनिर्धारित स्वरूप बताया था. एकम सत विप्रा बहुधा वदंति (सत्य एक है, बुद्धिमान मनुष्य उसे अलग-अलग नामों से बुलाते हैं) हिंदू धर्म की लोचदार शक्ति की कुंजी रही है. आनो भद्रा कृत्वो यन्तु विश्वत: (अच्छे विचारों को सभी दिशाओं से मेरी ओर प्रवाहित होने दो) विचारों के खुलेपन के लिए उसका आह्वान था. उदार चरितम वसुधैव कुटुंबम (उदारमना व्यक्ति के लिए समूचा संसार उसका परिवार है) समावेशी भावना के लिए उसका ध्येयवाक्य था. यही कारण है कि हिंदू दर्शन में एक नहीं बल्कि छह विचार प्रणालियां हैं. प्रत्येक ने पारंपरिक दिव्यता पर कम और ब्रह्मांड की चकरा देने वाली बहुलता के पीछे जो परम सत्य हो सकता है, उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया. फिर आश्चर्य क्या कि चार्वाक, जिनके भौतिकवाद ने उन्हें वेदों को झूठा कहने के लिए विवश किया, हिंदू धर्म के अंग थे. महात्मा गांधी ने लिखा है, ''अगर मैं हिंदू धर्म को थोड़ा भी जानता हूं तो यह अनिवार्य रूप से समावेशी और सदैव वृद्धिशील, सदैव प्रतिक्रियाशील है. यह कल्पना, अनुमान और तर्क-वितर्क करने की सबसे स्वतंत्र गुंजाइश देता है.''

हिंदुत्व ऐसे सनातम धर्म को वहाबी शैली के धर्म में बदलना चाहता है और इस तरह हिंदू धर्म के सार के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है. हिंदुत्व के कट्टर दुराग्रहियों ने हिंदू धर्म की विराट, सूक्ष्म, जटिल और बौद्धिक विरासत को उसके सबसे निचले मूल्य तक गिरा दिया है.

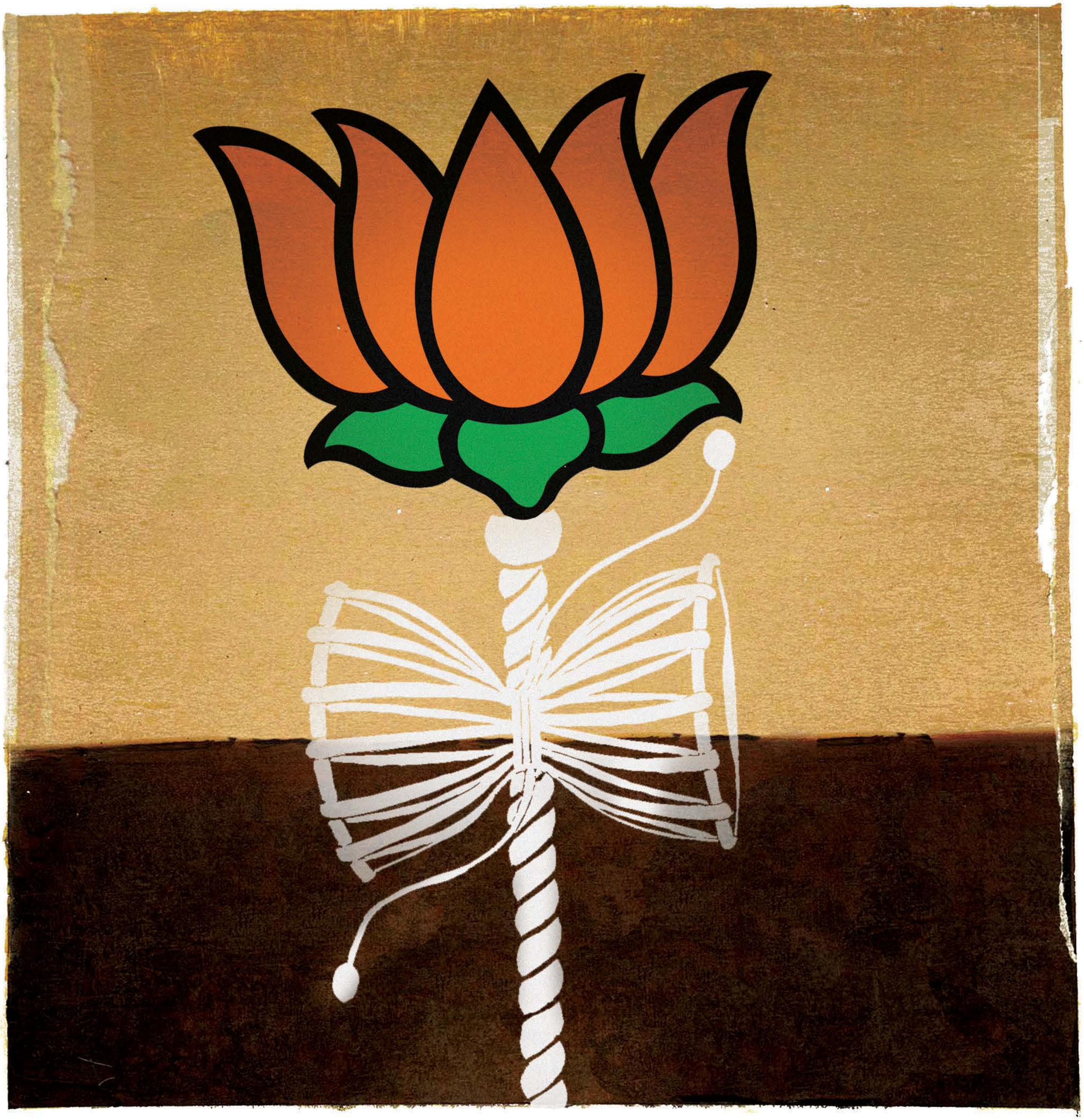

हिंदू धर्म के स्वयंभू रक्षकों के छद्म वेश में भाजपा-आरएसएस के फौजी दस्ते हैं

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

हिंदू धर्म के स्वयंभू रक्षकों के छद्मवेश में वे बीजेपी-आरएसएस के फौजी दस्ते हैं. उनकी विलक्षण खासियतें क्या हैं? पहली, हिंदू धर्म की उनकी जानकारी उथली, अत्यंत सतही और कर्मकांडी है. दूसरे—और ठीक इसी वजह से—वे संवाद, चर्चा और बहस-मुबाहिसे से कतराते हैं. तीसरा, अपने विचार थोपने के लिए हिंसा का सहारा लेने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता. चौथा, वे अत्यंत संकीर्ण और रूढ़िवादी हैं और समाज में मौजूदा गैरबराबरी और ऊंच-नीच का समर्थन करते हैं. पांचवां, वे गहराई से पितृसत्तात्मक हैं, जो मानते हैं कि महिलाओं को उनकी मातहत स्थिति स्वीकार करनी चाहिए और तथाकथित 'हिंदू' मूल्यों की घिसी-पिटी मान्यताओं का पालन करना चाहिए. छठा, उनकी प्रबलतम भावना 'दूसरे' के प्रति नफरत है, जिसमें दूसरे की परिभाषा में मुख्य रूप से मुसलमान आते हैं, लेकिन वे भी शामिल हैं जो मोटे तौर पर उनके समान-धर्मा सवर्ण भाइयों की आत्मतुष्ट मंडली का हिस्सा नहीं हैं. सातवां, वे भारत के हिंदू अतीत को महिमामंडित करना चाहते हैं, लेकिन उनका ज्ञान हास्यास्पद है, जो हवाई जहाजों और कारों की काल्पनिक दुनिया से बना है, और इस तरह प्राचीन भारत की वास्तविक उपलब्धियों और संस्कारों का अवमूल्यन करता है. आठवां, उनके मन में कानून के शासन के प्रति जरा सम्मान नहीं है, खासकर इसलिए कि वे मानते हैं कि उन्हें सत्ता का समर्थन हासिल है. नौवां, धर्म को देशभक्ति से मिलाने में उन्हें जरा भी गुरेज नहीं होता है; केवल उन्हीं की तरह के लोग हिंदू देशभक्त हो सकते हैं, जबकि अन्य दूसरों की देशभक्ति को वे संदिग्ध मानते हैं. और दसवां, वे झूठी जानकारियां खूब फैलाते हैं, जब तक कि यह उनकी पहले से बनी-बनाई विश्व दृष्टि को सहारा देती है.

हिंदुत्व के अलमबरदारों की अगर ये खासियतें हैं, तो भविष्य में हम उनसे क्या करने की उम्मीद कर सकते हैं? हमें स्वीकार करना होगा कि जब कई राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं और 2024 में राष्ट्रीय चुनाव भी होने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी रणनीतिकार धार्मिक ध्रुवीकरण को और हवा देंगे और हिंदू-मुस्लिम फूट को और तीव्र करेंगे. इसके लिए वे हिंदू निगरानी धड़ों को मुखर प्रोत्साहन देने और वक्त आने पर इनकार कर देने की नीति का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह राजनैतिक फायदे की फसल काटने की उम्मीद करेंगे, जबकि इसी दौरान साथ ही साथ वे ज्यादा अराजक और उपद्रवी किस्म की घटनाओं से खुद को अलग कर लेंगे.

लिहाजा 2022 में हम मथुरा स्थित मस्जिद के हमले की जद में आने की उम्मीद कर सकते हैं, फिर ऐसी कार्रवाई के खिलाफ दोटूक कानूनी प्रावधान चाहे जो हों. नफरत भरे भाषणों के जरिये गढ़ी गई कुंद मानसिकता को जोर-शोर से हवा दी जाएगी और इसके मूल में होंगी 'आहत धार्मिक भावनाएं'. हिंदू धर्म की कथित अवमाननाओं के खिलाफ हमले होंगे, मसलन, जैसा कि आश्रम वेबसीरीज की शूटिंग पर निर्लज्ज गैरकानूनी तोड़-फोड़ में देखा गया था. सत्ता के सामने फटकारकर सच बोलने वाले स्टैंडअप कॉमेडियन को परेशान किया जाएगा. महिलाओं को उनके पहनावे, उनकी मेल-मुलाकातों, उनके खान-पान और उनके रिश्तों को लेकर निशाना बनाया जाएगा. नमाज की जगहें, जो गुड़गांव में प्रशासन की मंजूरी के बावजूद हिंदू निगरानी धड़ों के निशाने पर हैं और ज्यादा हमलों की जद में आएंगी. अनिवार्य शाकाहार के पक्ष में मनमाने फरमानों की बाढ़ आ सकती है, फिर चाहे ज्यादातर हिंदू मांस खाते हों. और भी ज्यादा जोर-शोर से दावे किए जाएंगे कि मुसलमानों की आबादी कई गुना अनियंत्रित बढ़ रही है, जबकि सारे सरकारी आंकड़े इसके उलट कहानी बताते हैं.

रुड़की में चर्च पर हुआ हालिया हमला ऐसी और भी गुंडागर्दी का सांचा बन सकती है. अल्पसंख्यकों और हिंदू धर्म की इस संकीर्ण, कट्टर और एकांगी व्याख्या को स्वीकार करने से इनकार करने वाले सारे लोगों को निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया पर उत्तेजना फैलाई जाएगी. उग्र देशभक्ति धर्म प्रचार का औजार बन जाएगी. सबसे बढ़कर सर्वव्यापी और वास्तविक खतरा यह होगा कि उनके फरमान के आगे सिर नहीं झुकाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ संगठित गुंडा तत्व बलप्रयोग करेंगे. बदतर यह कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां, खासकर भाजपा शासित राज्यों में, कम ही कुछ करेंगी और ऐसी अराजकता को छूट देने वाले बयान दिए जाएंगे, जैसा कि भाजपा के शासन वाले राज्य मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने आश्रम हमले के मामले में दिया था.

हिंदू धर्म सहस्त्राब्दियों से इसलिए बचा रहा क्योंकि यह विविधताओं को अपने में समाहित करता है और इसमें शास्त्रार्थ या सभ्य विमर्श की अंतर्निहित क्षमता है. हमारे मूल ग्रंथ, उपनिषद, भगवद गीता, ब्राह्मण सूत्र, सभी संवाद के उदाहरण हैं. सभी जगह से सार ग्रहण करना और समावेशी होना हिंदू धर्म की कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है. भाजपा-आरएसएस के राजनैतिक हथियार के रूप में हिंदुत्व इस विलक्षण धर्म को अज्ञानी, निरक्षर और विकृत हुक्मनामों की श्रृंखला में बदल देना चाहता है. सारे सच्चे हिंदुओं को इस खतरे के सामने डटकर खड़ा होना चाहिए और इसे परास्त करना चाहिए.

भाजपा की चुनावी रणनीति धार्मिक ध्रुवीकरण को हवा देने की होगी. ऐसी नीति जिसमें हिंदू निगरानी धड़ों को मुखर प्रोत्साहन दिया जाएगा और वक्त आने पर इससे इनकार भी कर दिया जाएगा

पवन के. वर्मा *लेखक-राजनयिक और पूर्व सांसद (राज्यसभा) हैं और फिलहाल वे टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं*

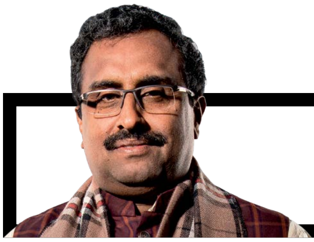

राम
माधव

हिंदुत्व

गर्व और गुस्से के बीच संतुलन

भारत के राष्ट्रीय जीवन में हिंदू सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहचान की केंद्रीयता को पुनर्स्थापित करने का आरएसएस का मुख्य मिशन वास्तविकता में बदल चुका है. 2022 में संघ को इससे पैदा हो रही भ्रांतियां दूर करने की जरूरत है

नए साल के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बेंगलूरू में प्रतिष्ठित नागरिकों की एक सभा को संबोधित किया. वे वहां हिंदू राष्ट्र या हिंदू-मुस्लिम संबंधों के बारे में नहीं, बल्कि पर्यावरण के बारे में बात करने गए थे. लंबे समय से स्वयंसेवी संगठनों का काम समझे जाने वाले इस क्षेत्र में अब आरएसएस भी रुचि दिखा रहा है. हाल ही में आरएसएस की नियमित गतिविधियों में एक नया खंड पर्यावरण गतिविधि जोड़ा गया है.

सिर्फ पर्यावरण ही नहीं आरएसएस-प्रेरित सक्रियता अब स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण सहित कई अन्य क्षेत्रों में देखी जा सकती है. 'सक्षम' विकलांगों के बीच काम करने वाला एनजीओ है. विकलांगों के लिए 'दिव्यांग' शब्द का प्रयोग आरएसएस ने सरकार की ओर से इस्तेमाल किए जाने के बहुत पहले से शुरू कर दिया था. कोविड महामारी से उपजे संकट के दौरान आरएसएस ने चुपचाप देश भर में 100,000 से अधिक ग्राम स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे. इन स्वयंसेवकों को भविष्य में कोविड की लहर की स्थिति में आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों की तरफ से बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया था. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण संस्थानों को चलाने से आगे बढ़ते हुए संघ के सदस्य अब विश्वविद्यालयों और उत्कृष्ट

संस्थानों की स्थापना करने में लगे हैं.

इस तरह की 'एनजीओ शैली' वाली सक्रियता संघ की छवि और उसके प्रति व्याप्त धारणा को ठीक करने का लक्ष्य केंद्रित प्रयास है. पिछले लगभग एक दशक में आरएसएस ने चुपचाप एक नई गतिविधि, 'विशेष संपर्क' के माध्यम से विशिष्ट लक्षित समूहों तक अपनी पहुंच बढ़ाई है. भागवत सहित संघ के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी आरएसएस के मुख्य मुद्दों को समझाने के लिए समाज पर 'प्रभाव' डाल सकने वाले लोगों से मिलते हैं. आरएसएस प्रमुख ने बीते दिनों में मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों के नेताओं से संपर्क करते हुए उन्हें पूर्वाग्रहों को दूर करने और संघ के बारे में ज्यादा जानने के लिए प्रोत्साहित किया है. इस क्रम और आगे बढ़ाते हुए, आरएसएस ने विश्व स्तर पर अपनी छवि परिवर्तन के प्रयासों पर प्रभाव डालने वाली दुष्प्रचार की चुनौती से निपटने के लिए दर्जनों देशों में राजनीतिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, धार्मिक और सामाजिक नेताओं से संपर्क करने का काम शुरू किया है.

धर्मनिरपेक्षता की उस विकृत धारणा, जिसे बहुत से हिंदुत्व समर्थक छद्म धर्मनिरपेक्षता कहते थे, को अब बहुसंख्यक भारतीयों ने खारिज कर दिया है

मितभाषी रहे इस संगठन में इन दिनों एक नया आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है. यह आत्मविश्वास इस तथ्य से उपजा है कि एक सदी से भी अधिक समय से यह भारत के राष्ट्रीय जीवन में हिंदू सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहचान की केंद्रीयता को पुनर्स्थापित करने के जिस मुख्य उद्देश्य के लिए सक्रिय रहा है, वह अब वास्तविकता बन चुका है. हिंदुत्व आज राष्ट्र का केंद्रीय विषय है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी खुद को हिंदू कहना चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी भी ऐसा ही करती हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या की मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने के लिए बजट आवंटन भी किया है.

एक दशक पहले इस सब की कल्पना नहीं की जा सकती थी. आजादी के बाद के दशकों में भारत का मुख्य राजनीतिक विमर्श धर्मनिरपेक्षता के इर्द-गिर्द केंद्रित था. हिंदू, हिंदुत्व और हिंदूवाद को किनारे करते हुए उसे सांप्रदायिक घोषित कर दिया गया था. हिंदू महासभा के नेता एन.बी. खरे का जवाहरलाल नेहरू को "दुर्घटना से हिंदू" के रूप में उल्लेख करना बीते वर्षों में मुख्यधारा की राजनीति की पहचान हिस्सा बन गया था. स्वतंत्रता के बाद के मुख्य राजनीतिक विमर्श में हिंदू पहचान की बहुसंख्यकवाद के रूप में अस्वीकृति तथा उसी सांस में अल्पसंख्यकवाद की पैरोकारी करने को ही मिथ्या धर्मनिरपेक्षता मान लिया गया था.

धर्मनिरपेक्षता की उस विकृत धारणा, जिसे बहुत से हिंदुत्व समर्थक छद्म धर्मनिरपेक्षता कहते थे, को अब बहुसंख्यक भारतीयों ने खारिज कर दिया है. खुद को हिंदू कहना अब किसी झिझक या शर्म की बात नहीं है. यहां तक कि प्रमुख कांग्रेसी नेता भी हिंदू इतिहास और सभ्यता के बारे में किताबें लिख रहे हैं. इसका श्रेय आरएसएस को मिलना चाहिए.

कहते हैं कि हर आंदोलन चार चरणों से गुजरता है, "पहले लोग आपकी अनदेखी करते हैं, फिर वे आप पर हंसते हैं. फिर वे आप पर हमला करते हैं, और फिर आप जीत जाते हैं." बहुत से आंदोलन पहले तीन चरणों के दौरान ही दम तोड़ देते हैं. आरएसएस इन सभी को सफलतापूर्वक पार कर गया है और उपहास तथा अस्वीकृति से पार पाकर राष्ट्रीय मुख्यधारा के हिस्से के रूप में उभरा है. एक सदी तक जिंदा बचे संगठन कम ही हैं. आरएसएस न केवल बचा है बल्कि तेजी से विकसित हुआ है.

आज, इसकी 50,000 से अधिक शाखाएं हैं और आरएसएस की गतिविधियां देश के लाखों गांवों तक फैली हुई हैं. हाल ही में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के लिए वित्तीय मदद जुटाने के अभियान से इसके प्रसार और प्रभाव का आकलन किया जा सकता है. बीते साल के आरंभ में शुरू किए गए इस अभियान में संघ के हजारों कार्यकर्ताओं ने घर-घर पहुंच कर 13 करोड़ से अधिक भारतीयों से समर्थन हासिल किया. इसमें सभी दलों, सामाजिक समूहों और यहां तक कि मुस्लिम और ईसाई जैसे अन्य धर्मों के लोग भी शामिल थे. कोई अन्य सामाजिक संगठन ऐसी व्यापक पहुंच और आम जनता से जुड़ाव का दावा नहीं कर सकता.

अपने शताब्दी वर्ष के करीब पहुंचते हुए यह जैसे-जैसे अपनी ताकत के साथ ही बदलते समय की आवश्यकता के अनुरूप कार्यक्रमों की शुरूआत कर रहा है, संगठन को कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. यद्यपि यह हिंदू सभ्यता की पुनरोक्ति के आधार के रूप में उभरा है, फिर भी इसकी परख और आलोचना का क्रम जारी है. इसकी तेज वृद्धि न केवल संगठनात्मक प्रसार के रूप में हुई है, बल्कि इसकी विचार प्रक्रिया के प्रभाव में भी हुई है. और वैचारिक प्रभाव में वृद्धि सांगठनिक प्रसार की तुलना में कई गुना अधिक है. वास्तव में, शाखाओं के बाहर के आरएसएस का आकार उसके अंदर के आरएसएस से बहुत बड़ा है. और, यह आवश्यक नहीं कि जो अनुशासन संगठन के भीतर है, वह बाहर भी हो.

यह स्थिति संघ नेतृत्व पर अधिक भार डालती है. मोहन भागवत इसे समझते हैं. कुछ समय पहले जब उन्होंने 'सभी भारतीयों का डीएनए एक सा' होने की बात की तो उन्हें एक वर्ग की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था. मूलतः उनका जोर मुसलमानों को यह बताने पर था कि वे इस प्राचीन राष्ट्र के सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत जीवन से अलग नहीं हैं. लेकिन जब उन्होंने हाल ही में दोहराया कि "40,000 साल पहले के भारत के सभी लोगों का डीएनए आज के लोगों के समान है", तो शायद यह उन नाराज वर्गों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया होने के साथ ही आगामी वर्षों में संगठन के लिए संभावित विषय भी था.

भारत में आज हिंदू गौरव की व्यापक अभिव्यक्ति है जो आवश्यक नहीं कि किसी अन्य समुदाय या धर्म के खिलाफ ही हो. धर्मांतरण और इस्लामी कट्टरपंथ जैसे कृत्यों से कुछ हिंदू वर्गों में आक्रोश भी है-वास्तविक या अन्यथा रूप से उत्पीड़न का शिकार होने का भाव है. अपने शताब्दी वर्ष के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए आरएसएस के लिए चुनौती यह होगी कि वह गर्व और क्रोध के बीच संतुलन बनाए रखे और यह सुनिश्चित करे कि दोनों में से कोई भी सीमा से बाहर न छलकें.

राम माधव *राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं.*

इलस्ट्रेशनः **सिद्धांत जुमडे**

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

वक्त बदल रहा है...

वैश्विक अर्थव्यवस्था की रिकवरी मजबूत है लेकिन वह असमान और अधूरी है, और 2022 में कई नई चुनौतियां हैं

महामारी शुरू हुए करीब दो साल होने को हैं और अभी तक हम मुसीबतों-खतरों से उबरे नहीं हैं. ओमिक्रॉन वैरिएंट अब भी फैल रहा है जबकि डेल्टा लहर अभी थमी नहीं है. लेकिन यह 2020 नहीं है. तब के मुकाबले हमारे पास आज कई वैक्सीन हैं और इलाज के लिए कम से कम दो दवाओं का निर्माण हो रहा है और कई का फॉर्मूला तैयार हो रहा है. हालांकि दुनियाभर में टीकाकरण की दरें अलग-अलग हैं लेकिन लॉकडाउन और सामाजिक दूरी बनाने के दूसरे बेहद कठोर उपाय बीते दिनों की बात हो सकती है. ऐसे में हम शायद कुछ झटकों के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूत रिकवरी जारी रहने की उम्मीद कर सकते हैं. 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था संभवतः करीब 5.8 फीसद की दर से बढ़ी, जो 2020 में −3.3 फीसद पहुंच गई थी. हम 2022 में 4.3 फीसद की दर से ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं. लेकिन यह रिकवरी असमान और अधूरी ही रहेगी. विकसित अर्थव्यवस्थाएं उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले ज्यादा मजबूती से पटरी पर आई है. उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में महामारी से पहले के मुकाबले रिकवरी 2022 के आखिर तक अधूरी रहेगी. इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए. महामारी बुनियादी तौर पर ऐसा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट था जिसके आर्थिक नतीजों को दूर करने के लिए भरपूर वित्तीय मदद की जरूरत थी. विकसित देशों में दूसरे देशों के मुकाबले सार्वजनिक स्वास्थ्य की कहीं बेहतर व्यवस्था है और उनके पास ज्यादा वित्तीय गुंजाइश भी है. ये अंतर असमान रफ्तार और रिकवरी की पूर्णता में जाहिर हो रहे हैं.

रिकवरी के व्यापक होने के साथ ही असाधारण नीतिगत समर्थन भी अपने अंत को पहुंच रहा है. मौद्रिक और वित्तीय नीतियां सामान्य हो रही हैं, अलबत्ता विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में उनकी अतिरिक्त क्षमताओं और उनके सामने मौजूद महंगाई के दबावों के आधार पर ऐसा हो रहा है. हमें उम्मीद है कि आपूर्ति श्रृंखला के सामान्य होने के साथ ही महंगाई का दबाव कम हो जाएगा लेकिन यह महामारी के पहले के मुकाबले बहुम स्तर पर जाकर सामान्य होगा. नीतियां सामान्य होने के साथ ही यह सवाल लाजमी है कि क्या सामान्य स्थिति के प्रति अर्थव्यवस्थाएं लचीली हो सकती हैं. कुछेक को छोड़कर अमेरिका समेत ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं इस इम्तिहान को पास कर जाएंगी क्योंकि निकासी धीमी होगी और प्राइवेट सेक्टर की बैलेंस शीट 2016-18 के मुकाबले ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं. लेकिन सारी अर्थव्यवस्थाएं अछूती नहीं रहेंगी. ब्राजील

जहांगीर अज़ीज़

और चिली को नीतिगत समर्थन की वापसी से पहले ही चुनौती मिल रही है और मुमकिन है कि भारत जैसे दूसरे देशों में घर और एसएमई की बैलेंस शीट को व्यापक नुक्सान पहुंचे, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है. इन देशों में जितनी वित्तीय मदद मिलनी चाहिए थी, उतनी नहीं मिली. मजबूत लेकिन असमान रिकवरी तथा महामारी की अनिश्चितताओं के बीच पांच विकास के मामलों पर नजर रखना चाहिए.

कोविड-19 बन जाएगी स्थानीय बीमारी

हालांकि डेल्टा के अब भी गंभीर होने और ओमिक्रॉन के प्रसार के मद्देनजर इसकी कल्पना करना मुश्किल है लेकिन टीकाकरण, दवाइयों और बेहतर चिकित्सीय प्रबंधन के साथ ही यह महामारी स्थानीय होती जा रही है. इस वायरस के कम खतरनाक रूप हमारे साथ बने रहेंगे. ज्यादा सचेत सामाजिक मेलजोल के साथ ही टीकाकरण सामान्य बन जाएगा. आर्थिक प्रभाव के मामलों में इसका यह मतलब हुआ कि स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ जाएगा—उसी तरह से जैसे इन्फ्लुएंजा की वजह से उत्पादकता लागत बढ़ जाती है—अनुपस्थिति और कामगारों की हिस्सेदारी कम होने के साथ ही कामगारों के काम की अवधि और पूंजी सिकड़ जाएगी. इन सबकी वजह से दुनियाभर में जीडीपी का कुछ हिस्सा गायब हो जाएगा लेकिन उसका ग्रोथ रेट पर खास असर नहीं पड़ेगा.

कॉप26 की प्रतिबद्धताएं

कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए कॉप26 की प्रतिबद्धताओं से न केवल भविष्य के ऊर्जा स्रोत बल्कि जिंसों की कीमत भी प्रभावित होंगे. कार्बन न्यूट्रलिटी की राह तय कर पाना आसान नहीं होगा, खासकर जब आपका देश पर्याप्त विकल्पों के बिना जीवाश्म ईंधन के उपभोग को कम करने की कोशिश करने वाला है. इस साल हमने पहले ही देख लिया है कि यूरोप में प्राकृतिक गैस की कीमतें तेजी से बढ़ गईं क्योंकि टिकाऊ विकल्पों की व्यवस्था किए बगैर जीवाश्म ईंधन वाली ऊर्जा के स्रोतों में कटौती कर दी गई. इसी तरह, चीन के कार्बन खत्म करने के प्रयासों की वजह से दुनियाभर में जिंसों की कीमत बढ़ गई. स्थाई और ज्यादा सक्षम हरित ऊर्जा के लिए व्यापक वैश्विक प्रयास वक्त के साथ ही सफल होंगे. इस बीच वैश्विक जिंस बाजार छोटे चक्रों के साथ ज्यादा संवेदनशील हो जाएंगे.

चीन का व्यवस्था परिवर्तन

हालांकि हमें चीन की धीमी ग्रोथ से 2021 में पटरी पर लौटने की उम्मीद थी, जबकि नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन अभी जारी है. इस बदलाव के दो पहलू महत्वपूर्ण हैं. पहला, ग्रोथ के प्रभुत्व वाले लक्ष्य से बहु-उद्देश्यीय फ्रेमवर्क की ओर स्थानांतरण का मतलब है कि मध्यम अवधि में कम ग्रोथ के लिए ज्यादा तैयार रहना होगा. एक ओर जहां नीतियों से इनोवेशन को प्रोत्साहन और अधिक मूल्य संवर्धित उद्योगों (ग्रीन टेक, बायोटेक, कंप्यूटिंग) को मदद मिलेगी, जिससे ग्रोथ को बढ़ावा मिलना चाहिए, वहीं दूसरी नीतियों से दीर्घकालिक फायदों की उम्मीद में अल्पकालिक ग्रोथ की संभावनाएं निरुत्साहित हो सकती हैं (फाइनेंशियल डिलीवरेजिंग, डिकार्बनाइजेशन, और क्षेत्रीय तथा आय की समानता में कमी). दूसरा, अतीत में आवास और औद्योगिक नीतियों को मैक्रोइकोनॉमिक नीतियों के साथ प्रतिचक्रीय आधार पर आगे बढ़ाया गया. इसका मकसद मैक्रोइकोनॉमिक नीतियों की प्रभाविता बढ़ाना और उनके संचरण अंतराल को कम करना था. औद्योगिक और आवास नीतियों के अब चक्रीय विकल्पों के बजाए दीर्घकालिक उद्देश्यों पर केंद्रित होने की वजह से मैक्रोइकोनॉमिक नीति के बदलाव कमजोर पड़ गए हैं और उनका संचरण अंतराल लंबा हो गया है. मुमकिन है कि नीतियों को पहले की तरह प्रभावी बनाने के लिए उनमें संशोधन की जरूरत हो. यह सीखने वाली प्रक्रिया है और इसमें वक्त लग सकता है, जिससे अधिकारियों के लिए पर्याप्त से कम नीतिगत मदद देने का जोखिम बढ़ जाता है. चीन के ग्रोथ इंजन में ढांचागत मंदी और बदलाव का यह भी मतलब है कि इससे चीन से जुड़ी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होंगी. चीन को जिंस और पारंपरिक उत्पाद निर्यात करने वालों को इस बदलाव की आंच महसूस होगी जबकि महंगे उत्पादों के निर्यातकों को फायदा हो सकता है.

> **डेल्टा के अब भी गंभीर होने और ओमिक्रॉन के प्रसार के मद्देनजर इसकी कल्पना करना मुश्किल है लेकिन टीकाकरण, दवाइयों और बेहतर चिकित्सीय प्रबंधन के साथ ही यह महामारी स्थानीय होती जा रही है**

कोविड से स्थायी नुक्सान

हमारा अनुमान है कि यह महामारी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मध्य समय के ग्रोथ का स्थायी नुक्सान कर जाएगी. यह उनके श्रम बाजारों, घरों और एसएमई बैलेंस शीट को पर्याप्त दागदार बना देगी. एक ओर जहां डिजिटाइजेशन के छलांग लगाने समेत इसकी यादें ताजा करने वाली कहानियां हैं कि उत्पादकता नए स्वर्णिम युग में कैसे पहुंच रही है, वहीं हमारा अनुमान है कि इन अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादकता वृद्धि के चालक उत्पादकता में निरंतर दबे रुझान की ओर संकेत करते हैं. चीन के मध्यकालिक ग्रोथ में मंदी पहले से मौजूद बाधाओं, जैसे बुढ़ाती आबादी, आर्थिक राष्ट्रवाद और व्यापार संरक्षण में इजाफा करेगी.

आ रहे चुनावी चक्र

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं इस मामले में खुशकिस्मत रहीं कि महामारी और उसके बाद के दिनों में कोई बड़े चुनावी बदलाव नहीं हुए. लेकिन आने वाले दो-तीन वर्षों में इन सभी अर्थव्यवस्थाओं में चुनाव होने वाले हैं. महामारी के साये में होने वाले कुछ चुनावों (ज्यादातर दक्षिण अमेरिका) में साफ तौर पर लोकलुभावनवाद की ओर झुकाव दिखा है. इस बदलाव से वित्तीय अनुशासन को नुक्सान पहुंचा है और बाजार सहम गए हैं. महामारी से पहले के वर्षों में कम ग्रोथ और (खासकर निम्न एवं मध्य आय वर्ग वाले) परिवारों और एसएमई की बैलेंस शीट दक्षिण अमेरिका में राजनैकि झुकाव की प्रमुख वजहें थीं. चुनाव के समय दूसरी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की भी परीक्षा होनी है.

जहांगीर अजीज *जे.पी. मॉर्गन के चीफ इमर्जिंग मार्केट्स इकोनॉमिस्ट हैं*

नीलकंठ मिश्र

भारतीय अर्थव्यवस्था

पूर्ति ज्यादा मांग कम

टीके लगने की तादाद जैसे-जैसे बढ़ेगी, आपूर्ति श्रृंखला की रुकावटें कम होंगी, उत्पादन बढ़ेगा. 2022 की चुनौती होगी मांग को ऊंचा बनाए रखना ताकि भारत महामारी से पहले की वृद्धि की राह पर लौट सके

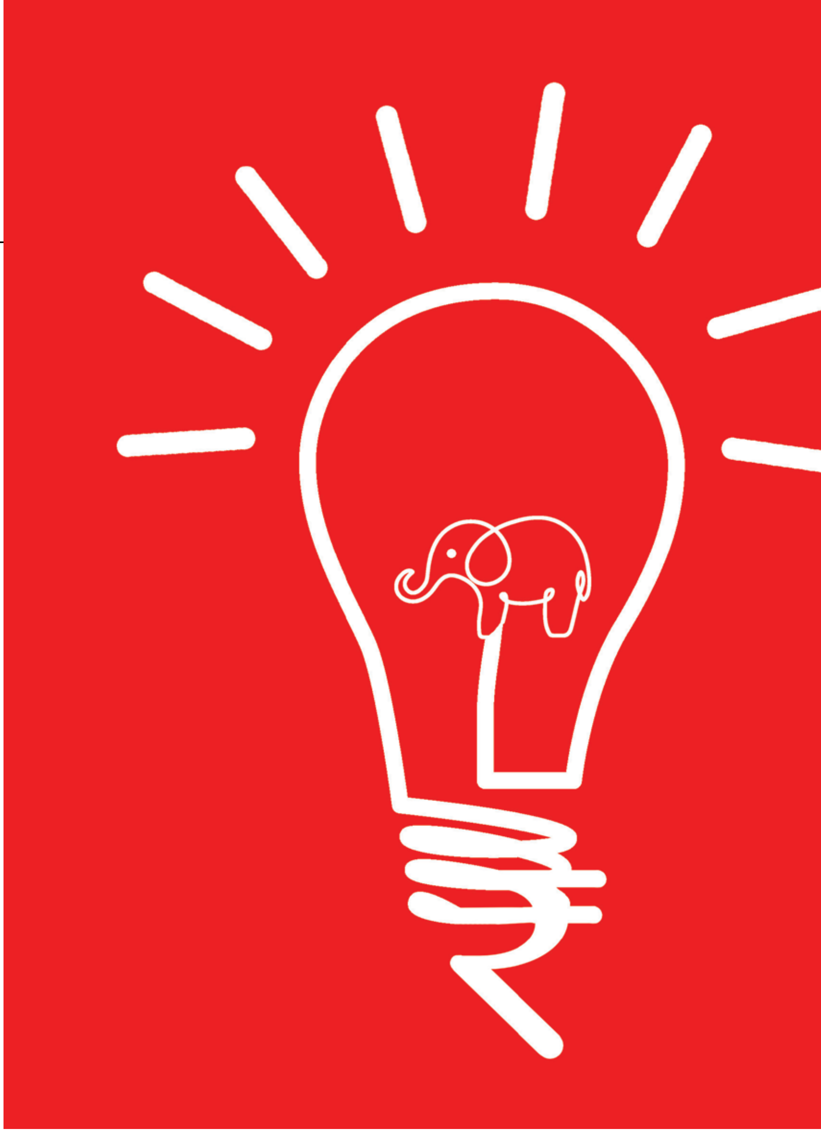

कोविड-19 महामारी की जिन लहरों ने 2020 में वैश्विक आर्थिक मंदी का बिगुल फूंका, 2021 के अंत में भी कायम थीं. डेल्टा वैरिएंट अब भी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है और लगभग हर देश को मानना पड़ रहा है कि कोविड-19 शायद कभी जाएगा ही नहीं. कुछ हफ्तों में हम शायद जान पाएं कि नए ओमिक्रॉन वैरिएंट से संक्रमण कितना गंभीर हो सकता है और यह लहर कितनी दूर जाएगी. मगर और भी नए वैरिएंट का खतरा मंडरा रहा है. इन चुनौतियों के बावजूद लगता यही है कि 2022 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 2021 के मुकाबले बहुत अलहदा हो सकता है.

कामकाज पर पाबंदियां 2021 में जैसे-जैसे हटीं, उपभोक्ता मांग में उछाल आया. सरकारी खजाने से लोगों की जेब में पैसा डालने से, खासकर अमेरिका में, इतना जोरदार बढ़ावा मिला कि बंदरगाह की क्षमता और जहाजों से लेकर सेलफोन, खिलौनों, जूतों और उपकरणों तक हर चीज की तंगी पैदा हो गई. छिन्न-भिन्न आपूर्ति श्रृंखलाओं को सेमीकंडक्टर सरीखे छोटे लेकिन बेहद जरूरी पुर्जों के लिए जूझना पड़ा. ऐसे में उत्पादन में लगातार खलल पड़ने से समुद्री जहाज मार्ग बंद हो गए. मैन्युफैक्चरिंग स्थलों पर संक्रमण के छिटपुट प्रकोप ने तंगी को और तीव्र कर दिया. इसने न केवल उपभोक्ताओं को बल्कि आपूर्ति श्रृंखलाओं के बिचौलिए को भी जमाखोरी करने के लिए उकसाया, जिससे मांग और पूर्ति की जाहिरा खाई और चौड़ी हो गई और कीमतों में तेजी आ गई. साल के अंत की तरफ बढ़ते हुए वैश्विक मांग लौटने से ऊर्जा की कीमतें बढ़ीं, पर कोयले, गैस और तेल के आपूर्तिकर्ताओं ने, जिन्होंने तकरीबन दो साल से मांग के दबे होने से उत्पादन क्षमता स्थगित कर रखी थी, तब भी कामकाज पूरे जोर-शोर से शुरू नहीं किया. अमेरिका में घर-परिवारों को मिली बड़ी नकद सहायता की वजह से भी श्रम बाजार में उससे ज्यादा तंगी पैदा हो गई जितनी उत्पादन के स्तर को देखते हुए होनी चाहिए थी. महंगाई के कई दशकों की ऊंचाई पर पहुंच जाने का शायद यह भी एक अहम कारण था. 2022 में वैश्विक उत्पादन में बढ़ोतरी होनी चाहिए. इससे मुद्रास्फीति का दबाव कुछ कम होगा. मसलन टीके लगने का स्तर बढ़ने से फैक्ट्रियां निर्विघ्न चल पाएंगी, वियतनाम सरीखे केंद्र फिर खुले रह पाएंगे और धातुओं तथा सेमीकंडक्टरों सरीखी प्रमुख आगतों की सुचारू आपूर्ति हो सकेगी, जिससे माल भरा रहेगा और उत्पादन श्रृंखलाएं फिर शुरू हो पाएंगी. चीन में व्यापक लॉकडाउन से आपूर्ति श्रृंखलाओं में खलल पड़ सकता है (बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में केवल चीन ही अब भी ''शून्य-कोविड'' का लक्ष्य लेकर चल रहा है). यही नहीं, तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य होने पर भूराजनीति के बादल मंडरा रहे हैं. इस खतरे से चौकन्ना रहना जरूरी है.

दूसरी तरफ, 2021 के उलट, 2022 में दाखिल होते वक्त दुनिया सुस्त पड़ती मांग से दोचार है. खुदरा बिक्री दुनिया भर में रुझान से पीछे चली गई है और दबी

इलस्ट्रेशन : **नीलांजन दास**

> **वैश्विक मांग में वृद्धि का कमजोर पड़ना निर्यात-चालित क्षेत्रों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है. अलबत्ता भारत की वृद्धि की रफ्तार बनाए रखने के लिए नीति निर्माताओं को वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ाने पर ध्यान लगाए रखना चाहिए**

हुई मांग के और कमजोर पड़ने, अमेरिका की भारी प्रोत्साहन राशि का असर फीका पड़ने, चीनी खुदरा बिक्री के रुझान से 10 फीसद से ज्यादा बने रहने और तेजी से बढ़ते संक्रमणों के चलते कई यूरोपीय देशों की ओर से फिर कामकाज पर पाबंदियां लगाए जाने से इनके अगले कुछ महीनों में रुझान से और भी नीचे जाने की आशंका है. सेवाओं-से-सामान का जो बदलाव लॉकडाउनों के दौरान आया था (क्योंकि सेवाएं प्रतिबंधित थीं), वह भी उलटना चाहिए. इससे सामान की मांग को नुक्सान पहुंचेगा. स्थिर-परिसंपत्ति निवेश दुनिया भर में कमजोर रहा. महामारी के बार-बार प्रकोप से पैदा अनिश्चितता के कारण तो ऐसा हुआ ही, लेकिन अपने रियल एस्टेट और स्थानीय बुनियादी ढांचे को लेकर चीन की नीति में आए बदलावों के कारण भी ऐसा हुआ. दिसंबर में थोड़ा सुधार हुआ, पर मकसद इन गतिविधियों को फिर तेजी से बढ़ाने के बजाए धीमे-धीमे बढ़ाना दिखाई देता है.

मांग में सुस्ती से निपट पाना शायद आसान न हो. मुद्रास्फीति विकसित देशों तक में सुर्खियों में है और कुछ विकासशील देशों में भी बढ़ी है, जिससे सरकारें राजनैतिक दबाव में हैं (खासकर अमेरिका में) और संभावना नहीं कि नीति निर्माता धीमी वृद्धि का जवाब और ज्यादा प्रोत्साहन पैकेजों से देने की स्थिति में होंगे. असल में, तकरीबन सारे केंद्रीय बैंक मौद्रिक समायोजन से पीछे हट रहे हैं और कुछ ने तो मौद्रिक सख्ती भी शुरू कर दी है. मांग में कमी और पूर्ति में सुधार से महंगाई कम करने में मदद मिलनी चाहिए, पर इसमें कई माह लग सकते हैं. अमेरिका सरीखे बाजारों में तो शायद और भी ज्यादा वक्त लग सकता है जहां राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन सबसे तगड़े रहे हैं. वैश्विक वित्तीय बाजारों का अफसाना महंगाई की चिंता से हटकर वृद्धि की चिंता पर आ सकता है, यहां तक कि तब भी जब कई अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई ऊंची बनी हुई है. यह मुद्रा, बॉन्ड और शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव का नुस्खा है, तब तो और भी जब व्यापारियों की मौजूदा पीढ़ी में ज्यादातर अमेरिका की ऊंची मुद्रास्फीति की नीति की पृष्ठभूमि से वाकिफ नहीं हैं.

तो भारत कैसा प्रदर्शन करेगा? भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल आंतरिक है: महामारी से पहले की राह के यह कितना नजदीक आ सकता है? आम राय से अनुमान यह है कि अगले वित्त वर्ष में उत्पादन कोविड से पहले के स्तर से करीब 10 फीसद नीचे रहेगा. यह निराशावादी अनुमान मालूम देता है. अंतर मात्र पांच फीसद रह सकता है और तब भारत की वृद्धि के पूर्वानुमानों को खासा बढ़ाना पड़ेगा.

निराशावादियों को उन 2.5 करोड़ कामगारों की चिंता है जो उद्योग और सेवा से फिर खेती-किसानी में लौट गए और शायद अन्य 1.5 करोड़ लोग बीते दो सालों में कामकाजी उम्र वाली आबादी में जुड़े हैं. मगर नौकरियों के इस नुक्सान को स्थायी कहना समझदारी नहीं होगी. सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली सेवाएं हैं व्यक्तिगत सेवाएं, यात्रा और पर्यटन, तथा शिक्षा. कार्यस्थलों पर काम पूरी तरह दोबारा शुरू होने पर दफ्तरों और घरों (जैसे सफाई कामगार, रसोइए, ड्राइवर और आया) में निजी सेवाओं की नौकरियां वापस आ जानी चाहिए. सरकारी और भारत में आने वाली अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के फिर शुरू होने से यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में नौकरियां बहाल होने में मदद मिलनी चाहिए. इसी तरह संभावना यह है कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा देने वाले माता-पिता निजी स्कूलों के खुलने पर उन्हें फिर इन स्कूलों में डालेंगे. इससे शिक्षक भर्ती करने होंगे.

औद्योगिक रोजगार के मामले में नुक्सान निर्माण सामग्री और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हुआ. कलपुर्जों की कमी घटने से ऑटो उत्पादन अब धीमे-धीमे बढ़ रहा है. निर्माण गतिविधियों में फिर उछाल आएगा, क्योंकि राज्य सरकारें, जो लॉकडाउन के दौरान खर्च करने को तरस गईं और जिसकी वजह से उनके पास फिलहाल खर्च न की गई करीब 3 लाख करोड़ की रकम है, फिर खर्च करेंगी. करों से मिलने वाली अच्छी रकम केंद्र सरकार के लिए भी राजकोषीय गुंजाइश पैदा कर रही है. यही नहीं, करीब एक दशक लंबे ठहराव के बाद, जिसने जीडीपी की वृद्धि में करीब एक फीसद से ज्यादा का पलीता लगा दिया, रियल एस्टेट निर्माण भी तेजी पकड़ने को तैयार दिखता है.

आखिर में, सामान्य हालात लौटने के साथ अनौपचारिक क्षेत्र में भी थोड़ी बहाली दिखाई दे सकती है. तंगी का माहौल बड़ी और संगठित फर्मों की तरफदारी करता है, जो आगे की राह में बदलना चाहिए, तब तो और भी जब पूंजी से भरपूर भारतीय वित्तीय क्षेत्र फिर कुछ जोखिम उठाने लगे हैं.

वैश्विक मांग में वृद्धि का कमजोर पड़ना निर्यात-चालित क्षेत्रों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है. अलबत्ता भारत की वृद्धि की रफ्तार बनाए रखने के लिए नीति निर्माताओं को वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ाने पर ध्यान लगाए रखना चाहिए, सेवाओं में भी (जहां बड़ा मौका पुकार रहा है और केवल सॉफ्टवेयर में ही नहीं) और वस्तुओं (इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान और फुटवीयर, खिलौने, ऑटो कलपुर्जे, अक्षय ऊर्जा उपकरण और रसायनों वगैरह) में भी. मजबूत वृद्धि ज्यादा नहीं तो कम से कम एक दशक तक जरूरी है, न केवल संप्रभु ऋण अनुपात को ज्यादा सुरक्षित स्तर तक नीचे लाने के लिए बल्कि लोगों को गरीबी से निकालने के लिए भी.

नीलकंठ मिश्र *एपीएसी स्ट्रैटजी के सह-प्रमुख और क्रेडिट सुइस के इंडिया स्ट्रैटजिस्ट हैं*

रोहन मूर्ति

अगली श्रमिक क्रांति

डिजिटल कामकाज का भविष्य कर्मचारियों के काम के बारे में अनुभव समझने और उसे बेहतर करने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर टिका है

दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता जैसी मेट्रिक्स से संचालित कंपनियां सभी को ऑनलाइन कॉमर्स, मीडिया, मनोरंजन और सोशल कनेक्शंस आदि में शामिल करने की कोशिश करती हैं. लेकिन ये सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो हम अपने काम (नौकरी) के अतिरिक्त करते हैं. यकीनन रोजाना हम अन्य गतिविधियों की तुलना में काम में अधिक वक्त बिताते हैं. काम हमारी बौद्धिक और भावनात्मक जिंदगी का अहम हिस्सा है. यह हमें वित्तीय सुरक्षा उद्देश्य, प्रयोजन और पहचान का एहसास कराता है. लिहाजा काम के दौरान हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, यह मायने रखता है.

आजकल ऑफिस का कामकाज डिजिटल हो गया है और महामारी ने इस बदलाव को तेज कर दिया है. संचार और उत्पादकता उपकरणों ने डिजिटल कार्य को अधिक कुशल और कम बोझिल के साथ उसे कारगर बनाने में मदद की है. हालांकि, जो बात अच्छी तरह से नहीं समझी गई वह है कि हम कैसे काम करते हैं—क्या हम सभी एक तरह से काम करते हैं, हम कहां अलग होते हैं, किस चीज में मजा आता है, हमें क्या उबाऊ, निराशाजनक या कष्टदायक लगता है आदि. काम पर अपने अनुभव को बदलने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि हम कैसे काम करते हैं.

लोगों से जुड़ने, नौकरी तलाशने, बिल्ली की तस्वीरें साझा करने आदि में हमारी मदद के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने में अरबों रुपए निवेश किए गए हैं. लेकिन इसकी तुलना में कामकाज के मानवीय अनुभव को समझने और बेहतर बनाने की तकनीक में काफी कम निवेश किया गया है. मिसाल के तौर पर—आपने आखिरी बार ऐसे तकनीकी नवाचारों के बारे में कब सुना था जिनसे टीमों को काम पर परामर्श के अवसर खोजने, निराशाओं को कम करने, मदद तलाशने या दुख साझा करने में सहायता मिल सके?

यह समस्या कितनी बड़ी है? दुनिया भर में अनुमानित 50 करोड़ से अधिक ऑफिस कर्मचारी हैं जो हर दिन कम-से-कम 5 घंटे डिजिटल काम पर बिताते हैं. दुनिया ऑफिस के काम पर खरबों डॉलर खर्च करती है, फिर भी कर्मचारियों के अनुभव में सुधार एक अनिवार्य आर्थिक मुद्दा नहीं बन सका है जिसे तकनीक सहज कर सकती है. आखिर में, महामारी ने ऑफिस कर्मचारियों के बड़े हिस्से को घर में आइसोलेट कर दिया. इससे उन्हें दुनिया भर में नौकरियां बदलने के अधिक अवसर मिले. ऐसे में प्रतिभा को एक जगह बांधे रखना कठिन हो गया है. इसलिए, कर्मचारियों के अनुभव की परवाह करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है.

संस्थान इन चिंताओं पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन तकनीक में पर्याप्त नवाचार की कमी की वजह से ये बेअसर साबित होती हैं. मिसाल के तौर पर, कंपनियां ऐसे लोगों को रखती है जो विभिन्न टीमों में से कुछ लोगों का मैन्युअली इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के जरिये आंकड़े इकट्ठा करते हैं और फिर सलाह देते हैं कि काम को किस तरह कारगर बनाया जाए. लेकिन यह तरीका अपूर्ण, साधारण और अपनाने योग्य नहीं है. क्या तकनीक बेहतर समाधान पेश कर सकती है?

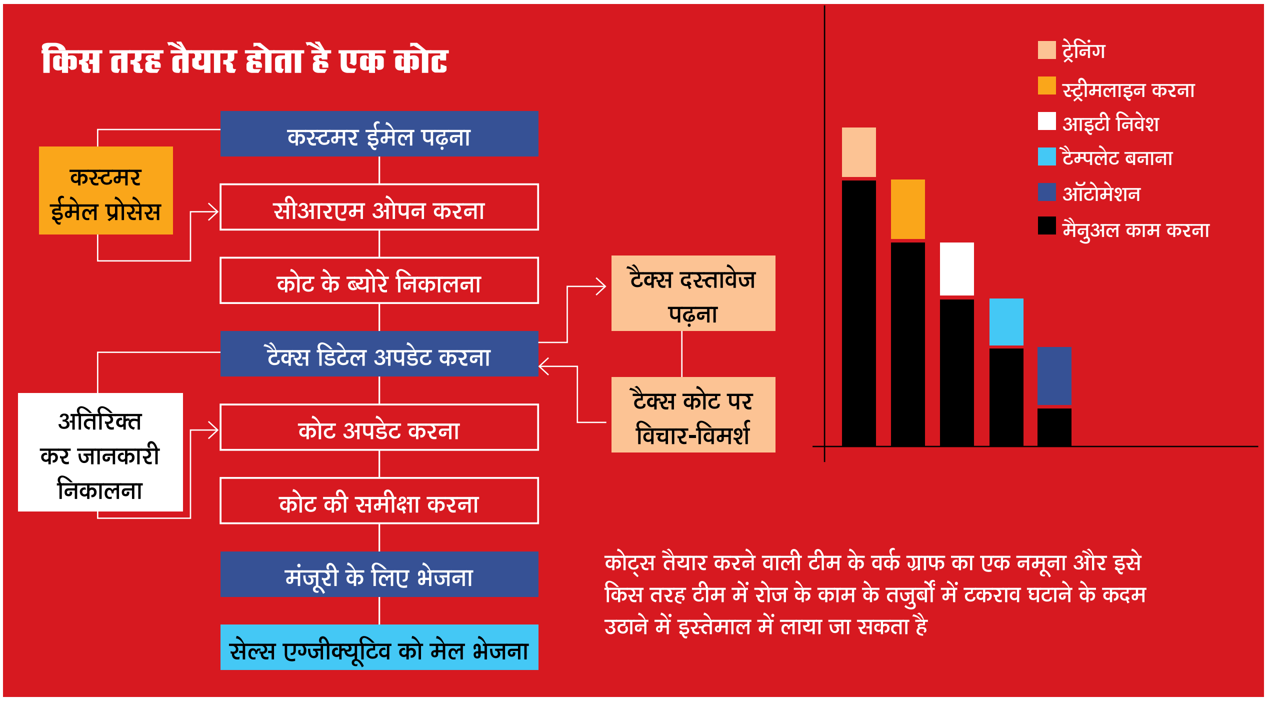
किस तरह तैयार होता है एक कोट

कोट्स तैयार करने वाली टीम के वर्क ग्राफ का एक नमूना और इसे किस तरह टीम में रोज के काम के तजुर्बों में टकराव घटाने के कदम उठाने में इस्तेमाल में लाया जा सकता है

यहां एक संभावना है. कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग में हालिया प्रगति कर्मचारियों के अनुभव को समझने और सुधारने के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल करने के नए साधन प्रदान करती है. इस तरीके में शामिल है: (1) नमूने लेना कि टीमें काम के दौरान सॉफ्टवेयर के साथ कैसे पेश आती हैं, (2) इस डेटा के बारे में मशीन लर्निंग से टीम के काम का पैटर्न समझना और (3) इन पैटर्न से टीम की समस्याओं की पहचान करना और टीम के अनुभव में सुधार करना. इस पद्धति में गोपनीयता की खातिर व्यक्ति को अनाम रखकर टीम पैटर्न पर ध्यान केंद्रित किया जाता है.

इसमें मुख्य अंतर्दृष्टि काम को डेटा के स्रोत के रूप में मानना है, जबकि पारंपरिक तरीकों में केवल काम के नतीजे को ही डेटा माना जाता है (जैसे, किसी टीम ने कितने लेनदेन पूरे किए?). यह डेटा तब कार्यस्थल पर बदलाव लाने के लिए उपयोगी होता है. इस नजरिये के केंद्र में 'वर्क ग्राफ' हैं—ऐसा खाका जो चरणों का जुड़ा हुआ क्रम है जिसे टीमें काम पूरा करने के लिए निष्पादित करती हैं. काम के दौरान टीमें सॉफ्टवेयर के साथ किस तरह पेश आती हैं, इसे समझने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए वर्क ग्राफ अपने आप बनते हैं और किसी भी पैमाने पर काम को समझने के लिए एक आधार का निर्माण करते हैं. टीमें किस तरह किसी कार्य को पूरा करती हैं, इसका खाका वर्ल्ड वाइड वेब के ग्राफ की तरह होता है जो सर्च इंजनों को ताकत देता है या लोगों के बीच जुड़ाव (सोशल ग्राफ्स) को जो अधिकतर सोशल प्लेटफॉर्म को क्षमता प्रदान करती हैं.

डिजिटल काम कैसे होता है, वर्क ग्राफ इसके डीएनए की तरह है. यह डीएनए की तरह ही वर्क ग्राफ डेटा के जरिये विभिन्न समस्याओं को समझने, उनका इलाज और समाधान करने के लिए सूचनाओं का एकमात्र स्रोत है.

वर्क ग्राफ के पैटर्न से काम पर किसी टीम के अनुभव को सुधारा जा सकता है. इस तरह, विभिन्न तरह की गहरी समझ हासिल की जा सकती है: उदाहरण के रूप में, आइटी और टेक्नोलॉजी को लेकर निराशा जो टीम के दैनिक अनुभवों को चोट पहुंचाती है, विभिन्न टीमों में काम के पैटर्न समान हैं इसलिए मार्गदर्शन या सीखने के अवसर, काम के टूटे हुए पैटर्न से टीमों के थकाऊ और अनावश्यक जटिलताओं का खुलासा होता है. काम के ग्राफ के विकल्प में लोगों के इंटरव्यू पर निर्भर रहना, अनुमान लगाना, तत्काल समझ लेने का गुण और संगठनों में बदलाव से उम्मीद करना शामिल है. हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में हाल ही के एक लेख में वर्क ग्राफ का इस्तेमाल करके खुलासा किया गया कि प्रबंधन टीमों से कैसे काम करने की अपेक्षा करता है और हकीकत में लगभग 60 फीसद का अंतर होता है. इसलिए, टीम को लाभ पहुंचाने के लिए बदलाव करने से पहले इन संगठनों को पहले अपनी टीम के काम के अनुभवों को बेहतर ढंग से समझना चाहिए.

वर्क ग्राफ के डेटा सोशल मीडिया से भी बड़ा लगता है. सोशल मीडिया को व्यापक रूप से बड़ी मात्रा में डेटा पैदा करने के लिए जाना जाता है जो व्यवसायों को ऊर्जा देता है. मिसाल के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर एक इंटरैक्शन (उदाहरण के लिए, किसी उपयोगकर्ता ने "जॉब तलाश करें" पर क्लिक किया या "कोई कमेंट लाइक" किया), की तुलना में काम पर 40 गुना अधिक डिजिटल इंटरैक्शन होते हैं (उदाहरण के लिए,"एक ईमेल भेजा गया"). आखिरकार, दुनिया काम के दौरान डिजिटल उपकरणों पर रोजाना 6-8 घंटे बिताती है और इन गतिविधियों के पीछे डेटा होता है.

अब तक दुनिया ने यह नहीं देखा है कि हम तकनीकी समस्या के रूप में काम को किस तरह अनुभव करते हैं. लेकिन महामारी ने इसे बदल दिया है. दुनिया में ऑफिस कार्य के पैमाने को देखते हुए, कार्यस्थल के भीतर यह कंज्यूमर स्केल का अवसर है. मेरा मानना है कि यह साल 2022 का एक मुद्दा होगा.

रोहन मूर्ति *सोरोको के संस्थापक और मुख्य टेक्निकल ऑफिसर हैं*

इलस्ट्रेशनः राज वर्मा

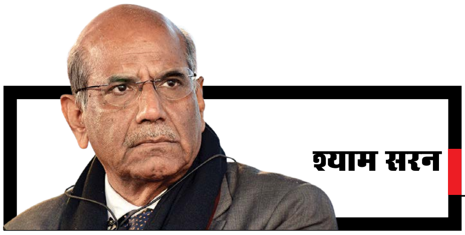

श्याम सरन भू-राजनीतिक परिदृश्य

वक्त एक्ट ईस्ट नीति पुनर्जीवित करने का

वैश्विक अर्थव्यवस्था को ओमिक्रॉन की चुनौती, अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होने से आतंकी समूहों की हिम्मत में बढ़ोतरी और चीन की भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भारत के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां पेश करती हैं

नया सामान्य जो भी है, बस 'सामान्य' नहीं है. हम जिस साल को पीछे छोड़ आए हैं, 2022 उससे भी ज्यादा अप्रत्याशित होने वाला है. कोविड-19 वायरस लगातार रूप बदल रहा है और दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है. जब हम सोच रहे थे कि हमारा सबसे बुरा समय निकल गया, उसी समय और तेजी से फैलने वाला ओमिक्रॉन संस्करण दुनिया भर में फैल रहा है. हिचकते-हिचकते खोली जा रही सीमाएं फिर एक झटके में पूरी ताकत से बंद की जा रही हैं. धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहे एयरलाइन व्यवसाय को एक बार फिर भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है और अधिकांश सेवा उद्योगों जैसे कि होटल, रेस्तरां, यात्रा और खुदरा विक्रय को फिर से गंभीर नुकसान होगा. प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्थाओं ने पिछले दो वर्षों में अनुमानतः 11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 819 लाख करोड़ रुपये) खर्च करके महामारी से उपजे स्वास्थ्य संकट और विकट आर्थिक-सामाजिक व्यवधानों का सामना किया है. एक और वर्ष तक इतना बड़ा परिव्यय बनाए रखने का गोला-बारूद इन अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक शस्त्रागार में नहीं बचा है.

हम तेज मुद्रास्फीति की शुरुआत देख रहे हैं. वर्ष 2022 में इसके और धारदार होने की संभावना है. इसकी प्रतिक्रिया में यदि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाने और हाल के दिनों में निर्मित अतिरिक्त तरलता घटाने का निर्णय करते हैं, तो भारत सहित सभी विकासशील देशों से बड़ी मात्रा में बाहर की ओर वित्तीय प्रवाह होने की संभावना होगी. उनके लिए विदेशी कर्ज की लागत बढ़ जाएगी. विकसित और विकासशील दोनों श्रेणी की अर्थव्यवस्थाओं के लिए

इलस्ट्रेशनः सिद्धांत जुमडे

2022 अधिक चुनौतीपूर्ण वर्ष होगा लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, इसमें विकासशील देशों को ही सबसे अधिक नुकसान होगा. हाल ही में भारत ने आर्थिक स्थिति के सामान्य की ओर वापसी के कुछ स्वागत योग्य संकेत देखे हैं, लेकिन इन्हें जारी रखना मुश्किल होगा.

चीन ने ही सबसे पहले कठोर लॉकडाउन लागू किया था और हाल ही में उसने फिर से इसे शुरू किया है. चीन पर इनके आर्थिक प्रभाव काफी हद तक स्वास्थ्य उपकरणों और दवा सामग्री के निर्यात में वृद्धि से समाप्त हुए थे. अत्यधिक अस्त-व्यस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन अपेक्षाकृत आर्थिक स्थिरता का द्वीप बन गया था जिससे इसका भू-राजनीतिक व्यक्तित्व मजबूत हुआ था. लेकिन नए साल की ओर बढ़ते हुए चीनी अर्थव्यवस्था की कमजोरियां दिखने लगी हैं. चीन की 2022 में संभावित 5 प्रतिशत की धीमी वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था में 280% से अधिक का ऋण और जीडीपी रेश्यो अवहनीय लगता है. एक और कमजोरी संपत्ति व निर्माण क्षेत्रों से संबंधित है, जिसका चीन के विकास में लगभग 30 प्रतिशत योगदान है. सबसे बड़ी रियल एस्टेट फर्म, एवरग्रांडे, दिवालियापन का सामना कर रही है और अन्य कंपनियां भी गंभीर संकट में हैं. यह स्थिति आर्थिक और वित्तीय संकट ला सकती है जिसे चीन की सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था में भी संभालना मुश्किल हो सकता है. महामारी ने देश की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और कई साझेदार देशों में ऋण जोखिम और राजनीतिक विरोध संबंधी चिंताएं सामने आई हैं. धीमी पड़ती चीनी अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था की तुलना में बड़ी समस्या पैदा कर सकती है क्योंकि वैश्विक स्तर पर विकास को संचालित करने वाला चीन जितना बड़ा दूसरा कारक नहीं है.

इन स्थितियों के बीच भू-राजनीति भंवर में है और इसके और भी अस्थिर होने की संभावना है. इसका महत्वपूर्ण समीकरण चीन और अमेरिका के बीच है. वैश्विक आर्थिक संकट 2008 के बाद से चीन जान चुका है कि वैश्विक शक्ति संतुलन को उसने मौलिक रूप से अपने पक्ष में झुकाते हुए महत्वपूर्ण रणनीतिक अवसर के दौर में प्रवेश कर लिया है. उसकी मुखर और आक्रामक विदेश नीति भी इसी धारणा पर टिकी हुई है. क्या चीन 2022 में अपने चरम को पार कर लेगा और क्या इसका परिणाम उसकी ''भेड़िया योद्धा कूटनीति'' को सीमित करने के रूप में हो सकता है? या, वह अपने हितों की लगातार बढ़ती उत्पीड़नकारी तथा एकपक्षीय दावेदारी पर दोगुनी ताकत लगाएगा—उसके ये हित हैं जो उसकी शक्ति बढ़ने के साथ-साथ बड़े हुए हैं? दोनों में से कोई भी प्रवृत्ति ताइवान के खिलाफ कार्रवाइयों और भारत-चीन सीमा पर उसके रुख में स्पष्ट रूप से दिख सकती है.

चीन शक्ति को सापेक्ष दृष्टि से देखता है. भले ही वह नीची वृद्धिदर और अति-विस्तार के चरण में प्रवेश कर रहा हो, फिर भी अफगानिस्तान से तेजी से और अराजक तरीके से अमेरिकी वापसी के कारण अमेरिका की विश्वसनीयता के बारे में इसकी धारणा और भी कमजोर हुई है. यह आश्वस्त होने के कारण कि अमेरिका के पास लड़ाई का माद्दा नहीं होगा, वह ताइवान मुद्दे का हल अपने पक्ष में करने के लिए उसकी कठोर नाकेबंदी या सैन्य कार्रवाई से कब्जा हासिल करने के लालच में पड़ सकता है. नया साल चीनी गणनाओं के संबंध में पहले से अधिक ठोस सुराग दे सकता है, लेकिन इसमें ताइवान जलडमरूमध्य में तनाव का बढ़ना तय हैं. इसके अतिरिक्त, यदि क्वाड के सहयोगी देश, जिनकी ताइवान मुद्दे में नई दिल्ली की तुलना में अधिक भागीदारी है, इस संगठन की अधिक औपचारिक और अधिक स्पष्ट सैन्य भूमिका के लिए दबाव डालते हैं, तो भारत को कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ सकता है. इससे भारत को चीन से जमीनी सीमा पर अधिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है.

क्वाड के सहयोगी देश ताइवान के मसले पर अधिक प्रत्यक्ष भूमिका निभाने का दबाव डाल सकते हैं. इससे भारत को चीन से जमीनी सीमा पर अधिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है

अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा भारत के लिए झटका है. इससे पाकिस्तान को भू-राजनीतिक लाभ मिला है, भले ही वह अल्पकालिक हो. पाकिस्तान ने सुनिश्चित किया है कि काबुल में सत्ताधारी दल में प्रमुख गुट हक्कानी समूह हो, जिसे पेंटागन के पूर्व प्रमुख माइक मुलेन ने ''आईएसआई की वास्तविक शाखा'' के रूप में वर्णित किया था. यह हक्कानी समूह ही है जिसने आईएसआई की ओर से अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास और भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया था. इस देश में भारत की ओर से किसी भी रूप में अपनी उपस्थिति पुनर्जीवित करने का कोई भी प्रयास हमेशा जोखिम भरा होगा. जब देश अकाल और आर्थिक पतन का सामना कर रहा होगा तब भारतीय मानवीय और आर्थिक सहायता का स्वागत किया जाएगा, लेकिन इससे भारत को कोई सार्थक लाभ नहीं मिलेगा.

अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा उन जिहादी गुटों का मनोबल काफी बढ़ाने वाला रहा है, जिनका ध्यान पहले से जम्मू-कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों पर है. चीन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के लिए अधिक शक्तिशाली ढाल बनेगा, जिससे सीमापार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने के भारतीय प्रयासों को निराशा होगी. काबुल में राजनीतिक परिवर्तन से उत्पन्न सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए भारत ने क्षेत्रीय देशों के साथ समन्वय की दिशा में अच्छा काम किया है. गणतंत्र दिवस पर मध्य एशियाई देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना एक कल्पनाशील कदम है, लेकिन इसके वास्तविक प्रभाव को बढ़ा कर नहीं आंका जाना चाहिए.

उम्मीद की जानी चाहिए कि 2022 ऐक्ट ईस्ट नीति को पुनर्जीवित किए जाने का वर्ष होगा. इसकी कुंजी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते पर लौटने में है. भारत ऐक्ट ईस्ट के आर्थिक और वाणिज्यिक पक्षों से दूर नहीं रह सकता. इसे एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) का सदस्य बनने का आवेदन भी नए सिरे से करना चाहिए, जिसमें व्यापार रियायतें भले नहीं मिलतीं तथापि भारतीय व्यापार और उद्योग के लिए नेटवर्किंग और सीखने का मंच मिलता है. भारत एकमात्र क्वाड सदस्य है जो एपीईसी का सदस्य नहीं है. इसे सदस्यता पाने के लिए क्वाड में अपनी उपस्थिति का लाभ उठाना चाहिए. ये कुछ ऐसी पहलें हैं जो भारत को अप्रत्याशित और नई चुनौतियों से भरे एक और वर्ष से पार पाने में मदद कर सकती हैं.

श्याम सरन *पूर्व विदेश सचिव और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली में सीनियर फेलो हैं*

एंड्रयू स्माल

चीन और भारत

ड्रैगन के निशाने पर

संकटों में इजाफा और एकाधिक मोर्चों पर शत्रुतापूर्ण संबंधों के साथ आगे बढ़ने की चीन की बढ़ती फितरत के चलते नया वर्ष दक्षिण एशिया के लिए उथलपुथल भरा होने वाला है जिसके केंद्र में भारत होगा

चीन के विश्लेषक लगातार इसके आदी होते जा रहे हैं कि बीजिंग का रवैया किसी खास स्थिति में क्या हो सकता है, इस पर नए सिरे से सोचा जाए, क्योंकि यह उसके अतीत के रवैए से तय नहीं होगा. दक्षिण एशिया और दूसरी जगहों पर भी लंबे समय से चली आ रही विदेश नीति के मानकों और समझौतों को उलट देना चीनी नजरिए के मामले में अब आम हो गया है.

सिद्धांत रूप में, 2022 पिछले दो वर्षों की तुलना में अधिक स्थिर वर्ष होना चाहिए. आगामी पार्टी कांग्रेस के मद्देनजर आम तौर पर कोई भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव बाहरी वातावरण में शांति बनाए रखना चाहेगा. लेकिन इसे गारंटी मान कर नहीं चला जा सकता. निश्चित रूप से यह तय करने की कोशिश होगी कि शरद ऋतु में शी जिनपिंग जब अपनी सत्ता को मजबूत करने अगले चरण में प्रवेश कर रहे होंगे, तब उनको किसी अप्रिय आश्चर्य का सामना न करना पड़े. लेकिन कोविड-19 महामारी के शुरुआती चरणों के दौरान चीनी रवैए से स्पष्ट हो चुका है कि बचाव और असुरक्षा की अवधि और अधिक आक्रामकता और अत्याचार-उत्पीड़न के नए-नए तरीकों को जन्म देती है, न कि सुलह-सफाई की प्रवृत्तियों को.

चीन में संकटों को बड़ा करने की भूख पहले से ज्यादा है और जाहिर है कि वह खुद को कई मोर्चों पर विरोधी संबंधों के साथ जीने में सक्षम मानता है. यह तथ्य भी नहीं भुलाया जाना चाहिए कि पिछली पार्टी कांग्रेस के आयोजन के पहले डोकलाम टकराव का बीज बो दिया गया था. संभव है कि हम हिमालयी सीमाओं के प्रति चीन का पहले से ज्यादा व्यामोह और उस

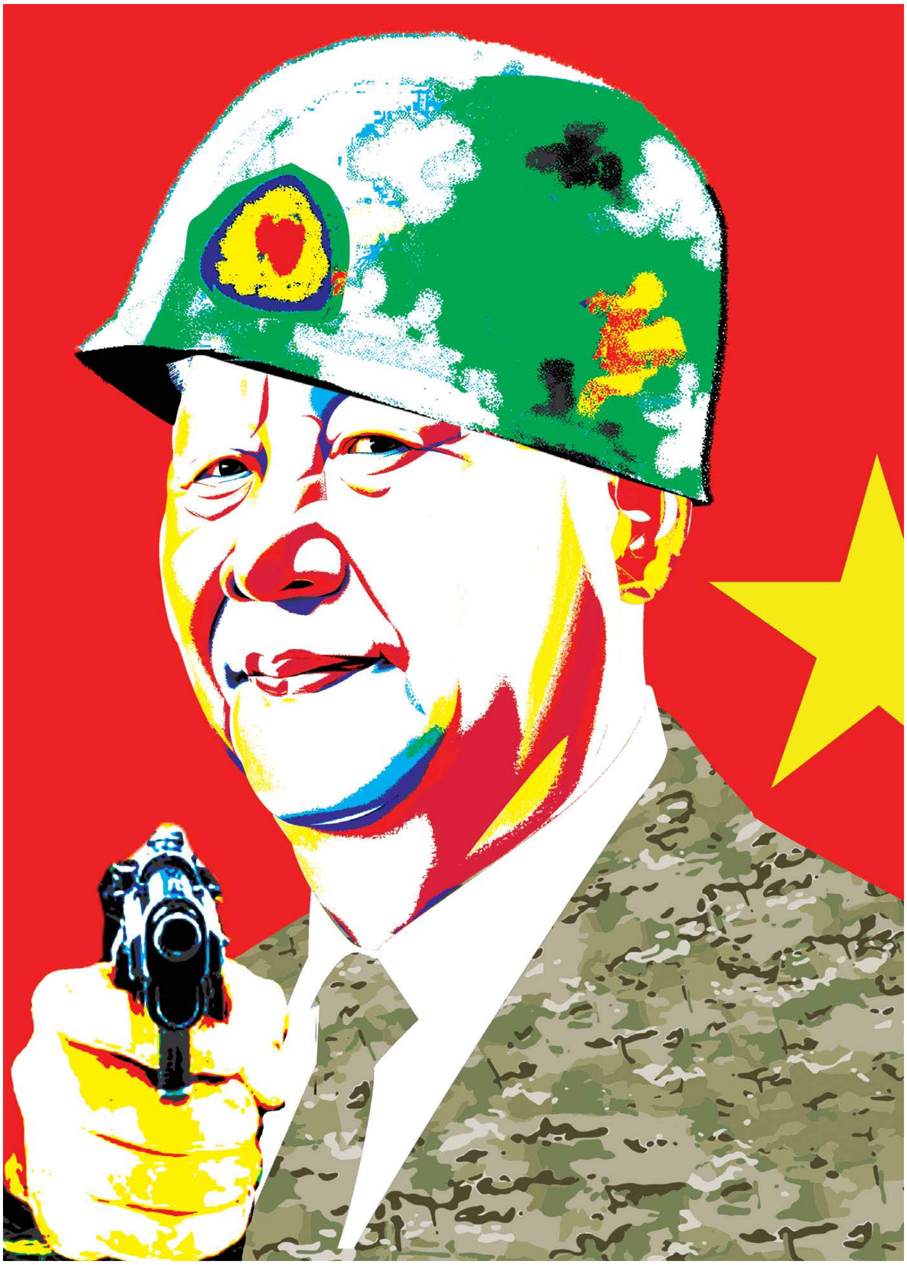

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

साल की गई उन गलतियों को न दोहराने का दृढ़ संकल्प देखें जिनके कारण उसे लगा था कि उसे बचाव की मुद्रा अपनानी पड़ी.

हालांकि चीन की सत्तारूढ़ पार्टी का पंचवर्षीय सम्मेलन का असर 2022 के बड़े हिस्से पर पड़ेगा, लेकिन ऐसी बड़ी वजहें भी हैं, जो इस क्षेत्र में चीन के रवैये को प्रभावित कर सकती हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है वाशिंगटन के साथ बीजिंग के संबंधों का स्वरूप. चीन के साथ संवाद करने वाले लगभग हर देश ने यह अनुभव किया है कि वह अपने द्विपक्षीय संबंधों को उस बड़े टकराव से अलग करके देखने को तैयार नहीं है, जो वह अमेरिका के साथ बढ़ता देखता है. चीन का मुख्य सिरदर्द केवल वाशिंगटन ही नहीं है, बल्कि क्वाड, एयूकेयूएस, जी 7 और अन्य समूहों के साथ संतुलनकारी करार भी हैं जो बाइडेन प्रशासन के अधीन अमेरिकी नीति का केंद्र बने हैं और जिन्हें शी 'छुटभैए गुट' की संज्ञा देते हैं. ये करार टिकते हैं और गहराते हैं, तो वे शक्ति का एक दीर्घकालिक वैश्विक संतुलन तैयार करेंगे जो हिंद-प्रशांत सुरक्षा से लेकर तकनीकी होड़ तक, कई क्षेत्रों में चीन के विरुद्ध काम करेंगे.

भारत इन अतिव्यापी गठबंधनों में से कई के केंद्र में है और उम्मीद की जानी चाहिए कि चीन उसे द्विपक्षीय संबंधों के बजाय ज्यादातर मौकों पर भू-राजनीतिक विचारों के चश्मे से देखगा और उसी तरह व्यवहार करेगा. चीनी कूटनीति के इस अधिक चपल चरण में विभिन्न देशों को वाशिंगटन से अलग होने और दूरी बनाए रखने पर लाभन्वित करने के प्रयास हो सकते हैं. चीन के अधिक परिष्कृत विदेश नीति जानकारों की चिंता का मुद्दा है कि आजकल बीजिंग लगभग हर मामले में लट्ठबाजी कर रहा है.

इससे क्षेत्र में ब्लॉक राजनीति की ओर दीर्घकालिक रुझान तेज होता है. अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता, गहराते अमेरिका-भारत संबंध, कमजोर पड़ते अमेरिका-पाकिस्तान संबंध, चीन-पाकिस्तान का पहले से ज्यादा निकटता के साथ जुड़ाव, और बिगड़ते चीन-भारत संबंध दक्षिण एशिया की अतीत में पतली राजनीतिक रेखाओं को मोटा करती हैं. यह चीन के मित्रों के लिए भी असहज करने वाला प्रसंग है. पाकिस्तान दशकों से वाशिंगटन और बीजिंग के साथ अपने संबंधों का निर्वाह करता रहा है जो आम तौर पर बिना किसी बाधा के एक साथ चल रहे थे. अब विभिन्न क्षेत्रों में 'पक्ष चुनने' के लिए दबाव बढ़ रहा है, और पाकिस्तान की प्राथमिकता अभी भी चीन पर बहुत बुरी तरह से निर्भर होने से बचने की है, फिर भी किसी तरह की पैंतरेबाजी की जगह कम होती जा रही है.

संरचनात्मक कारक दोनों पक्षों को एक साथ और अधिक निकटता से आगे बढ़ा रहे हैं, यह स्थिति चीन-पाकिस्तान संबंधों में किसी सुनहरे दौर से बहुत दूर है. दोनों देशों के संबंधों को व्यापक आधार प्रदान करते हुए महत्वाकांक्षी स्तर पर ले जाने वाली चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) परियोजना ठप हो गई है. कई वर्षों से, पाकिस्तान में घरेलू, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति ने न केवल दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण नई परियोजना के लिए राजी होने के विरुद्ध बाधाओं की श्रृंखला खड़ी की है, बल्कि ग्वादर बंदरगाह जैसी मौजूदा प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन में भी अड़चन पैदा की है.

हाल में सुरक्षा की स्थिति भी खराब हुई है. पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा के दसू में बम विस्फोट किसी सीमा तक पाकिस्तान में चीनी कर्मियों पर सबसे बड़ा हमला था. इसके अलावा करीब से चूक जाने वाली घटनाओं की संख्या भी काफी परेशान करने वाली थी. बीजिंग इन घटनाक्रमों को अफगानिस्तान की स्थिति से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ मानता है. अमेरिका की वापसी के बाद चीन का डर इस बात को लेकर कम था कि अफगानिस्तान में क्या हो सकता है, जहां उसके हित न्यूनतम हैं, लेकिन उसे व्यापक क्षेत्र, खास तौर पर पाकिस्तान में उसके प्रभाव की चिंता ज्यादा थी. सीपीईसी के लिए पहले से ही खराब स्थिति में चीन की सावधानी का स्तर बढ़ने से उम्मीद की जा सकती है कि इस पहल में कमजोरी नए वर्ष में बनी रहेगी, क्योंकि कोई भी बड़ी परिवर्तनकारी उम्मीद नजर नहीं आती.

अमेरिका-चीन दुश्मनी से भारत-अमेरिका संबंध गहरे हो रहे हैं और चीन-पाकिस्तान के बीच गहरे होते रिश्तों का मतलब है दक्षिण एशिया में राजनैतिक रेखाओं का और ज्यादा पुख्ता होना. यह तनाव की स्थितियां बढ़ा सकता है और क्षेत्र में अशांति का कारण बनेगा.

यही सतर्कता सीमाओं पर बीजिंग की नीति की खासियत होगी. इसके बावजूद चीन तालिबान सरकार के साथ अच्छे कामकाजी संबंध रखने वाले कुछ देशों में से एक है, बीजिंग को इस मामले में तालिबान की ताकत पर भरोसा नहीं है कि वह उसकी आर्थिक परियोजनाओं को जोखिम में डाल सकता है. इसलिए, चीन का समर्थन मानवीय सहायता, मामूली व्यापार और कुछ छोटी परियोजनाओं तक सीमित रहेगा. यह सब बढ़ सकता है, बशर्ते सुरक्षा स्थिति इसकी अनुमति दे और चीन सरकार राजनीतिक मांगों पर, विशेष रूप से उग्रवादी उइगुरों का दमन रोकने की दिशा में आगे बढ़े. व्यावहारिक स्तर पर इसका मतलब हो सकता है कि चीन प्रमुख परियोजनाओं पर वर्षों तक धीमी गति से काम करे और देश के मुश्किल से निकाले जा सकने वाले खनिज संसाधनों के प्रति कोई उत्साह दिखाने के बजाय खतरों की रोकथाम और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करे. अमेरिका के साथ व्यापक प्रतिस्पर्धा में बीजिंग अभी भी अफगानिस्तान को एक जाल के रूप में देखने का आदी है.

आने वाले समय में महाद्वीपीय एशिया के खाली किए गए स्थानों के बारे में फंसने से बचने के प्रति सावधानी के साथ शेष दक्षिण एशिया में तेज होती भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के मद्देनजर चीन अपने दृष्टिकोण में विविधता ला सकता है. एक क्षेत्र को देनदारियों के संभावित सेट के रूप में देखा जा सकता है, जहां चीन की जोखिम उठाने की क्षमता घट गई है, जो कुछ साल पहले बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव निवेश के दौरान थी. दूसरा क्षेत्र प्रतिस्पर्धा के तेजी से 'गर्माते' रंगमंच के रूप में देखा जा सकता है, जहां वह अतीत के व्यावहारिक, धैर्यवान, विवेकपूर्ण और एक जैसे रवैए को छोड़ कर अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए तैयार है. भारत की सीमाओं पर बीजिंग पहले ही इस बात को दिखा चुका है.

एंड्र्यू स्माल *अमेरिका के जर्मन मार्शल फंड में वरिष्ठ ट्रान्स अटलांटिक फेलो हैं.*

सुनीता नारायण

ऊर्जा व्यवस्था की साफ-सफाई

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग में भारत की असली चुनौती बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं, बल्कि यह तय करने की होगी कि निपट निर्धन व्यक्ति भी 'स्वच्छ' ऊर्जा की कीमत चुका सके

जब मामला जलवायु परिवर्तन का हो तो इस चुनौती से लड़ने के लिए दुनिया और भारत के तरीके में तीन हकीकतें शामिल होनी चाहिए. पहली बात, हमें जीवाश्म ईंधनों को जलाने से उत्पन्न उत्सर्जन की वजह से विकट होती जलवायु की हकीकत को स्वीकार करना चाहिए, जिससे पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है. इसलिए दुनिया को फौरन तेज रफ्तार से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए काम करना चाहिए. इस पर कोई तर्क–वितर्क नहीं होना चाहिए.

दूसरी बात, मुख्यत: जीवाश्म ईंधनों को जलाने से उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैस आर्थिक वृद्धि से जुड़े हैं और इससे भी अहम बात यह है कि वायुमंडल में ये उत्सर्जित गैस लंबे समय तक बनी रहती हैं. लिहाजा, जब दुनिया उत्सर्जनों से निबटने की बात करती है तो वह राष्ट्रों और पीढ़ियों के बीच साझेदारी पर चर्चा करती है. इसीलिए उत्सर्जन कम करने के लिए वैश्विक कार्रवाई अलग और इस समस्या में विभिन्न देशों के योगदान पर आधारित होनी चाहिए. जलवायु न्याय कोई नैतिक नहीं बल्कि जरूरी पूर्व शर्त होनी चाहिए.

तीसरी बात, भारत जैसा देश, जिसने वायुमंडल में भारी प्रदूषण नहीं फैलाया है बल्कि खुद जलवायु परिवर्तन का शिकार है—हमारी दुनिया में आज भीषण उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों या विकट मौसम और अत्यधिक बारिश की वजह से गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित हैं—को अपने हित में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए. भारत को न सिर्फ पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए ऐसा करना चाहिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना चाहिए कि तेजी से बिगड़ते पर्यावरण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खराब प्रभाव को कम किया जा सके.

यहीं हमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की

इलस्ट्रेशनः **नीलांजन दास**

उन घोषणाओं को मानना चाहिए जो उन्होंने हाल में ग्लासगो में आयोजित क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस (कॉप26) में की थी. वहां सबसे अहम वादा यह किया गया कि भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50 फीसद हिस्सा अक्षय ऊर्जा के स्त्रोतों से हासिल करेगा. यह बहुत बड़ी बात है—इस पर कोई सवाल नहीं है. हकीकत यह है कि ऊर्जा व्यवस्था में बदलाव करके ही दुनिया में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी. इस तरह से भारत यह कह रहा है कि भविष्य में उसका ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर 'हरित' होगा—देश कोयले का इस्तेमाल नहीं छोड़ेगा लेकिन इस काले हीरे पर अपनी निर्भरता को जबरदस्त रूप से कम कर देगा, जिसे जलवायु परिवर्तन करने वाली गैसों के लिए जिम्मेदार माना जाता है.

अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं. फिलहाल, अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए भारत की कोयले पर निर्भरता बहुत ज्यादा है—2019 में कोयला आधारित बिजली स्थापित क्षमता की 63 फीसद थी और उससे देश की 80 फीसद ऊर्जा जरूरत पूरी हुई. लेकिन अगर इस योजना को कामयाब बनाना है तो 2030 तक देश को यह स्थिति बदलनी होगी. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के मुताबिक, कोयला आधारित ऊर्जा पर निर्भरता करीब 56 फीसद कम हो जाएगी और बाकी जरूरतें अक्षय ऊर्जा के स्त्रोतों से पूरी की जाएंगी. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत को अपने मौजूदा अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को 100 गीगावाट से बढ़ाकर 2030 तक 650-700 गीगावाट करना होगा जबकि कोयला आधारित ऊर्जा 280 गीगावाट होगी यानी अभी से मामूली तौर पर ज्यादा. यह बहुत बड़ा काम लगता है और ऐसा लगना भी चाहिए. लेकिन यह मुमकिन है बशर्ते हम सोच-समझकर और कल्पनाशीलता के साथ योजना बनाएं.

हकीकत यह है कि हमें अपने करोड़ों लोगों के जरूरी जीविकोपार्जन और उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी ऊर्जा व्यवस्था में आमूल बदलाव की जरूरत है. आज भारत की ऊर्जा व्यवस्था इतनी बिखरी हुई है कि यह सबसे सस्ती ऊर्जा उत्पादन—कोयला आधारित ताप बिजली—को अपनाकर उसकी आपूर्ति करता है लेकिन वास्तव में वह दुनिया में सबसे महंगी हो जाती है. इसकी कई वजहें हैं; विकृत सब्सिडी व्यवस्था से लेकर, जिससे अंतत: उन्हीं गरीबों और किसानों का कोई फायदा नहीं होता जिनके नाम पर उसे दिया जाता है, से लेकर बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की नाकामियां और बड़े पैमाने पर चोरी शामिल हैं. लेकिन नतीजा यह है कि भारत ऊर्जा निर्धनता से विचलित है क्योंकि करोड़ों लोग अब भी अंधेरे रहते हैं और महिलाएं जलावन वाले चूल्हों पर खाना बना रही हैं, जो उनकी खुद की सेहत के लिए खराब है. दूसरी ओर, अपेक्षाकृत अमीर उपभोक्ता उसी बिखरी ऊर्जा व्यवस्था से बाहर जाकर जेनरेटरों के लिए डीजल से लेकर बॉयलर और कैप्टिव बिजली संयंत्रों के लिए कोयला और पेटकोक जैसे उससे भी ज्यादा गंदे विकल्प अपना लेते हैं. इन सबका स्वास्थ्य पर जानलेवा असर पड़ता है क्योंकि कोयले का इस्तेमाल बेहद प्रदूषणकारी बिजली संयंत्रों और कैप्टिव बिजली संयंत्रों में बढ़ता है. यह सस्ता या टिकाऊ नहीं है. इसे बदलना ही होगा.

भारत कह रहा है कि भविष्य में उसका ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर हरित होगा-देश कोयले इस्तेमाल छोड़ेगा नहीं लेकिन इस पर अपनी निर्भरता को जबरदस्त रूप से कम कर लेगा

यहीं नई ऊर्जा व्यवस्था अपनी भूमिका निभा सकती है. लेकिन इसके लिए निवेश की जरूरत है, वह भी सिर्फ बुनियादी ढांचे के निर्माण में नहीं बल्कि स्वच्छ और सक्षम वितरण तथा आपूर्ति नेटवर्क को फिर तैयार करने के लिए. असली चुनौती बुनियादी ढांचे का निर्माण करना नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि निर्धनतम व्यक्ति भी 'स्वच्छ' ऊर्जा की कीमत चुका सके. समस्या का केंद्र यही है. हमें यह देखने के लिए कि स्वच्छ ऊर्जा किस तरह से सस्ती हो सकती है, अक्षय ऊर्जा से परे देखने की जरूरत है ताकि समावेशी विकास हो सके. यह जलवायु वित्त पोषण के इस्तेमाल का मौका है ताकि यह न केवल स्वच्छ ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए धन दे बल्कि उस लागत में अंतर की भी भरपाई करे जिससे इस ऊर्जा को सबके लिए सुलभ बनाया जाएगा.

लिहाजा, 2022 में क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले तो हमें देश में जलवायु परिवर्तन के लिए कार्रवाई करने की जरूरत है. इसे 'सामान्य' होना चाहिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर के लिए उत्सर्जन के विकल्प तैयार होने चाहिए तथा यह भी तय होना चाहिए कि हम बदलाव की निशानदेही कैसे करेंगे. हम हमेशा ऐसा करने के अनिच्छुक रहे हैं, ऐसा होने पर यह हमें उत्सर्जन कटौती के वैश्विक लक्ष्यों से बांध देगा. लेकिन हमें यह पीड़ा बर्दाश्त करनी होगी. हमें मालूम है कि आज प्रदूषण फैलाए बगैर, हमारे सामने विकास को नए सिरे से गढ़ने के विकल्प हैं. हम अपने उद्योग और शहर में आवाजाही के इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए अपनी ऊर्जा तैयार करेंगे. लिहाजा, यह इसे ज्यादा संसाधन सक्षम, ज्यादा सस्ता और नतीजतन ज्यादा टिकाऊ बनाने के लिए रिडिजाइन करने का मौका है. इस योजना के लिए आंकड़ों और 2030 तक की योजना बनाने और इसकी लागत जानने की जरूरत है—फंडिंग की यह जरूरत महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु वित्त पोषण को इस बदलाव का हिस्सा होना है.

साल 2022 का दूसरा एजेंडा जलवायु परिवर्तन के भीषण प्रभावों—बेहद बारिश की वजह से बाढ़ और अल्प वर्षा की वजह से सूखे से लेकर ट्रॉपिकल चक्रवातों या मौसम के दूसरे बदलावों की संख्या में वृद्धि—को दूर करने के लिए रणनीति तैयार करना है. हमें इन बदलावों को रोकने के लिए और वह भी जल्दी रोकने के लिए हस्तक्षेप की रणनीतियों की जरूरत है. मिसाल के तौर पर, किसानों को फसल की बर्बादी के लिए ज्यादा मुआवजे की जरूरत है और सरकार को इस चुनौती से निबटने के लिए बीमा योजना पर फिर से काम करना चाहिए. फिर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बारिश होने पर हमारे शहर डूब न जाएं—इसके लिए शहरी नवीकरण कार्यक्रम के तहत बस्तियों में झील, तालाब और हरित क्षेत्रों के संरक्षण पर ध्याना दिया जाना चाहिए. लेकिन सबसे बड़ा गेमचेंजर ग्रामीण भारत में जल संरक्षण और जीविकोपार्जन के हरित साधनों में निवेश करके बार-बार के झटकों के खिलाफ लचीलेपन की क्षमता विकसित करना होगा. मैं और भी उपाय बता सकती हूं. लेकिन 2022 में असली बदलाव यह होगा कि हम वजूद के इस खतरे के प्रति गंभीर हो जाएं.

सुनीता नारायण *डाउन टु अर्थ की संपादक और सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरनमेंट की डायरेक्टर हैं*

सिराज हुसैन
और
श्वेता सैनी

कृषि कानूनों के बाद कृषि

सुधारों की नई फसल पर जोर जरूरी

विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन ने भारतीय कृषि को जन चेतना के केंद्र में ला दिया. महत्वपूर्ण सुधारों की गति मंद नहीं पड़नी चाहिए

प्रधानमंत्री की ओर से तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को अचानक रद्द करने के ऐलान को कई लोग कृषि सुधारों की डगर के अंत के रूप में देख रहे हैं. लेकिन, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है. किसानों के 15 महीनों तक चले आंदोलन से मिले कुछ सबक ये हैं:

परामर्श बेहद महत्वपूर्ण हैं और निष्पक्ष दिखना जरूरी है

आंदोलन ने सरकार को यह एहसास करा दिया कि कृषि में सुधार करने के लिए समावेशी और व्यापक परामर्श होना चाहिए. 2022 में कृषि में संरचनात्मक सुधारों के भविष्य के लिए विशेषज्ञों और किसानों के प्रतिनिधियों के साथ सीधी बातचीत जरूरी हो सकती है. आखिरकार, प्रोत्साहन, निवेश, आयात/निर्यात, कर-निर्धारण आदि पर नीतियां बनाते वक्त सीआइआइ, फिक्की और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री की राय पर सरकार विचार करती ही है.

किसानों को पिछले कुछ वर्षों में दो सबसे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिए गए हैं—पारिवारिक श्रम की लागत (एफएल) के साथ-साथ भुगतान की गई लागत (ए2) पर न्यूनतम 50 फीसद एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) तय करना, और सालाना 6,000 रुपए पीएम-किसान योजना के तहत दिए गए. लेकिन, ये प्रोत्साहन किसानों या राज्य सरकारों

से परामर्श के बाद सामने नहीं आए हैं. ये केंद्र की ओर से एकतरफा घोषणाएं थीं. अब जब सरकार ने फसल पैटर्न, उर्वरक सब्सिडी और एमएसपी के भविष्य जैसे विवादास्पद मुद्दों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति की घोषणा की है, तो उम्मीद है कि विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के विशेषज्ञों और किसानों के प्रतिनिधियों को पैनल में नामित किया जाएगा.

राज्यों की वस्तुस्थिति के अनुसार सुधारों को तय करें

भारत के राज्य कृषि विकास के विभिन्न चरणों में हैं. उनमें संसाधन बंदोबस्ती और कृषि-पारिस्थितिकी समस्याओं से संबंधित विभिन्न बाधाएं हैं. इसलिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके हिसाब से नीतियों को तैयार करना होगा.

सुधारों के लिए स्थानीय जोर और व्यापक व्यावहारिकता की जरूरत

अन्य बड़े सबक में से एक यह है कि जहां सुधारों के नेतृत्व की जिम्मेदारी राज्यों को देने की जरूरत है, वहीं सुधारों को समग्र रूप से देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक और एकीकृत रूप से तैयार करने की जरूरत है. गेहूं, चावल और दलहन सरीखी अपनी मुख्य फसलों के अतिरिक्त बचत को नहीं रखना भारत गवारा नहीं कर सकता. 2022 में केंद्र को राज्यों की आकांक्षाओं/जरूरतों और देश की दीर्घकालिक जरूरतों के बीच मेल सुनिश्चित करने की जरूरत है.

कृषि के इन प्रमुख क्षेत्रों में 2022 में सुधार की जरूरत है:

उर्वरक सब्सिडी

उर्वरक से संबंधित सब्सिडी सबसे मुश्किल सुधारों में से एक है. लंबे समय से यह बहस चल रही है कि प्रति हेक्टेयर भूमि जोत के आधार पर उर्वरक सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) यूरिया के अत्यधिक उपयोग पर रोक लगा सकता है. वैश्विक कीमतों में भारी वृद्धि की वजह से केंद्र को उर्वरक सब्सिडी पर 1.55 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं जबकि 2021-22 के लिए अनुमानित बजट केवल 79,530 करोड़ रुपए है.

व्यापक काश्तकारी और भूमि को पट्टे पर देने के बावजूद, इसका केवल दसवां हिस्सा ही रिकॉर्ड में है (कृषि जनगणना के अनुसार). ऐसे में उर्वरक सब्सिडी का कोई भी डीबीटी केवल भूमिधारक तक पहुंचेगा, वास्तविक किसान तक नहीं. इसके अलावा, प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत में भारी अंतर होता है. 2019-20 में, केरल में प्रति हेक्टेयर 36.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की खपत हुई, जबकि बिहार में प्रति हेक्टेयर 245.3 किलोग्राम—देश में सबसे अधिक, यहां तक कि पंजाब के (243 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) से भी अधिक—की खपत हुई. ऐसे में उर्वरक सब्सिडी का एक समान डीबीटी आसान नहीं है.

> **भारत के शहरी मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि देश में खाद्य सुरक्षा काफी है. उन्हें इसका एहसास नहीं है कि कृषि उत्पादन का देश का अधिकांश अधिशेष (अतिरिक्त बचत) बहुत कम है. इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है**

खाद्य सुरक्षा

भारत के शहरी मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि देश में खाद्य सुरक्षा काफी है. उन्हें इसका एहसास नहीं है कि कृषि उत्पादन का देश का अधिकांश अधिशेष (अतिरिक्त बचत) बहुत कम है. इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है. अगर अर्थव्यवस्था वास्तव में हर साल 7-8 फीसद की दर से बढ़ती है और उनका लाभ जनता को मिलता है तो कृषि उत्पादों, खासकर प्रोटीन, फल और सब्जियों की मांग में इजाफा होगा और कुछ वस्तुओं की वर्तमान बचत खत्म हो जाएगी. इसलिए पैदावार में सुधार और नुक्सान को कम करने के लिए संयुक्त प्रयास बेहद जरूरी है.

कृषि पर जलवायु का प्रभाव

इस साल एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर तत्काल सहमति की जरूरत है, और वह है भारत के मूल हरित क्रांति क्षेत्रों, मसलन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृषि-पारिस्थितिकीय स्थिरता. इसी तरह से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में गन्ने की खेती टिकाऊ नहीं है.

गन्ने का क्षेत्र 1990-91 में 36.8 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2018-19 में 50.6 लाख हेक्टेयर हो गया है. मोटे तौर पर इस वृद्धि की मुख्य वजह नई किस्मों की आमद के साथ-साथ गन्ने की गारंटीकृत कीमतों की नीति है. नतीजतन, भारत सालाना 3.2 से 3.3 करोड़ टन चीनी का उत्पादन करता है जबकि इसकी घरेलू मांग केवल 25.5 लाख टन की है. किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करने में चीनी मिलों को सक्षम बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह के प्रोत्साहन दे रही हैं. फसल पैटर्न को लेकर बनने वाली विशेषज्ञ समिति न केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खेती, बल्कि विभिन्न राज्यों में गन्ने पर भी ध्यान देगी.

एपीएमसी को मजबूत करना और बुनियादी ढांचे में निवेश

साल 2020 में तीन कृषि कानूनों के लागू होने से पहले ही इस बात पर आम सहमति बन गई थी कि एपीएमसी (कृषि उपज बाजार समितियों) समेत कृषि विपणन में गंभीर सुधारों की जरूरत है. इन सुधारों में व्यापार लाइसेंस का उदार मुद्दा, सभी राज्यों में अधिकतम दो फीसद का एक समान बाजार शुल्क, एक राज्य में सभी एपीएमसी के लिए एकीकृत लाइसेंस और राज्यों के भीतर और बाहर कृषि उपज की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं, शामिल है.

किसानों के आंदोलन ने भारतीय कृषि के वर्तमान और भविष्य में लोगों की बहुत ज्यादा जागरूकता और रूचि पैदा की है. ऐसे में सुधारों की गति मंद नहीं पड़नी चाहिए.

सिराज हुसैन और श्वेता सैनी *इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन्स (आइसीआरआइईआर), नई दिल्ली में सीनियर फेलो (विजिटिंग) हैं. हुसैन पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव भी हैं*

इलस्ट्रेशनः **राज वर्मा**

अरविंद पी. दातार

कोर्ट का कायाकल्प

न्यायपालिका की तात्कालिक चुनौतियों में निचली अदालतों में लंबे समय से लटके मामले कम करना, जजों के खाली पद भरना और न्यायाधिकरणों के काम को आसान बनाना शामिल है. न्यायिक स्वतंत्रता भी बड़ी चिंता का विषय है

आजादी के 75वें साल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए हमें एक स्पष्ट रोडमैप की जरूरत है जो यह पक्का करे कि हमारे गणतांत्रिक संविधान की न्यायिक शाखा, जिसमें अदालतें और न्यायाधिकरण या पंचाट आते हैं, दक्षता और स्वतंत्रता से काम करे. अनुबंधों को लागू करने के लिहाज से फिलहाल भारत 193 देशों में 163वीं पायदान पर है और इससे बेहतर चेतावनी नहीं हो सकती है. अगर हम अपने लोकतंत्र के उपेक्षित तीसरे खंबे पर ज्यादा ध्यान दें तो पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कहीं ज्यादा तेजी से पूरा कर सकते हैं. 2022 में जिन तीन क्षेत्रों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, वे हैं—लंबित मामले, न्यायिक नियुक्तियां और पंचाटों की कार्यप्रणाली.

लटके मामले

साल 2021 को अलविदा कहते वक्त सभी हाई कोर्ट में 56,38,327 मामले (40,80,659 दीवानी और 15,57,668 फौजदारी मामले) लंबित हैं. इनमें करीब 54 फीसद तीन साल से ज्यादा वक्त से लंबित हैं, जिनमें एक दशक से ज्यादा वक्त से लटके 9,40,513 मामले भी शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि आधे से ज्यादा लंबित मामले 22 में से केवल पांच हाई कोर्ट में हैं.

लंबित मामलों का स्वरूप विभिन्न अदालतों में बिल्कुल अलग-अलग है. बॉम्बे में व्यावसायिक मामले बहुत बड़ी तादाद में लटके हैं जबकि इलाहाबाद को आपराधिक मामले निपटाने पर ध्यान देना होगा, जो बकाया मामलों में 48 फीसद हैं. इसके विपरीत, मद्रास हाई कोर्ट में ऐसे मामले महज 11 फीसद हैं, अजीब बात यह है कि देश में लंबित दीवानी मामले सबसे ज्यादा इसी कोर्ट में हैं. लिहाजा लंबित मामलों को निपटाने के लिए अदालतों को उनकी जरूरतों के हिसाब से तैयार योजना की जरूरत है. परेटो का सिद्धांत सीधे-सादे ढंग से लागू करने पर पता चलेगा कि किसी भी श्रेणी के 80 फीसद मामले एक उपश्रेणी के 20 फीसद मामलों से निकलेंगे. बकाया मामलों के बड़े कारणों की पहचान करके और मामलों के समूह बनाकर लॉगजाम को साफ करने में अहम मदद मिलेगी. यह भी इतना ही जरूरी है कि मौजूदा संसाधनों से मामलों का निपटारा बढ़ाने के लिए कैजन और सीमांत लाभ जैसे प्रबंधन के सिद्धांतों को लागू करें. इसी तरह जिला स्तर पर लटके मामले भी चिंता का विषय हैं, जहां 4.04 करोड़ लंबित मामलों में से 56 फीसद के लिए महज पांच राज्य जिम्मेदार हैं.

आंकड़ों पर नजदीक से नजर डालने पर पता चलता है कि उच्च न्यायालयों में दीवानी मामलों की संख्या ज्यादा है, वहीं जिला और मजिस्ट्रेट अदालतें आपराधिक मामलों की बहुत भारी तादाद से पटी पड़ी हैं. इससे यह भी पता चलता है कि हमारे बीच के सबसे गरीब लोग पैसे के अभाव में या पर्याप्त संख्या में जजों के न होने से विचाराधीन कैदी बने हुए हैं.

निचली अदालतों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट और विशेष अदालतें बनाने का प्रयोग मामलों के तेजी से निपटारे में ज्यादा कारगर नहीं रहा इसलिए नए तरीके निकालने होंगे. कर्नाटक में कुछ मजिस्ट्रेट और दीवानी अदालतों के साथ किए गए दक्ष सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर लॉ ऐंड टेक्नोलॉजी के एक टाइम-वर्क अध्ययन से पता चला कि फौजदारी जज का 52 फीसद वक्त

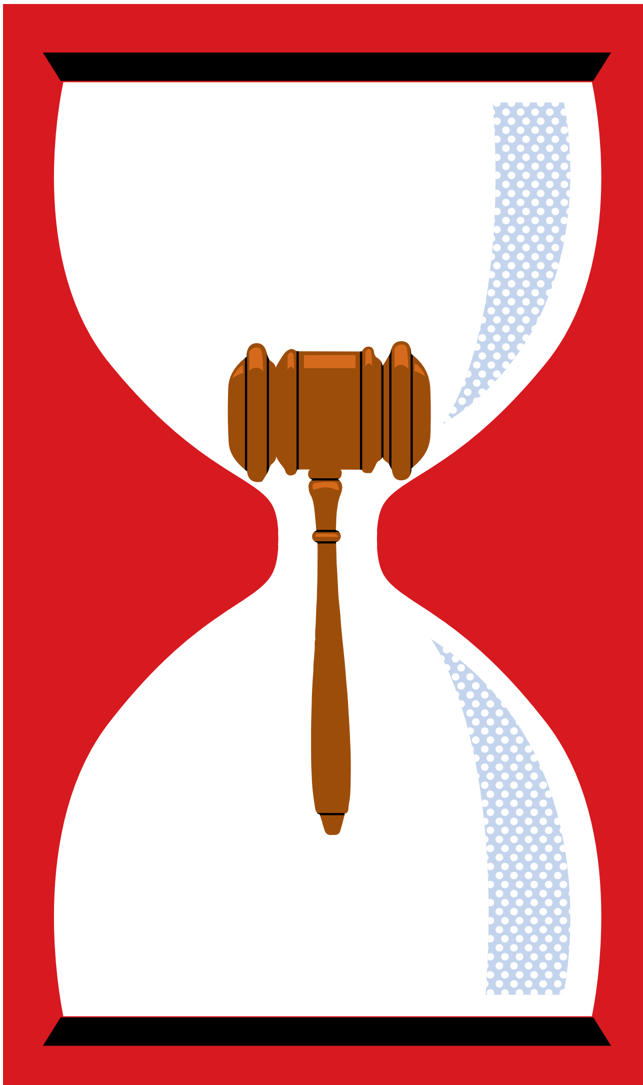

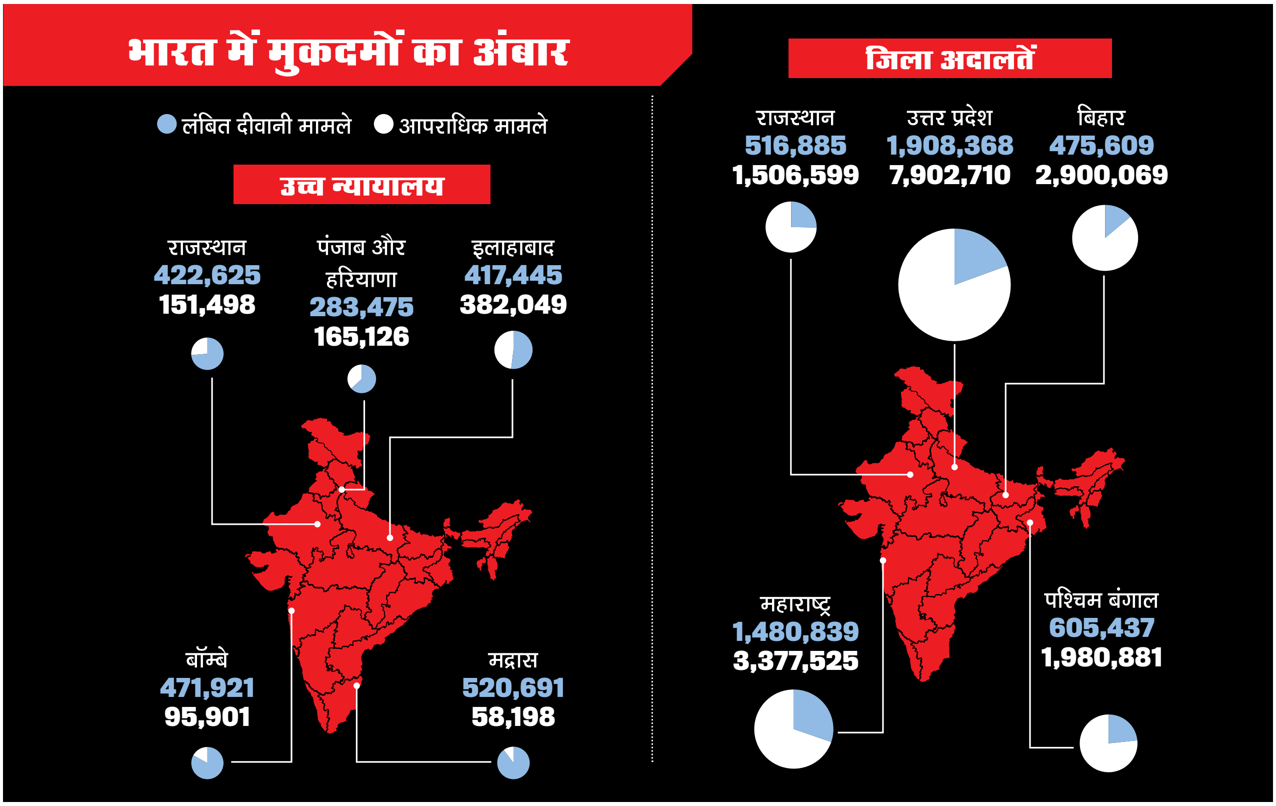
भारत में मुकदमों का अंबार
● लंबित दीवानी मामले ○ आपराधिक मामले
उच्च न्यायालय
राजस्थान 422,625 151,498
पंजाब और हरियाणा 283,475 165,126
इलाहाबाद 417,445 382,049
बॉम्बे 471,921 95,901
मद्रास 520,691 58,198
जिला अदालतें
राजस्थान 516,885 1,506,599
उत्तर प्रदेश 1,908,368 7,902,710
बिहार 475,609 2,900,069
महाराष्ट्र 1,480,839 3,377,525
पश्चिम बंगाल 605,437 1,980,881

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

और दीवानी जज का 48 फीसद वक्त मुकदमे बुलाने और स्थगित करने में गया. अगर यह प्रशासनिक काम सेवानिवृत्त जजों की समिति को सौंप दिया जाए, तो ट्रायल कोर्ट मामलों की वास्तविक सुनवाई पर ध्यान दे सकेंगे. उससे उनकी उत्पादकता तत्काल दोगुनी हो जाएगी. मामलों के आने के प्रवाह की जांच भी इतनी जरूरी है. जमानत को स्वचालित और आसान बना वाले सीधे-सादे संशोधनों से भी फौजदारी अदालतों और उच्च न्यायालयों में मुकदमों का अंबार काफी कम हो जाएगा. जमानत की सख्त शर्तों से अपराध तो कम नहीं हुए बल्कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया. इस पर भी फिर से विचार करना जरूरी है कि चेक का भुगतान न होने को अपराध बनाए रखा जाए या नहीं.

न्यायिक नियुक्तियां

सभी हाईकोर्ट में जजों की कुल 1,098 संख्या में से 402 पद खाली पड़े हैं. कुछ अदालतों में तो स्थिति खास तौर पर भयावह है. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने के खराब ढंग से बने प्रावधानों को अच्छा ही हुआ रद्द कर दिया गया, क्योंकि वे कारगर नहीं होते. अब जब तक संविधान संशोधित नहीं किया जाता, मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था जारी रहेगी. यह मिथ है कि न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका का कोई दखल नहीं है. संविधान का अनुच्छेद 224ए छोटे वक्त के लिए तदर्थ जजों के रूप में सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति का अधिकार देता है. कोई कारण नहीं है कि इस प्रावधान का इस्तेमाल न किया जाए और 10 साल से ज्यादा पुराने मामलों के निपटारे में उनकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल न किया जाए.

पंचाट और न्याय

1990 के दशक की शुरुआत से न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) या पंचाट बनाने की शुरुआत हुई. इसका मकसद मामलों के ज्यादा तेजी से निपटारा और अदालतों का बोझ घटाना था. पारंपरिक टैक्स ट्रिब्यूनल के अलावा, बैंकिंग, सेवा कानून, कंपनी कानून, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कई दूसरे क्षेत्रों के मामलों का निपटारा न्यायाधिकरण करने लगे. यह प्रयोग बुरी तरह नाकाम रहा और इसमें तत्काल सुधार की जरूरत है. मौजूदा मॉडल में सेवानिवृत्त जज और सिविल सेवक पंचाटों का कामकाज देखते हैं, जिन्हें बहुधा उस विषय की कोई विशेषज्ञ जानकारी नहीं होती जिससे उनके पंचाट को निपटना होता है. यह भी नाकाम हो चुका है. सीमित कार्यकाल की मंजूरी (पांच साल), पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव और बैठने-काम करने की समुचित व्यवस्था न होने से योग्य लोग मुश्किल से ही आवेदन करते हैं. सबसे बदतरीन झटका यह है कि हर पंचाट को स्वतंत्र न्यायिक पंचाट के बजाय मंत्रालय का हिस्सा माना जाता है. अव्वल लोकतंत्रों में हरेक पंचाट की कसौटी यह है कि वे उतने स्वतंत्र होते है जितने कानूनी अदालतें. दुर्भाग्य से सरकार को अहसास ही नहीं है कि मजबूत और स्वतंत्र पंचाट प्रणाली से कानून के शासन वाले देश के रूप में भारत की छवि सुधरेगी.पहला और सबसे अहम कदम राष्ट्रीय पंचाट आयोग का गठन है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की है.

पंचाटों में खाली पदों की स्थिति हाई कोर्ट से भी बदतर है. मसलन, देश के ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण की सभी पांचों पीठ खाली हैं. नई दिल्ली और चंडीगढ़ के ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में एक पदाधिकारी नहीं है. तकरीबन सभी न्यायाधिकरणों की यही निराशाजनक कहानी है. फिर यह नतीजा तो होना ही था कि पंचाटों में भी मामलों के अंबार लगे हैं. और पंचाट के गैरमौजूदगी के कारण वादी के सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं रह जाता कि वह हाई कोर्ट की शरण में जाए, जिससे समस्या और उलझ जाती है. जो लोकतंत्र न्यायिक स्वतंत्रता के प्रति असहिष्णु या एलर्जिक हैं, उन्होंने केवल कानून के शासन को ही चोट नहीं पहुंचाई बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी भोथरा किया है. यह वह सबक है जो रूस, तुर्की और पोलैंड की ओर से अपनाए गए रास्ते से हमें सीखना चाहिए. 2022 की पौ फटने के साथ हमारे सामने सड़क में एक असंदिग्ध कांटा है—यह तो हमारे हाथ में है कि कौन-सा रास्ता चुनें, लेकिन उसके बाद नतीजे चुनना हमारे हाथ में नहीं है.

—**अरविंद पी. दातार** *सीनियर एडवोकेट हैं*

इलस्ट्रेशनः तन्मय चक्रबर्ती

पराग खन्ना

प्रवास

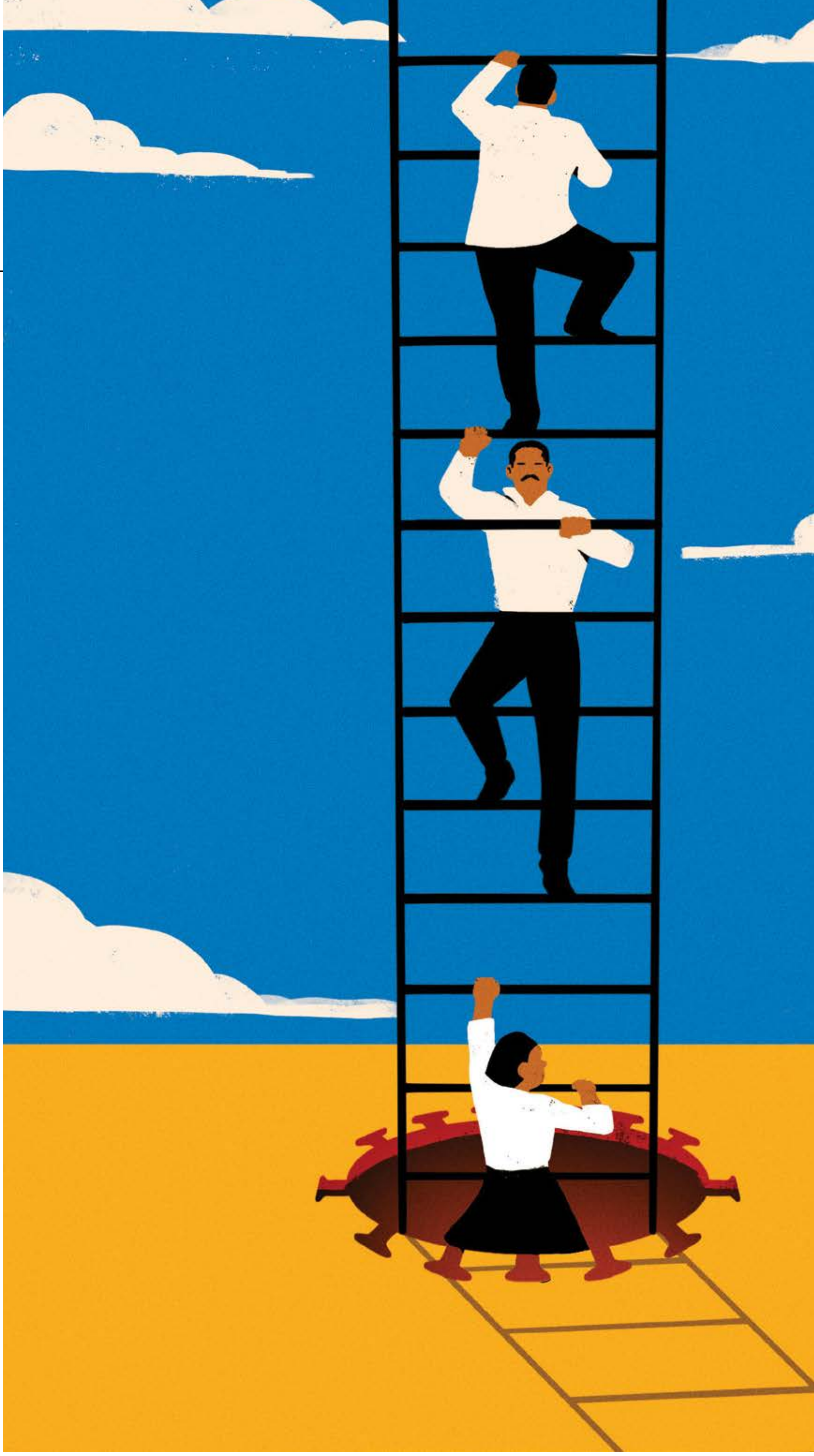

सबके चहेते हिंदुस्तानी

भारत के लोग दुनिया को क्यों और कैसे आकार देंगे. भारतीयों की आत्मसात होने की क्षमता इसमें बड़ी भूमिका निभाएगी

दुनिया में भारतीय प्रवासियों की अगली लहर कहीं अधिक बड़ी हो सकती है. भारत में 25 साल से कम उम्र के 600 मिलियन युवा हैं.ओईसीडी यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में अत्याधिक कुशल विदेशी श्रमिकों में से 3.1 मिलियन भारतीय पहले से हैं जबकि चीन के कुशल विदेशी श्रमिकों की गिनती 2.2 मिलियन है. कोविड के बाद के आर्थिक संकट और देश में बढ़ते प्रदूषण के भयावह स्तर को देखते हुए भारतीय पहले के मुकाबले अब कहीं अधिक देश छोड़ने को प्रेरित हो रहे हैं.

नावाचार को आत्मसात करने की भारतीय क्षमता की कई वजहें हैं. भारत कभी अंग्रेजी बोलने वाला, ब्रिटिश उपनिवेश रहा है. जबकि चीनी उस देश का नागरिक है जो भी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा नहीं रहा और जिसकी अपनी एकांत संस्कृति रही है. जब मैं बड़ा ही हो रहा था और अमेरिका चला गया, तब मैं केवल हिंदी बोलता था. जब मैं अंग्रेजी पहली भाषा के रूप में सीख रहा था, न्यूयॉर्क के जापानी, कोरियाई, वियतनामी बच्चे दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी की कक्षा में थे. मैंने झटपट अंग्रेजी सीखी और

इलस्ट्रेशनः सिद्धांत जुमडे

ऐसा नहीं कि बस भारतीय ही अंग्रेजी बोलते हैं. बात यह है कि भारत जरूरत से कहीं ज्यादा आइटी या मेडिसिन पढ़ने वाले लोग उत्पन्न कर रहा है. पूरी दुनिया में कामगारों की कमी वाले यही दो सबसे बड़े क्षेत्र हैं

उसे आत्मसात कर लिया. तो आत्मसात की शक्ति ही भारतीय प्रवासी समुदाय को चीनी प्रवासी समुदाय के मुकाबले अधिक विशाल बनाती है. यह शक्ति ही हर जगह उन्हें सांस्कृतिक स्वीकृति दिलवाती है.

दस साल पहले हम ऐसे देश के रूप में चीन की बात नहीं करते थे जिसे सारी दुनिया दुश्मन मानती है. दस साल पहले हम परोपकारी, बुनियादी ढांचे पर केंद्रित, व्यापार से जुड़े महाशक्ति देश के रूप में चीन की बात करते थे. हम यह नहीं कह रहे थे कि चीन कुटिल, शोषक, लगभग व्यापारिक और वैश्विक दबदबा कायम करने को आमादा देश है. अब चीन को लगभग हर जगह मूलत: दुष्ट माना जाता है.

तो हम यह बातचीत ऐसे समय कर रहे हैं जब अगर आपके यहां ढेरों चीनी लोग हैं, तो आप चाहेंगे कि वे न हों. देखिए अमेरिका में, ब्रिटेन में क्या हो रहा है—चीनी वैज्ञानिकों के प्रति समन्वित संदेह जनमा है, भयवश चीनी वैज्ञानिकों, चीनी छात्रों को भगाया जा रहा है. अब यह बातचीत एक दूसरी बातचीत को काटती है. कामगारों की कमी बदतर होती जा रही है जबकि एशियाई आबादी बढ़ रही है. लेकिन अगर आप भूराजनैतिक आधार पर, शक और जासूसी के आधार पर चीनियों को खारिज कर रहे हैं, तो भी वह कमी तो आपको पूरी करनी ही है. तो भारतीय युवाओं के लिए बूम ठीक उस वक्त आया है जब आप कामगारों की कमी पूरी करने को बेताब हैं. मैं फ्रैंकफर्ट में सबसे बड़ी यूरोपीय सॉफ्टवेयर कंपनी एसएपी या सैप के मुख्यालय गया. मैंने क्या देखा? बहुत सारे भारतीय. मुझे याद नहीं आता कि अपने हाइ स्कूल के सालों में मैंने जर्मनी में इतने भारतीय देखे हों. अब भारतीयों का पूरा शहर है जो पूरे यूरोपीय इलाके को ताकत दे रहा है.

अमेरिका में तो हम इसके आदी हैं. हम जानते हैं कि भारतीय बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां चला रहे हैं. इस पर हैरानी भी नहीं होती. क्या कभी कोई चीनी सत्या नडेला या पराग अग्रवाल होगा? ऐसा नहीं कि बस भारतीय ही अंग्रेजी बोलते हैं. बात यह है कि भारत जरूरत से कहीं ज्यादा आइटी या मेडिसिन पढ़ने वाले लोग उत्पन्न कर रहा है. पूरी दुनिया में कामगारों की कमी वाले यही दो सबसे बड़े क्षेत्र हैं. विकसित देशों को इसी की जरूरत है—उन्हें मेडिकल और आइटी पेशेवरों की जरूरत है.

महिलाएं दूसरा बड़ा कारक हैं. मेरी किताब में यह एक पंक्ति है—''दुनिया में महिला भारतीय आइटी पेशेवर सबसे कम आततायी प्रवासी है.'' उसमें आपको भला ऐसी क्या बुराई मिल सकती है जिससे आप उसे अपने देश में न रखना चाहें? वह मूल्य बढ़ाएगी ही. वह आपका जीडीपी बढ़ाएगी, अपार्टमेंट किराये पर लेगी, दोस्त बनाएगी, कभी गुनहगार नहीं होगी. यह सांस्कृतिक तौर पर असंवेदनशील भले लगे, पर यह सच है. तथ्य यह है कि दुनिया भारतीय महिलाओं को गले लगाएगी.

दूसरा है जलवायु परिवर्तन. देखिए जलवायु परिवर्तन भारत और चीन में क्या कर रहा है. तथ्य यह है कि जलवायु परिवर्तन कई भारतीयों को नई जगह जाकर बसने को मजबूर करेगा. पहले भारत के भीतर और फिर उनके विदेश जाकर बसने का एक और कारण बन जाएगा. मध्यमवर्गीय भारतीय यूएई में संपत्ति खरीद रहे हैं. हाल में छह लाख भारतीयों ने दूसरों देशों में जाकर बसने के लिए अपनी नागरिकता छोड़ दी. जब भारतीय मध्यवर्ग में शामिल होता है और वह दूसरे देश जाना गवारा कर सकता है, तो पूरी संभावना है कि वह जा सकता है.

इसी से जुड़ी एक बात यह है कि भारत में अवसर तलाश रहे लोगों की संख्या के मुकाबले अवसरों की कमी है. अगर आप भारत में प्रतिभाशाली हैं और भारत में ही रहना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी कंपनियों में आपके लिए नौकरियां होंगी. माइक्रोसॉफ्ट सिएटल में किसी औसत दर्जे के आदमी को 2,50,000 लाख डॉलर देकर उसकी सेवाएं भला क्यों ले जबकि वही काम कोई टेक्नोलॉजी पेशेवर भारत में 50,000 डॉलर में कर सकता है? अगर आप भारत में प्रतिभाशाली हैं, तो भारत न केवल अवसरों की धरती है बल्कि वैश्विक अवसरों का भौगोलिक संधिस्थल भी है.

लोग 'मूव' की मेरी थीसिस के बारे में पूछते हैं, कि हमारे यहां तो हर जगह इंटरनेट है. मैं उनसे कहता हूं कि आपके यहां इंटरनेट भले हो, पर अगर पानी न हो तो क्या आप केन्या में अपने खेत पर रुकेंगे? पढ़े-लिखे भारतीय भारत में रुक सकते हैं, पर अवसर के मुकाबले कामगारों की बहुतायत होगी, भले ही अवसर बढ़ रहे हों.

मध्य एशियाई चीनियों से बुरी तरह आतंकित रहते हैं, पर उन्हें बॉलीवुड का संगीत बहुत अच्छा लगता है, वे भारतीयों से बहुत प्यार करते हैं. क्योंकि सोवियत भारतीयों से प्यार करते हैं. इन देशों के साथ हमारा बंधुत्व हमारे भूराजनैतिक इतिहास का अंग है. मध्य एशिया एक हुआ—वे दिन दूने रात चौगुने फल-फूल रहे हैं, आइटी, मेडिसिन, कृषि से लोग ला रहे हैं. रूस भारतीय किसान आयात करेगा.

फिर यूरोप तो बड़ा है ही. एशियाई यूरोपीयों की पूरी नई पीढ़ी होगी, क्योंकि वे वहां जन्मे होंगे—लाखों भारतीय जो यूरोप में बड़े होंगे क्योंकि वे वहीं जन्मे होंगे. यह दुनिया का सबसे बड़ा बढ़ता प्रवासी समुदाय होगा. यूरोप में दुनिया में किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले कामगारों की ज्यादा जरूरत है. और यूरोपीय अरबों या अफ्रीकियों को पसंद नहीं करता इसलिए भारतीयों को फलने-फूलने का मौका मिलेगा. नस्लवाद के बारे में हम इतना कुछ पढ़ते हैं, उसके बावजूद यह हो रहा है.

(श्वेता पुंज से बातचीत पर आधारित)

पराग खन्ना *फ्यूचरमैप के संस्थापक और मूवः हाउ मास माइग्रेशन विल रिशेप द वर्ल्ड के लेखक हैं*

शारदा उगरा

खेल

टीम इंडिया की तलाश

वर्ष 2022 हर भारतीय खिलाड़ी के लिए खुद को साबित करने का या उस खेल की नई परिभाषा गढ़ने का मौका होगा

आखिर 2022 में भारत खेल जगत की बड़ी तस्वीर क्या होगी, इस पर नजर दौड़ाने के लिए उस मर्द खिलाड़ी की ओर रुख करना होगा. जी नहीं, वह विराट कोहली नहीं, नीरज चोपड़ा है. यह ओलंपिक पदक विजेता, भाला (जेवलिन) फेंकने वाले की स्टीरियोटाइप छवि वाला, हमारे अब तक के अधूरे सपने का हीरो है. चोपड़ा के लिए 2022, भारत में खेल की तरह ही, सांस थामे जीने का वर्ष है. ओमिक्रोन संक्रमण चाहे बढ़े या नहीं, चोपड़ा को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देनी है कि टोक्यो उनके लिए आरंभ बिंदु था या संतुष्ट होकर आराम फरमाने का मौका. जुलाई 2022 में चोपड़ा को अपनी पहली सीनियर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दुनिया के चौथे नंबर के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी के नाते स्पर्धा में हिस्सा लेना है. इस पैमाने उनसे पहले के तीन खिलाड़ी उस भारतीय पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने को उतावले होंगे, जिसने महज ध्यान लगाने की कुटिया सरीखी जगह से निकलकर टोक्यो में हर मानक को पछाड़ दिया.

चोपड़ा के लिए 2022 हर तरह के दबाव का चरम बिंदु लेकर नमूदार हुआ है. उन्हें आगामी स्पर्धा में अपना बेहतरीन शरीरिक

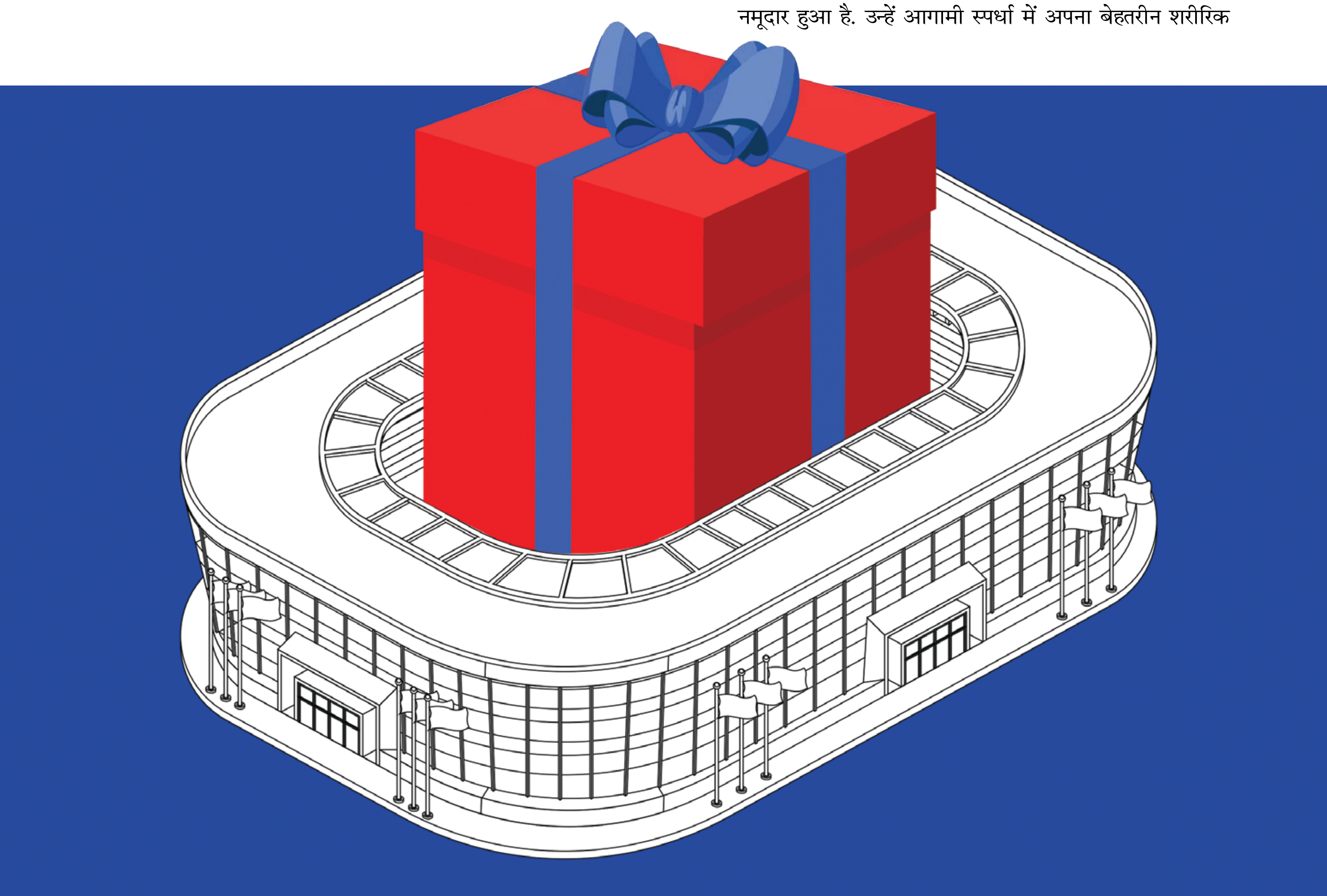

क्षमता का प्रदर्शन की तरकीब खोजनी होगी, वह भी एक नहीं, बल्कि साल में तीन बार. वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद 60 दिनों के भीतर ही चोपड़ा को दो और अंतरराष्ट्रीय खिताबी मुकाबलों में महारत दिखानी होगी, जो उनके माथे बंधी हुई है, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स (सीडब्ल्यूजी) और एशियाई चैंपियनशिप में. उनके पास विकल्प था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में खिताब हासिल करके दो बड़ी स्पर्धाओं में से कम से कम एक में हिस्सा न लेते, लेकिन उन्होंने यह विकल्प नहीं चुना. टोक्यो से लौटकर चारों ओर वाहवाहियों से घिरे होने के दौरान ही उन्होंने मुझसे कहा, ''मैं एथलीट हूं. मेरा काम जुटे रहना है.''

वर्ष 2022 में प्रदर्शन के लिहाज से-नीरज 2.2-यानी उनके और सुधरे, संशोधित स्वरूप की उम्मीद है. उन्हें अपने बेहतरीन प्रदर्शन (88.07 मीटर) से आगे बढ़कर 90 मीटर के उस विरले मार्क को छूना है और खेल के मौजूदा महारती जोहानेस वेटर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होना है, जो 90 मीटर का निशान ऐसा छूता है, जैसे कोई आराम से सड़क पार कर रहा हो. चोपड़ा वाहवाहियों के लाल कालीन से दिसंबर के पहले हफ्ते में ही उतर गए और विदेशी प्रशिक्षण की अक्लमंदी हासिल करने के लिए भारत से रवाना हो गए. वे अभी अमेरिका में हैं. 2022 भले ही भारी तनाव के क्षण लेकर आया हो पर उनकी सबसे बड़ी ताकत तो लचीलापन है.

टोक्यो की यादें ताजा हैं इसलिए सुस्ती बरतना कोई विकल्प नहीं है: जो चमकदार खिताबों से रौशन हैं, उन्हें उसी आभा के पीछे छिपने के लिए बुलाया जाएगा

हमारे सभी खेलों के एथलीटों से 2022 ऐसी तेजी से अपने में सुधार लाने और कायाकल्प की मांग करता है, जिसके वे आदी नहीं होंगे. कोविड के पहले के दौर में ओलंपिक के बाद अमूमन 12 महीने की अवधि होती थी, जिसमें वे सीडब्ल्यूजी और एशियाई चैंपियनशिप की तैयारी के लिए अपनी फिटनेस वगैरह पर पूरा ध्यान दे पाते हैं. लेकिन ओलंपिक में देर होने से वह साल भर की अवधि खो गई और सब कुछ एक साथ आन पड़ा.

टोक्यो की यादें ताजा हैं इसलिए सुस्ती बरतना कोई विकल्प नहीं है: जो चमकदार खिताबों से रोशन है, उन्हें उसी आभा के पीछे छिपने के लिए पुकारा जाएगा. जो ओलंपिक में कुछ खास नहीं कर पाए, 2022 उनमें उम्मीद जगा सकता है. खासकर निशानेबाज, जिनके सीडब्ल्यूजी पदक चमक बिखेर चुके हैं, उनके लिए अब यह हासिल करना संभव नहीं होगा, क्योंकि यह खेल ही सीडब्ल्यूजी कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया है. उनके लिए एशियाई चैंपियनशिप मुकाबला कड़ा हो जाएगा और उसके बाद वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में होड़ लेना होगा. देश में (क्रिकेट के बाद) सबसे खास खेल का रुतबा निशानेबाजी की जगह अब चोपड़ा, बैडमिंटन और हॉकी ने ले ली है. इसी वजह से 2022 निशानेबाजी के लिए खोई जमीन और साख वापस पाने का मौका है.

यह साल एक और खेल फुटबॉल पर नया फोकस लेकर आया है क्योंकि दो बड़े आयोजन एएफसी वूमेंस एशियन कप और फीफा यू-17 वूमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है. चमक-दमक से दूर छिटक गए हमारी फुटबॉल की दिलचस्पी उसके सब जगह एक समान आसान खेल की वजह से है, बड़े आयोजनों की कड़ी समीक्षा की दरकार है. उनका सेलेब्रेटी मॉडल उस जरूरत को नजरअंदाज करता है, जो जमीनी स्तर पर लाखों लड़के, लड़कियां 'पहचान और प्रदर्शन' के बगैर गुमनामी में स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की लीग में खेलते हैं. वे तो मुट्ठी भर एलिट खिलाड़ियों के शोपीस इवेंट की खातिर 'तैयारी' टूर का आयोजन करते हैं.

इस पूरे साल भारतीय खेल (फिर क्रिकेट के अलावा) के नए हब के रूप में ओडिशा के उदय पर मुहर लगेगी. मार्च 2021 में भारत में खेल शहरों के ग्रांट थॉर्टन सर्वे में भुवनेश्वर नंबर 3 पर था, उसके आगे दिल्ली और मुंबई थे. उसके बाद बेंगलूरू और अहमदाबाद का नंबर था. हालांकि प्रकाशित सर्वे में न जाने कैसे अहमदाबाद और बेंगलूरू के बाद भुवनेश्वर चौथे स्थान पर पहुंच गया. लेकिन इन टाइपिंग की गलतियों के अलावा ओडिशा ने खेल प्रोफाइल में बाकी सभी ताकतवर खेल ठिकानों को पीछे छोड़ दिया. राज्य ने खेल में मौके पर काफी पैसा लगाया है, राष्ट्रीय हॉकी टीमों का उसका प्रायोजन खबरों से दूर नहीं हो पाया क्योंकि टोक्यो में हॉकी अभियान कामयाब जो रहा. जनवरी 2023 में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए राउरकेला में 20,000 सीटों का हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है.

आखिर में, देश के दिलो दिमाग में सबसे ज्यादा छाया रहने वाला भारी-भरकम गोरिल्ला यानी क्रिकेट है. 2022 में 10 टीमों वाले आइपीएल के साथ भारी मंथन होने वाला है. आइपीएल का 15वां सीजन क्रिकेट के कायाकल्प का अगला चरण होगा, राष्ट्रीय पुरुष टीम और दुनिया में उसकी छाप दोनों मदों में. रुझानों का संकेत तो यही है कि पुरुष टीम स्पष्ट दो हिस्सों में बंट जाएगी-अलग-अलग कप्तानों के तहत रेड बॉल टीम और व्हाइट बॉल टीम. दो अलग फॉर्मेट के लिए दो कप्तानों की बात भारत में पहली बार नहीं होगी, लेकिन इस बार दायरे साफ-साफ बंटे होंगे. पहले कुंबले-धोनी या धोनी-कोहली का फॉर्मूला महज थोड़े अंतराल के लिए हुआ था, ताकि आखिरकार एक को सभी तीनों कमान सौंप दी जाए. 33 साल के कोहली अपने करियर के उत्तरार्ध में हैं और अपनी कप्तानी के थोड़े-बहुत विस्तार के साथ अपनी बल्लेबाजी कला को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. तीनों फॉर्मेट में माहिर और कप्तानी की रेस में आगे फिलहाल मुट्ठी भर ही खिलाड़ी हैं: 34 वर्षीय रोहित शर्मा, 31 वर्षीय मोहम्मद शामी, 29 साल के के.एल. राहुल, 28 वर्षीय जसप्रीत बुमराह और 24 साल के ऋषभ पंत. नया साल ऑस्ट्रेलिया में आइसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के रूप में आइसीसी खिताब का एक और मौका लाएगा. कोहली ने कहा है कि वे कप्तानी की दौड़ में नहीं होंगे और जो भी चुना जाता है, वही टीम की भविष्य की पटकथा लिखेगा.

लेकिन आइपीएल शुरू होने के काफी पहले, 2022 की पहली तिमाही में उलट-फेर होना तय है, अगर यूएई क्रिकेट छह टीमों की 34 मैच वाले टी20 लीग की शुरुआत होती है. मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रबंधकों ने यूएई के साथ फ्रेंचाइजी करार की बात पुष्ट की है और कम से कम दो भारतीय टी20 फ्रेंचाइजी ने टीम भेजने में दिलचस्पी दिखाई है. ये हैं मल्टीनेशनल हो चुकी नाइट राइडर्स और रिलायंस की मुंबई इंडियंस. दोनों जुड़ जाती हैं तो सब कुछ बदल जाएगा.

शारदा उगरा *वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, जो तीन दशकों से प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं*

इलस्ट्रेशनः राज वर्मा

पुस्तक अंश

विपदा केवल उस्मानाबाद की न थी

बाप-बेटे के बीच चल रही मौन प्रतियोगिता को बेटी दो घंटे से महसूस कर रही थी. उससे रहा नहीं गया. सूनी सड़क पर जैसे कोयल कूकी, ‘मेडल नहीं मिलेगा किसी को. रुककर पानी तो पी लो. मुझे भी प्यास लगी है.’’

प्रवीण कुमार

एक जोड़ी साइकिल उस्मानाबाद से साल भर पहले चली थी. साइकिल सवार महासागर में अपना नक्शा खो चुके किसी जहाजी जैसे थे जिनका दिशा-बोध लड़खड़ाया हुआ था. वे किनारे को नहीं जानते थे पर भीतर की उम्मीद को जानते थे. उसी के दम पर वे अब तक का जीवन काटते आए थे और आगे उसी के सहारे कड़ी धूप में साइकिल खींचते हुए निकले थे. पर बेछांह और जल्लाद सड़क उनकी उम्मीद से ज्यादा लंबी और गरम थी, जिस पर उनकी साइकिल के पहिए बारी-बारी से पंचर हो रहे थे.

पहली साइकिल पुरानी और जर्जर हो चुकी थी जिसके हैंडल और कैरियर पर घर का लगभग हर सामान टंगा था. बेडशीट-चादरों, पतले-पतले गद्दों और थोड़े-से अनाज को साइकिल सवार ने टेंट वाली प्लास्टिक की चद्दर से ढक रखा था और उसे अपनी सीट के पीछे कैरियर पर मजबूती से बांध दिया था. उसके ऊपर प्लास्टिक की एक-दो बाल्टियां औंधी पड़ी थीं, जिनमें मग और छोटी-मोटी जरूरतों के सामान के साथ थालियों, कटोरों और गिलासों को ठूंसा गया था. बाल्टियों को रस्सियों के सहारे कसा गया था और उन्हीं रस्सियों के सहारे उनके दाएं-बाएं दो तसले लटकाकर बांधे गए थे. रोटी बनाने के तवे के हैंडल को साइकिल सवार ने अपनी सीट के नीचे फंसा दिया था. तवा औंधा ही रखा गया था. सब कुछ कायदे से इतना विन्यस्त था कि साइकिल के चलने से सामान आपस में टकराते नहीं थे. बस कटोरियां ही थीं जो थाली से टकराकर कभी-कभार शोर कर जातीं. साइकिल सवार को उस शोर से भी दिक्कत नहीं थी. उसकी नजर बिलकुल सीधी सड़क पर थी और बीच-बीच में वह साइकिल के हैंडल के मध्य फंसे स्टोव को कनखियों से घूर देता था. स्टोव से मिट्टी का तेल रिस रहा था और यह चीज उसे परेशान कर रही थी.

साथ चल रही दूसरी साइकिल अपेक्षाकृत नई थी. उस पर एक लड़का और एक लड़की सवार थे. लड़का चौदह-पंद्रह का होगा और लड़की बारह की उम्र के आसपास. लड़का साइकिल चला रहा था और साइकिल के हैंडल पर घंटी के अलावा कुछ नहीं था. लड़की पीछे साइकिल के कैरियर पर तौलिया डाले गुमसुम बैठी थी और उसके हाथ में एक एयरबैग था. बैग में दो-दो जोड़ी कपड़े और पानी भरी बोतलें थीं. साइकिल चलाते-चलाते लड़का कुछ हांफने लगा था. उसके कांपते हुए पैर बता रहे थे कि वह अपनी उम्र से कहीं अधिक बोझ ढो रहा था. उसके साथ चल रहा साइकिल सवार उसका बाप था जो बेटे को हांफते देखकर भी पिघल नहीं रहा था. बाप को लग रहा था कि अभी दो घंटे पहले ही तो साइकिल चलाने की अदला-बदली हुई थी उससे. तब बेहूदे ने जर्जर साइकिल को ऐसा हांका था कि स्टोव से तेल रिसने लगा. अगर स्टोव की टंकी फूटी होगी तो भगवान ही मालिक है. बाप ने एक बार फिर स्टोव को घूरा और साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी. बेटा बाप की हरकत समझ रहा था. इसी रोष में वह भी रुका नहीं बल्कि बाप की ताकत आंकने का फैसला करते हुए उसने भी साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी. धूप अब भी तेजाबी थी और काली लंबी सड़क बेछांह.

बाप और बेटे के बीच चल रही इस मौन प्रतियोगिता को बेटी दो घंटे से महसूस कर रही थी. उससे रहा नहीं गया, सूनी सड़क पर जैसे कोयल कूकी, ''मेडल नहीं मिलेगा किसी को. रुककर पानी तो पी लो. मुझे भी प्यास लगी है.''

कोयल के कूकते ही दोनों साइकिलों की रफ्तार धीमी हुई और फिर वे रुक भी गईं.

माधुरी बैग से पानी की बोतल के साथ थोड़ा गुड़ और चना भी निकालने लगी. लड़के ने साइकिल से उतरते ही मोबाइल निकाला और आसपास के नक्शे को उसमें टटोलने लगा, फिर कुछ उम्मीद से बोला, ''यह आगे कोई नदी दिखा रहा है.'' बाप ने जैसे कुछ सुना ही नहीं. वह नक्शे को नहीं उम्मीदों को टटोलना जानता था. इन मशीनी नक्शों पर उसको भरोसा नहीं था. उसे कहीं भी बस अपना जुगाड़ बैठाना था जिससे तीन जीवों का दाना-पानी चलता रहे. वह भीतर से बहुत डरा हुआ था. उसने सालभर में दर्जनों मजदूरों की लाशों को भूख और प्यास के मारे सड़कों पर मरा हुआ देखा था. एक गर्भवती मजदूरनी तो राजमार्ग पर बच्चा जनते हुए ही मर गई थी. जब तक मजदूरों की कोई दूसरी खेप वहां तक पहुंचती गिद्ध और चीलें उस मरी हुई मां के साथ उसके जिंदा नवजात की देह नोचकर आधा खा चुके थे. मजदूरों की बिखरी हुई फौज बिलखकर रह गई. मजदूर

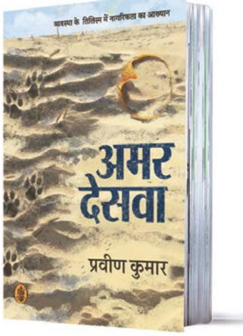

अमर देसवा

लेखकः प्रवीण कुमार

प्रकाशकः राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली

कीमतः 250 रुपए

इतने नासमझ नहीं होते कि निजाम के इस मानवता विरोधी अपराध को न समझ रहे हों. बस पढ़े-लिखों की तरह उन्हें परिभाषाएं गढ़नी नहीं आती हैं. इस सरकारी अपराध को वे तालाबंदी के नाम से पुकार रहे थे और भुनभुनाते हुए मुट्ठियां भींच रहे थे. उस बिखरी हुई फौज का एक हिस्सा इन दो बच्चों का बाप भी था. पर उसकी नजर सरकार से ज्यादा सड़क पर थी. और सड़क से ज्यादा तीन प्राणियों के पेट पर.

चना-गुड़ फांकते हुए बाप ने बेटे को डपटा, ''तुम्हारे नक्शे के चक्कर में तीन बार फंसे हैं हम लोग. बंद कर नक्शा और मुरारी को फोन लगा.''

बेटे का पहले से ही माथा गरम था, बाप से उलझ गया ''इसी नक्शे के दम पर तीन माह दाना-पानी चला था नांदेड़ में. नहीं तो मैं भी देख ही रहा हूं तुम्हारे दोस्तों को. कहीं ढंग की नौकरी नहीं लगवाई किसी ने तुम्हारी.''

अमर
देसवा
प्रवीण कु
देवेश

अपने दो कहानी संग्रहों छबीला रंगबाज का शहर और वास्को डी गामा की साइकिल से चर्चा में आए कथाकार प्रवीण कुमार का यह पहला उपन्यास है

एकदम छील दिया बेटे ने बाप को. बाप भी उलझ ही गया, ''उस्मानाबाद में तुम्हारे दादा ने नौकरी दिलवाई थी क्या? खाली हम पर ही बीत रहा है यह? सब लोग उजड़ गया तालाबंदी में! फोन लगाओ मुरारी को फिर से.''

''अरे आपका मुरारी फोन उठाएगा तब न? उठा ही नहीं रहा है!'' लड़का एकदम आपे से बाहर हो रहा था.

अजीब मुसीबत है. साला कोई कहीं साथ नहीं दे रहा है. ऐसे तो भूखे ही मर जाएंगे. कुछ-कुछ सोचते हुए बाप परेशान हो गया. साल के तीन-साढ़े तीन महीने सड़क नापते हुए ही गुजर गए थे. पर कहीं ढंग का काम मिले तब तो! बेटा अभी भी मोबाइल में घुसा पड़ा था. बाप झल्ला गया, ''हम कह रहे हैं विजय कि उठाकर पटक देंगे मोबाइल. चना-गुड़ फांको और साइकिल उठाओ.''

''वीडियो गेम नहीं खेल रहा. आसपास कोई फैक्टरी खोज रहा हूं. क्या पता कुछ काम का निकल आए!''

''अरे भाग! फैक्टरी होगी तो काम भी मिल जाएगा क्या? नक्शा केवल ई बताएगा कि फैक्टरी है. वहां काम है कि नहीं, यह थोड़े न बताएगा.''

विजय कसमसा कर रह गया. पर पिता की बात कुछ हद तक सही थी. अब तक का अनुभव भी यही कह रहा था. अब सच्चाई तो यह थी कि दोनों ही जीव इस हालत से बाहर निकलने का भरोसा खो चुके थे. ऊपर से तपते सूरज और दहकती धरती के बीच होश संभालना मुश्किल हो रहा था. ऐसे में मोबाइल पर विजय क्या ही खोजबीन करता? वह साइकिल पर झटके से बैठ गया और बोला, ''चल माधुरी बैठ.''

''चना-गुड़ तो खा लो भाई,'' माधुरी ने मिन्नत की.

''ना, अब सीधे नदी किनारे.'' विजय ने पानी भी नहीं पिया. बाप का कलेजा कट रहा था पर कुछ बोलता तो फिर झगड़ा शुरू हो जाता. चुपचाप उसने भी अपनी साइकिल को पैडिल मार दिया.

***

नक्शे ने इस दफा कोई जालसाजी नहीं की थी. अगले सवा घंटे की मौन प्रतियोगिता के बाद नदी दिखी. बीच में एक पुल भी था. जल्लाद सड़क नदी के पुल पर जाकर धूसर हो रही थी. पुल के पार आगे की सड़क फिर वैसी ही काली और बेछांह थी.

थके जीव बेछांह सड़क से अलग होकर एक ढलान की ओर बढ़े और आहिस्ता-आहिस्ता पुल के ठीक नीचे आ गए. साढ़े तीन घंटे बाद किसी छाया ने पनाह दी थी. नदी सूखकर पतली हो गई थी. पर उसमें धार थी. एक बहती हुई नदी से बड़ा सहारा भला क्या हो सकता है! उसकी शीतलता पुल के नीचे पसरी थी. माधुरी को लगा कि जन्नत नसीब हुई है. पिता ने भी साइकिल खड़ी करके अंगड़ाइयां लीं. इधर प्यासा विजय गश खाकर गिर गया. अचानक ही.

बाप और बेटी एक साथ उसकी ओर दौड़े.

पुल के नीचे माधुरी स्टोव जलाकर भात रांध रही थी. अनाज की गंध से विजय की आंख खुली. उसने आसपास निहारा. सांझ ढल रही थी. पिता नदी में पैर डाले आसमान निहारता दिखा. पिता की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी और वह देह से भी मजबूत था पर कुछ था जो भीतर ही भीतर उसे कमजोर कर रहा था. आखिर इस देह की भी सहने की एक सीमा थी. उस्मानाबाद आने के बाद जैसे उसकी देह ही शापित हो गई थी. तब विजय पांच महीने का था. पता नहीं क्या सोचकर वह उस्मानाबाद आया था मैनेजर बनने! उतना पढ़ा-लिखा भी नहीं था पर ख्वाब बहुत बड़े देख लिए थे. उन ख्वाबों को किसी की नजर लग गई. हालात ने मजदूरों के बीच उनकी ही तरह की जिंदगी गुजर-बसर करने का सबक सिखा दिया. यहां आने के दो साल के भीतर माधुरी का जन्म हुआ. गृहस्थी डांवाडोल होने लगी. बहुत सोच-समझकर अतिरिक्त आमदनी के लिए एक परचून की दुकान भी खोली गई. पर वह भी गरीब मजदूरों के बीच संभल नहीं पा रही थी. दुकान पत्नी के देखरेख में ही थी पर उस दुकान के न चलने में उसका क्या कुसूर था? मजदूर अक्सर उधारी लगाते थे. कुछ उधारी चुकाते तो कुछ बिना चुकाए अपने गांव-घर भाग जाते. मजदूर और मजदूरी में से कोई भी टिकाऊ न था. उधार बढ़ता गया और तंगी से दुकान बंद करनी पड़ी. फिर विजय की मां लगातार बीमार रहने लगी. डॉक्टर ने बताया कि उसके दिल में छेद है. उसके सालभर के भीतर ही विजय की मां ने सबका साथ छोड़ दिया.

पिता क्या सोचकर आया था और क्या होकर रह गया. कई बार यह भी सोचा कि वापस अपने घर लौट जाए. पर घर लौटकर वह करता ही क्या? कायदे के काम की गारंटी और कहीं दिख नहीं रही थी और यहां कमोबेश एक बंधी-बंधाई आमदनी थी. काम भी बहुत वजनी नहीं था. जिंदगी संभालने वाले कुछ भरोसेमंद साथियों का साथ भी तो था.

वह जैसे-तैसे बच्चों को पालने लगा. बच्चे स्कूल जाने लगे. पिता ने सोचा कि विजय दसवीं कर लेगा तो कुछ कमा लेगा कायदे का. पिता वाली फैक्टरी बहुत बड़ी नहीं थी और उसका भविष्य भी कुछ बढ़िया नहीं दिख रहा था. पर उसी में विजय को घुसाने की जुगत में था वह. बस दसवीं कर जाए विजय. इसी उधेड़बुन में पिता पित्तमारू जिंदगी काट रहा था.

किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ऐसी विपदा पड़ेगी. वह भी केवल उस्मानाबाद में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में. अचानक महामारी का शोर उठा. देखते-ही-देखते खदानें और फैक्टरियां धड़ाधड़ बंद होने लगीं. जब तक कोई होश संभालता सड़क-दुकान-मकान सब सूने पड़ गए. लोग रेल-बस-ट्रक जैसे जहां थे वहीं थम गए. मजदूरों में अफरातफरी मच गई. आधे तो तत्काल अपना जुगाड़ लगाकर भाग खड़े हुए. जिनमें थोड़ी कुव्वत थी वे टिके रहे. एक माह तो बैठकी में ही निकल गया. मजूरी करके भी जिन परिवारों का पेट नहीं भर रहा था उन्हें आटे-दाल का भाव सताने लगा. ■

सवाल + जवाब

"हम सब अब नोआ हैं"

अपनी नई किताब ईडन में देवदत्त पटनायक ने यहूदी, ईसाई और इस्लामी कथाओं की भारतीय नजरिए से पड़ताल की, तो दिलचस्प नतीजे सामने आए

● अब्राहम से जुड़े मिथों को भारतीय चश्मे से देखते वक्त बहुत ज्यादा तुलना से कैसे बचे?
जब आप दो चीजों को देखते हैं, आप तुलना करेंगे और फर्क दिखाएंगे. लेकिन मैं नहीं सोचता कि तुलना जरूरी तौर पर ऊंच-नीच पैदा करती है. मैं कभी नहीं कहता कि एक दूसरे से बेहतर है. मुझे लगता है कभी-कभी लोगों के दिमाग तंग होते हैं. मेरा मकसद दिमाग का विस्तार करना है, ताकि उसमें एक से ज्यादा विचार समाने लगें.

● किताब को चित्रों से सजाना कितना कठिन था?
जब से मैंने इस्लामिक परंपरा की सेसैनियम पेंटिंग, ओटोमन भित्तिचित्र और इथियोपिया के बाइबिल के ये चित्रांकन देखे थे, बाइबिल की कहानियों को भारतीय पुट देते हुए चित्रित करना मेरा सपना था. मैं हमेशा खुद से पूछता—अगर किसी भारतीय ने उसका चित्र बनाया होता तो टॉवर ऑफ बाबेल कैसा दिखता?

● कोविड की दुनिया में मिथ और लोककथाएं क्या भूमिका निभाती हैं?
ईडन को लीजिए, यह नोआ की कहानी है. चारों तरफ सैलाब है और वह उसके बीचोबीच इस नाव पर है और उम्मीद कर रहा है कि नौका पर सवार सारे जानवर बच जाएं. इसी तरह घरों में बंद हम इनसान भी, जो कोविड के पीछे हटने का इंतजार कर रहे हैं, नोआ हैं. मानवीय रूपक में जोड़ने की ताकत है.

● प्राचीन मिथ क्या स्वाभाविक रूप से 21वीं सदी के लिए प्रासंगिक हैं या यह मिथकशास्त्रियों का काम है कि वे उन्हें संदर्भ सहित सामने रखें?
सभी कहानियां कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं. मिथकीय कहानियां खास तौर पर ताकतवर होती हैं क्योंकि वे हमेशा उन शब्दों में बात करती हैं जिनमें सेक्युलर नैरेटिव बात नहीं करता—संसार की उत्पत्ति, संसार का अंत, जीवन का उद्देश्य. बिग बैंग की कहानी आपको जोश से नहीं भरती. यह इतना कहती है कि तुम कण हो. वैज्ञानिक ईर्ष्या, क्रोध और दुर्भाग्य सरीखी चीजें नहीं समझा सकते. कहानियां यह काम करती हैं.

—श्रीवत्स नवेतिया

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

9:41
INDIA TODAY
LIVE
TOP NEWS
VIDEOS
PROGRAMMES
TOP STORIES

LOK SABHA 2019

Narendra Modi Live: By Congress-mukt India we will fulfil Gandhi's dream

PM Narendra Modi was speaking in Lok Sabha

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

IndiaContent
SEARCH FOR
EDITORIAL IMAGES
ENDS HERE